चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है

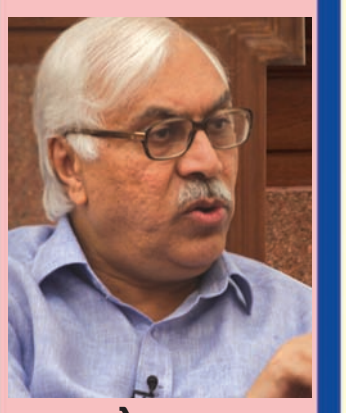

पेज- 3

नीतीश बिहारियों को सम्मान नहीं दिला सके

पेज- 4

ग्रामसभा की ताक़त साबित हुई

पेज- 7

सच्चाई नहीं, यह साज़िश है

पेज- 15

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 08 नवंबर-14 नवंबर 2010 | मूल्य 5 रुपये

माया कैसे तोड़ेंगी इतने मंदिर-मस्जिद!

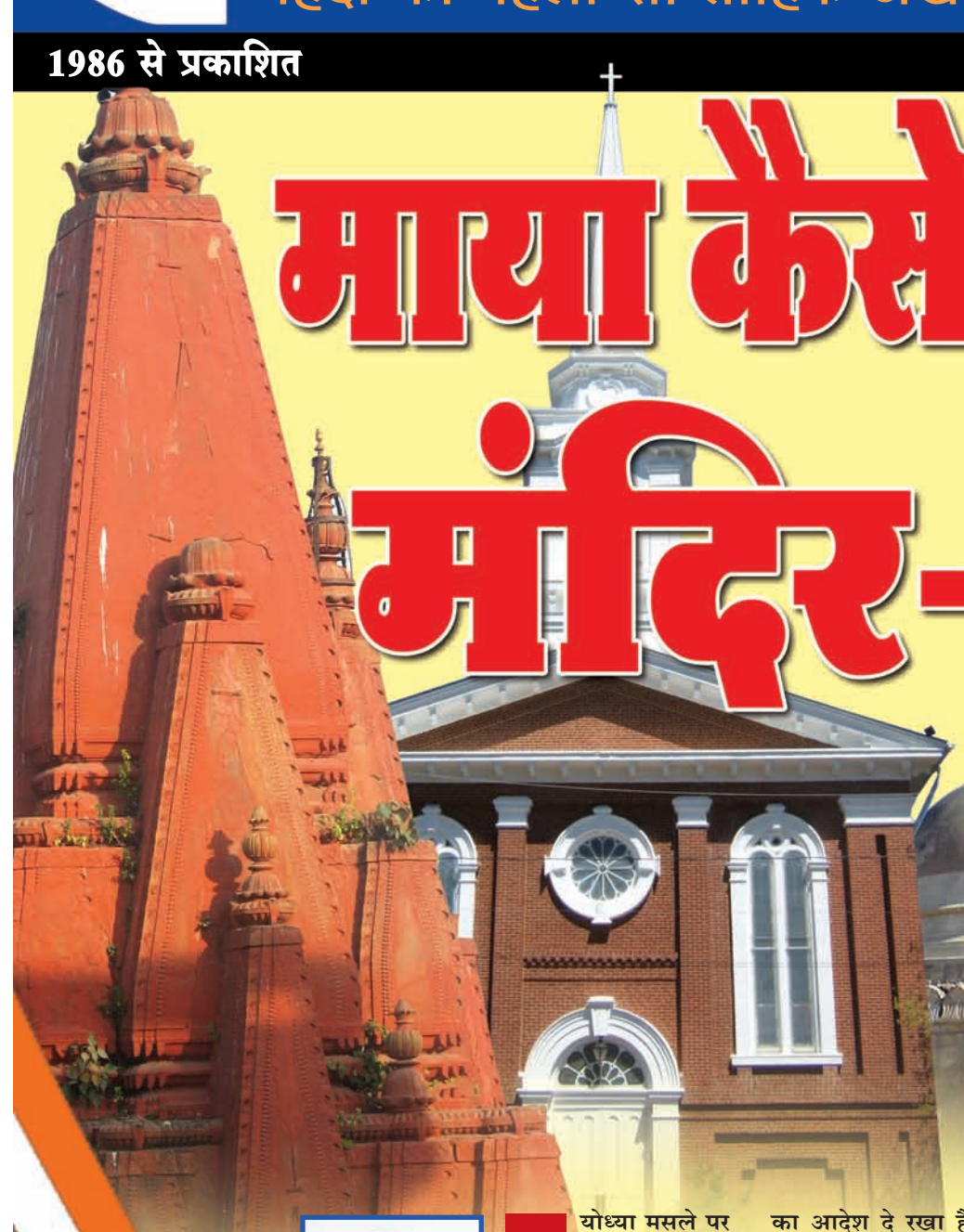

विजय यादव

अयोध्या मसले पर हाईकोर्ट का फ़ैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने फ़ैसले के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी केंद्र के माथे मढ़ दी. साथ ही धमकी दी कि अगर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बिगड़ती है तो केंद्र ज़िम्मेदार होगा. मायावती ने यह बात अयोध्या के संदर्भ में तो कह दी थी, लेकिन क्या वह सार्वजनिक स्थलों पर बने 45 हज़ार से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों के मामले में भी ऐसा कह सकेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने इन अवैध धार्मिक स्थलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आदेश दे रखा है. यह धार्मिक स्थल सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं. अब अगर इन्हें ध्वस्त किया जाता है तो जनाक्रोश का सामना राज्य सरकार को ही करना पड़ सकता है. वह भी उस स्थिति में, जब भाजपा इसी बहाने नेपाल से सटे ज़िलों में संप्रदाय विशेष के धर्मस्थलों का मुद्दा उठाने का मन बना चुकी है. ऐसा नहीं है कि अवैध धार्मिक स्थलों के इस बवंडर से अकेले उत्तर प्रदेश सरकार को ही जूझना पड़ रहा है. इस लिहाज़ से तमिलनाडु अव्वल है, जहां सबसे अधिक 77,450 अवैध धार्मिक स्थल हैं. राजस्थान में 58,253, मध्य प्रदेश में 51,647, छत्तीसगढ़ में 30,000 और गुजरात में 15,000 धार्मिक स्थल ऐसे हैं, जो सार्वजनिक स्थलों पर बने हैं. गुजरात में कट्टर हिंदूवादी छवि के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे दर्जनों धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कराकर एक मिसाल भी क़ायम की थी. अब सवाल यह उठता है कि क्या धर्मनिरपेक्ष छवि की मुख्यमंत्री मायावती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ऐसा जोखिम उठा सकेंगी?

अकेले राजधानी लखनऊ में ही ऐसे धार्मिक स्थलों की संख्या 971 है. सर्वाधिक 4706 अवैध धार्मिक स्थल सिद्धार्थनगर में हैं. ये धार्मिक स्थल सड़कों, गलियों के नुक्कड़ पर स्थित हैं, जहां लोग आते-जाते रोजाना मत्था टेकते हैं. धर्म की आड़ में सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण कर जब यहां निर्माण कराया जा रहा था, उस समय नगर निगम, विकास प्राधिकरण के अभियंता अपनी आंख मूंदे रहे. अब सुप्रीमकोर्ट का चाबुक चलने के बाद वह ऐसे स्थलों की सूची तैयार कर शासन को सौंप चुके हैं. सुप्रीमकोर्ट ने पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार को यह आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों यानी सड़कों, नुक्कड़ों एवं उद्यानों में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा अथवा अन्य किसी धार्मिक ढांचे के निर्माण की अनुमति न दी जाए. सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकारों को इस संबंध में एक विस्तृत नीति तैयार करने, सार्वजनिक स्थलों पर बने धार्मिक स्थलों की पहचान करने और उन्हें हटाने या स्थानांतरित करने के बारे में योजना बनाने का आदेश दिया था. इन धार्मिक स्थलों के ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई की गई, ऐसा कोई ब्योरा उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक सुप्रीमकोर्ट के समक्ष पेश नहीं कर सकी है. वजह साफ है, राज्य सरकार को डर सता रहा है कि अगर इन धार्मिक स्थलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई तो उसे जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा. सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश को एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं हो सका है.

इससे नाराज़ सुप्रीमकोर्ट ने पिछले माह सितंबर की 14 तारीख़ को राज्य सरकारों को दो सप्ताह का समय देते हुए कहा कि इस बार सीधे मुख्य सचिवों को तलब किया जाएगा. ज़ाहिर है कि सुप्रीमकोर्ट इस मसले पर हीलाहवाली बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है. इससे पूर्व सुप्रीमकोर्ट ने पिछली 27 जुलाई को एक आदेश जारी कर अवैध धार्मिक स्थलों की संख्या बताने और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का ब्योरा देने को कहा था. इसके आलोक में राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में शपथपत्र पेश कर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अकेले राजधानी लखनऊ में ही ऐसे धार्मिक स्थलों की संख्या 971 है. सर्वाधिक 4706 अवैध धार्मिक स्थल सिद्धार्थनगर में हैं. ये धार्मिक स्थल सड़कों, गलियों के नुक्कड़ पर स्थित हैं, जहां लोग आते-जाते रोजाना मत्था टेकते हैं. धर्म की आड़ में सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण कर जब यहां निर्माण कराया जा रहा था, उस समय नगर निगम, विकास प्राधिकरण के अभियंता अपनी आंख मूंदे रहे. अब सुप्रीमकोर्ट का चाबुक चलने के बाद वह ऐसे स्थलों की सूची तैयार कर शासन को सौंप चुके हैं.

अवैध धार्मिक स्थलों की ज़िलावार संख्या

सिद्धार्थनगर	4706	बाराबंकी	511
प्रतापगढ़	244	अंबेडकरनगर	867
बस्ती	456	छत्रपति शाहू जी महाराज नगर	199
बरेली	929	सुल्तानपुर	174
आगरा	536	गोरखपुर	405
फिरोजाबाद	111	देवरिया	448
मैनपुरी	133	महराजगंज	84
मथुरा	205	कुशीनगर	89
अलीगढ़	455	जालौन	135
एटा	426	झांसी	1101
हाथरस (महामाया नगर)	729	ललितपुर	835
आजमगढ़	747	इटावा	295
बलिया	425	फतेहगढ़ (फ़र्रुख़ाबाद)	227
मऊ	433	कानपुर नगर	1490
कांशीरामनगर	361	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	271
इलाहाबाद	381	कन्नौज	226
फतेहपुर	443	औरैया	162
कौशांबी	38	हरदोई	311
बदायूं	804	खीरी	160
पीलीभीत	287	लखनऊ	971
शाहजहांपुर	253	रायबरेली	521
चित्रकूट	159	उन्नाव	825
बांदा	202	सीतापुर	431
हमीरपुर	236	बागपत	155
महोबा	457	बुलंदशहर	701
बहराइच	620	गाजियाबाद	693
बलरामपुर	122	गौतमबुद्धनगर	349
संत कबीर नगर	214	मेरठ	1415
गोंडा	1008	बिजनौर	1198
श्रावस्ती	302		
फैजाबाद	1417		

पुलिस भगवान का कोई क्या बिगाड़ेगा

खाकी वर्दी में यह कलयुग के पुलिस भगवान हैं. जिनसे उम्मीद तो लोग न्याय की रखते हैं, लेकिन वह काफी भौतिक चढ़ावे के बाद भी नसीब नहीं हो पाता. सुप्रीमकोर्ट ने सड़क, नुक्कड़ एवं चौराहा घेरकर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर तो अपनी नज़र टेढ़ी कर ली, लेकिन इन पुलिस भगवान का क्या होगा, जो उत्तर प्रदेश की सड़कों एवं फुटपाथों पर चौकी खोलकर बैठ गए हैं. राजधानी लखनऊ में ही अमीनाबाद जैसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाक़े में महिला कॉलेज और विद्युत उपकेंद्र के बीच पुलिस ने सड़क खोदकर चौकी बना रखी है. आम आदमी यही काम करता तो उसे लाठी-डंडों से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया जाता, लेकिन यहां तो खाकी ख़ुद ही लिप्त थी. सो ज़िम्मेदार महकमों ने इस ओर से अपनी-अपनी आंखें मूंद ली. यह तो एक बानगी है, चारबाग हो या फिर इंदिरा नगर की भूतनाथ मार्केट अथवा मुंशी पुलिया के पास अरविंदो पार्क का इलाक़ा, जहां मर्जी आई, पुलिस ने वहीं सार्वजनिक स्थल पर चौकी खोल रखी है. सड़क घेरकर चौकी बनाने के अलावा पुलिस ने खाकी की दबंगई दिखाते हुए जगह-जगह फुटपाथ बूथ रखे हुए हैं, जहां केवल बैठकबाज़ी होती है. आम आदमी को इन बूथों पर कोई सहायता नसीब नहीं होती. यही हाल प्रदेश के अन्य शहरों का है. धार्मिक नगरी वाराणसी में संकरी सड़कों पर वाहनों के बढ़ते बोझ के बीच यातायात वैसे ही रेंग-रेंगकर आगे बढ़ता है, उस पर सड़क घेरकर बनाई गई चौकियां एवं बूथ लोगों की दिक्कतों में इज़ाफ़ा करते रहते हैं. कहने के लिए यह सब आम जनता की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि जिस किसी भी इलाक़े में पुलिस ने ऐसी चौकियां स्थापित की हैं, वहां विभाग की कमाई ज़रूर बढ़ गई है. आम आदमी को कितनी सुरक्षा मिली है, यह दर्शाने के लिए शहर में आएदिन होने वाली हत्या, लूट और अन्य घटनाएं ही काफी हैं.

फोटो- *प्रीति सोनकर*

नौकरशाही पर नजर रखने वाले लोगों के लिए पीएमओ के अधिकारियों का यह रवैया हैरान नहीं करता है. 2004 का यह मामला मौजूदा मनमोहन सिंह सरकार से सीधे संबंधित नहीं है,

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

राजनीति में उलझे नौकरशाह

राजनीति के मल्लयुद्ध में नौकरशाहों का पक्ष लेना अक्सर उनके लिए ही घातक साबित होता है. पंजाब के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया गया है. उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनकी पत्नी और बेटे सुखबीर बादल के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्होंने गवाहों को डराया–धमकाया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की. गौरतलब है कि बादल एवं उनके परिवारवालों को अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन ये दोनों पुलिस अधिकारी अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं. दोनों अधिकारियों, एसपी (निगरानी) सुरिंदर पाल सिंह और डीआईजी बी के उप्पल ने बादल परिवार के खिलाफ मुकदमे का विरोध किया था. आश्चर्य की बात तो यह है कि पंजाब में इस तरह का यह अकेला मामला नहीं है. राज्य में भ्रष्ट बाबुओं की तो जैसे शामत आ गई है. राज्य के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर मनदीप सिंह भी सीबीआई की जांच के दायरे में आ गए हैं. उन पर पंचायत सचिवों की नियुक्ति में घालमेल का आरोप है. इस घोटाले में राज्य विधानसभा के स्पीकर निर्मल सिंह कहलान और 13 अन्य नौकरशाहों के भी शामिल होने का संदेह है. कोई आश्चर्य नहीं कि राज्य सरकार ने जांच के लिए सीबीआई के अनुरोध को ठुकरा दिया था. जांच एजेंसी ने इसके बाद गृह मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया. हालांकि सीबीआई को घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ जांच की अनुमति मिल गई है, लेकिन इससे सियासी गलियारों में राजनीति का खेल बंद होने की कोई संभावना नजर नहीं आती.

पीएमओ और सूचना आयोग में भिड़ंत

सूचना अधिकार कानून के तहत दर्ज की गई अर्जियों के चलते प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) केंद्रीय मंत्रियों की संपत्तियों का खुलासा करने को मजबूर भले हो गया हो, लेकिन नौकरशाही 2004 के पद्म पुरस्कारों से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक करने के मामले में अभी भी रुकावट बनी हुई है. केंद्रीय सूचना आयुक्त ने इस साल अप्रैल में ही प्रधानमंत्री कार्यालय को उक्त जानकारियां उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन यह अब तक नहीं हो पाया है. पीएमओ के रवैये से नाराज नए केंद्रीय सूचना आयुक्त ए एन तिवारी ने अब इस बाबत मंत्रालय की उपसचिव संयुक्ता रे को पत्र लिखा है.

नौकरशाही पर नजर रखने वाले लोगों के लिए पीएमओ के अधिकारियों का यह रवैया हैरान नहीं करता है. 2004 का यह मामला मौजूदा मनमोहन सिंह सरकार से सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है कि पद्म पुरस्कारों की सूची के साथ अक्सर छेड़छाड़ होती है और पीएमओ के अधिकारी अपनी मर्जी से नामों की कांट–छांट करते हैं, जिससे विवाद पैदा होते हैं. पीएमओ के मौजूदा आला अधिकारी भी अपने इस विशेषाधिकार को खोना नहीं चाहते और इसीलिए संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने से लगातार बचने की कोशिश करते रहे हैं. लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि पीएमओ केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश की कब तक अनदेखी करता रहेगा? सवाल यह भी है कि क्या तिवारी पीएमओ से अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे? आखिर हाल ही में केंद्रीय सूचना आयुक्त का पद संभालने वाले तिवारी के लिए यह पहली बड़ी चुनौती हो सकती है.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

1991 बैच के लिए बुरी खबर

1991 बैच के आईएएस अधिकारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उन्हें भारत सरकार की सूची में शामिल करने के लिए होने वाली बैठक की तारीख अभी तक तय नहीं की जा सकी है.

सेठ बनेंगे सचिव?

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नया सचिव कौन बनेगा? इस बात को लेकर चर्चा गर्म है. वर्तमान सचिव शांतनु कोंसुल की विदाई 31 अक्टूबर तक होने वाली है. शांतनु को शुंगलु कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जो राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार की जांच करेगी. शांतनु की जगह कौन? इसके लिए कई नामों पर विचार चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अजीत कुमार सेठ का नाम चर्चा में है. सेठ अभी कैबिनेट सचिवालय में सचिव स्तर पर तैनात हैं. सेठ 1974 बैच और उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

आईडीएएस–आईआईएस बनेंगे जेएस

चार अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. 1988 बैच के दो आईडीएएस अधिकारियों दिविका रघुवंशी एवं अलका शर्मा और 1985 बैच के दो आईआईएस अधिकारियों ओंकारमल केडिया एवं मनोज कुमार पांडेय के नाम संयुक्त सचिव के लिए बनाई गई सूची में शामिल कर लिए गए हैं.

बिस्वास बनेंगे निदेशक

प्रांशु बिस्वास के बारे में यह कयास लगाया जा रहा है कि वह जल्द ही डीआईपीपी में निदेशक बनाए जा सकते हैं. 1990 बैच के बिस्वास आईओएफएस अधिकारी हैं.

माया कैसे तोड़ेंगी इतने मंदिर-मस्जिद !

पृष्ठ 1 का शेष

सभी अवैध धार्मिक स्थलों का ब्योरा दे दिया है. इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बनाई गई नीति से सुप्रीमकोर्ट को अवगत कराया गया है. इस नीति के तहत ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता वाली ज़िलास्तरीय समिति प्रत्येक मामले का पुनरावलोकन करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट भेजेगी. अपने बचाव में राज्य सरकार ने यह तर्क दिया है कि धार्मिक स्थलों की संख्या अधिक होने की वजह से अभी किसी ज़िलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है. राज्य सरकार के पास इस आशय का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने धार्मिक स्थलों को हटाया गया, उन्हें किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया या फिर कितने धर्मस्थलों को नियमित करने की प्रक्रिया अपनाई गई. शासन के प्रमुख सचिव आलोक रंजन के मुताबिक़, इस पूरे मामले में प्रमुख सचिव गृह फतेह बहादुर सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है. क़ानूनी मसले वही देख रहे हैं. उनके विभाग से जो जानकारियां मांगी गई थीं, वे मुहैया करा दी गई है. शासन के आला अधिकारी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर इन धार्मिक स्थलों

अयोध्या प्रकरण पर हाईकोर्ट का फ़ैसला आने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सक्रियता बढ़ी है, उसे देखते हुए इन धार्मिक स्थलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बसपा सरकार के लिए मुश्किल होगा. शासन के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक़, राजनीतिक दलों के नेता भले ही इस मसले पर खुलकर सामने न आएं, लेकिन वे अपने समर्थक धार्मिक संगठनों के ज़रिए क़ानून व्यवस्था के लिए दिक़्क़तें पैदा कर सकते हैं. इससे निबटने का रास्ता तलाशा जा रहा है. इसके बाद ही इन धार्मिक स्थलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकेगी.

feedback@chauthiduniya.com

आम आदमी हुआ सजग

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जनता में जागरूकता उत्पन्न हुई है और वह सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थल बनाए जाने के विरोध में खड़ी होने लगी है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसी ही एक पहल हुई, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग भी मिला. यहां पिकनिक स्पॉट के पास फरीदी नगर मयूर विहार सी ब्लॉक में सार्वजनिक पार्क नंबर एक है. इस पार्क की ज़मीन पर मयूर विहार सी ब्लॉक वेलफेयर सोसायटी ने मंदिर निर्माण का निर्णय लिया. मज़ेदार बात यह है कि जिस दिन सोसायटी की नई इकाई का गठन किया गया, उसी दिन मंदिर बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया. आमतौर पर किसी भी नई इकाई के गठन के पहले दिन ऐसे किसी भी प्रस्ताव से बचा जाता है. मंदिर बनाने का एजेंडा पारित होने के बाद नई इकाई के पदाधिकारी पार्क की ज़मीन पर इसके लिए बैठकबाज़ी करने लगे. इसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने अपने स्तर से पहल करके विरोध किया. मौखिक रूप से जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो कालोनी की महिलाओं ने समिति के पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा. इसमें सुप्रीमकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी धार्मिक स्थल बनाना क़ानूनन ग़लत है. यह ज़मीन पार्क के लिए है, जहां कालोनी के बच्चे खेलते-कूदते हैं और सार्वजनिक जीवन की अन्य तमाम गतिविधियों का केंद्र भी पार्क की ज़मीन है. अगर इस पर मंदिर का निर्माण कराया जाएगा तो कालोनी में रहने वालों को परेशानी होगी और यह सुप्रीमकोर्ट की अवमानना भी होगी.

इस पत्र की प्रतिलिपि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव, नगर निगम के नगर आयुक्त, लखनऊ के डीआईजी, एसएसपी समेत अन्य ज़िम्मेदार अधिकारियों को भी भेजी गई. पत्र भेजने वाली महिलाओं में प्रतिमा प्रसाद पत्नी मुनीब प्रसाद, विद्यावती पत्नी वियोधन, मीरा देवी पत्नी राजेंद्र यादव, रीना यादव पत्नी बीएन यादव एवं अन्य शामिल हैं.

पत्र का असर यह हुआ कि समिति के पदाधिकारियों ने मंदिर निर्माण की योजना फ़िलहाल स्थगित कर दी है. इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने मौक़े पर जाकर वस्तुस्थिति का जायज़ा लिया. एलडीए अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों एवं महिलाओं को आश्वस्त किया कि ऐसे किसी भी निर्माण को शुरू नहीं होने दिया जाएगा. स्थानीय खुर्रम नगर पुलिस चौकी प्रभारी ने भी वहां के लोगों को भरोसा दिलाया और कहा कि अगर ऐसा होता है तो वे तत्काल पुलिस को सूचित करें. सुप्रीमकोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक स्थल बनाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मयूर विहार की महिलाओं की यह पहल उन स्थानों के लिए अनुकरणीय है, जहां पार्कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक स्थल बनाने का कुचक्र रचा जा रहा है.

के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो विरोधी राजनीतिक दल उसका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, भले ही विध्वंस की कार्रवाई सुप्रीमकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जाए.

इन अधिकारियों की चिंता ग़लत नहीं है. भाजपा के विधान परिषद सदस्य एवं प्रदेश प्रवक्ता हृदय नारायण दीक्षित कहते हैं कि सुप्रीमकोर्ट में सरकार को अपना पक्ष अच्छी तरह से रखना चाहिए. अदालत को ठीक स्थिति बतानी चाहिए. उनके मुताबिक़, सड़क पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल का निर्माण करना ग़लत है. उससे भी अधिक संवेदनशील मुद्दा नेपाल की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के इलाक़ों में हाल के वर्षों में अनगिनत धर्मस्थलों का बनना है. उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए. भाजपा इस मुद्दे को उठाएगी. वहीं सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इस मामले में हालात सामने आने पर ही कोई निर्णय लेने की बात कही. उत्तर प्रदेश में दो साल बाद विधानसभा चुनाव होना है. इस लिहाज़ से बसपा सरकार जानबूझ कर इस आग में अपने हाथ नहीं जलाना चाहती है. वैसे भी

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार
वर्ष 2 अंक 35
दिल्ली, 08 नवंबर–14 नवंबर 2010
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है

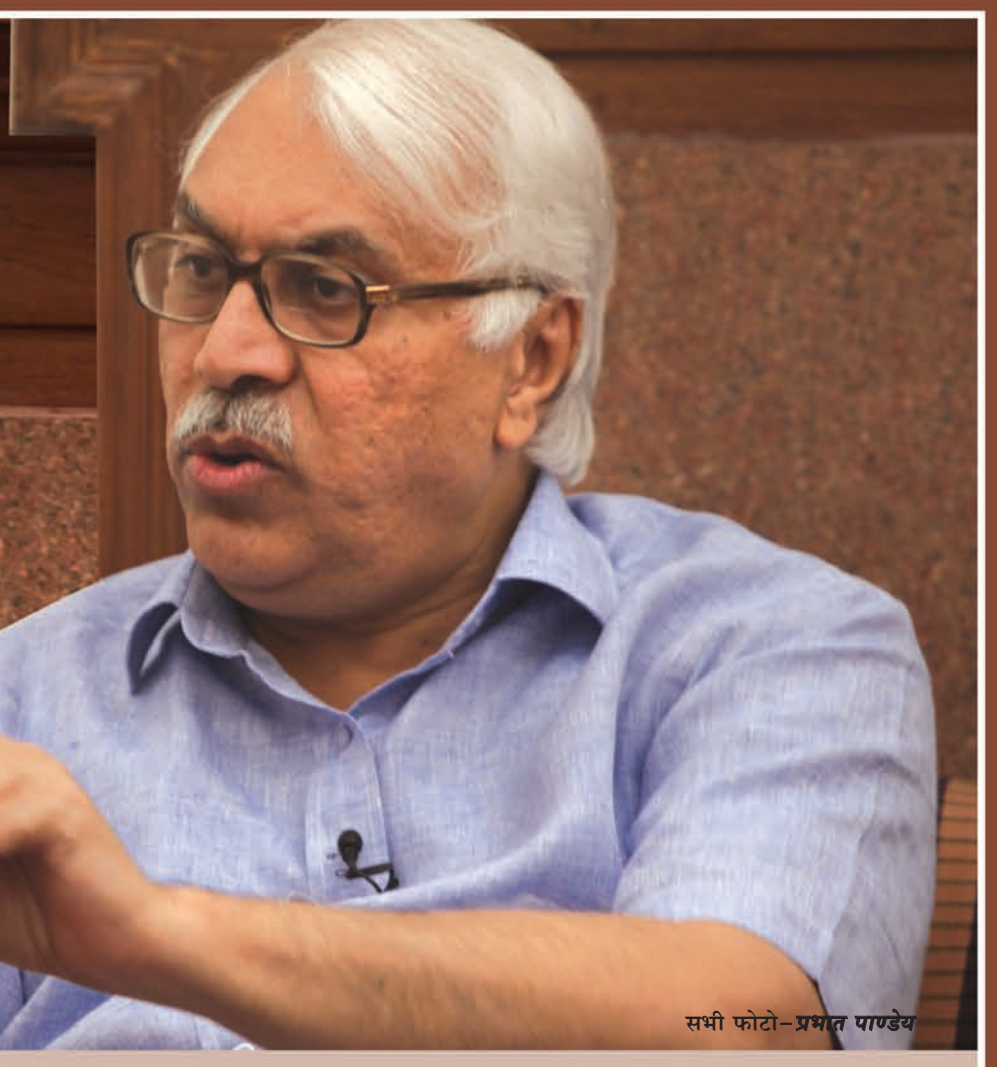

बिहार विधानसभा चुनाव के चार चरण संपन्न हो चुके हैं. अभी दो चरणों का मतदान शेष है. विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, रात के अंधेरे में लोगों को पैसा देने की भी बात सामने आई है, कई उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि आपराधिक है, सभा के दौरान अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल जैसे अहम बिंदुओं पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई क़ुरैशी से चौथी दुनिया (उर्दू) की संपादक *वसीम राशिद* ने एक लंबी बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बिहार विधानसभा चुनाव में एक नेता दूसरे नेता को गंगा में बहा देने की बात कर रहा है तो कोई मंच पर खड़ा होकर किसी को पीटने की बातें करता है. चुनावी रैलियों में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, वह वरुण गांधी के भाषण की याद ताज़ा करता है. चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक क्या कर रहे हैं? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते?

चुनाव में ऐसी घटनाएं तो होती हैं. एक–दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी हो जाए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंपैरिमेंट के लिए हर क्षेत्र में हमारी 5–10 टीमें होती हैं, जो घूमती रहती हैं, हर वीआईपी और नेता के भाषण को रिकॉर्ड करती हैं. एक–दो घटनाएं पिछले दिनों सामने आई हैं. हम लोग राय ले रहे हैं. हमारे पास गंगा में फेंकने वाली शिक़ायत भी आई है. यह चीज़ें उचित नहीं हैं. पर्यवेक्षक अलर्ट रहते हैं, उस घटना की रिकार्डिंग भी आ गई है. हमारी लीगल टीम ने उसे देखा है, हम भी देखेंगे. सभी नेताओं से हमारी यही अपील होती है कि वे मॉडल कोड पर सख्ती से अमल करें. पूर्व के चुनावों के मुक़ाबले इस बार बिहार में काफ़ी नियम–क़ानून हैं. इस बार शिक़ायतें भी बहुत कम आई हैं. ऐसी छोटी–मोटी घटनाएं सामने न आतीं तो और अच्छा रिकार्ड क़ायम होता. हम नेताओं को नोटिस देते हैं कि आपने ऐसा कहा, आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने क्या कहा और क्यों कहा. अगर हम उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं तो पुन: स्पष्टीकरण देने को कहते हैं. नेताओं को चुनाव आयोग से नोटिस जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनकी जनता में साख है, उसे चोट लगती है और जनमत संग्रह की नौबत आ जाए तो वह उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं होती, जिसे वह नज़रअंदाज़ करना चाहते हैं. हम जो एक्शन लेते हैं, वह तो लेंगे ही, साथ ही अपील करना चाहेंगे कि ऐसे अवसर न आएं, क्योंकि चुनाव साफ़–सुथरे होने चाहिए.

लगभग 44 प्रतिशत प्रत्याशियों पर आपराधिक मुक़दमे चल रहे हैं. आयोग प्रत्याशियों से शपथपत्र तो जमा कराता है, लेकिन ऐसे लोग को चुनाव लड़ने से रोक नहीं पाता. क्या मान लिया जाए कि चुनाव आयोग एक बिना दांतों वाली बेज़हर संस्था है?

दरअसल लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए भी वे चुनाव आयोग को दोषी मानते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं. चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है और कौन नहीं, यह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित मामला है. इसके लिए क़ानून बनाया जाता है, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता. उस वक़्त के क़ानून के मुताबिक़ जब तक आरोप अदालत में साबित न हो जाएं, तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है, इसलिए हम उन्हें अयोग्य घोषित नहीं कर सकते. हालांकि विधि आयोग ने अनुशंसा की थी. अक्सर होता यह है कि विरोधी पार्टी झूठे आरोप लगाकर फ़र्ज़ी मुकदमा कर देती है. आप अच्छे प्रत्याशी हैं, आपको हराना मुश्किल है तो एक झूठा मुकदमा चुनाव से कुछ दिनों पहले कर दो कि उनके ख़िलाफ़ तो मुकदमा है. वैसे अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि वाला प्रत्याशी होता है तो हम उसके पीछे एक गाड़ी लगाते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट होता है, वीडियो टीम होती है, वह बराबर उसकी निगरानी करती है, पूरी रिकार्डिंग होती रहती है. वह प्रत्याशी पीछे मुड़कर देखता और डरता है कि हर चीज़ रिकार्ड हो रही है. हमने संसद को लिखा, सरकार को लिखा, लेकिन वे कोई कानून ही नहीं बनाते. हमने पिछले दिनों सभी राष्ट्रीय पार्टियों को बुलाया. सात राष्ट्रीय और 35 क्षेत्रीय पार्टियां आईं. सबने कहा कि आपका यह रिफ़ॉर्म हमें स्वीकार नहीं है.

कई प्रत्याशी नामांकन के वक़्त सैकड़ों गाड़ियों के साथ ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. एक–एक उम्मीदवार करोड़ों रुपये ख़र्च कर रहा है. खुलेआम रुपये बांटे जा रहे हैं. क्या पैसे वालों के खिलाफ कार्यवाही करने में चुनाव आयोग को डर लगता है?

हम ऐसी कोई बात टीवी या अख़बार में देखते हैं तो किसी शिक़ायत का भी इंतज़ार नहीं करते, तुरंत कार्यवाही करते हैं. इस बार चुनाव में बहुत सख्ती हो रही है. एक बड़े नेता का बयान है कि वह हेलीकॉप्टर में बैठ गए, अधिकारियों ने उनका बैग चेक नहीं किया तो उन्होंने ख़ुद कहा कि हमारा बैग चेक कर लीजिए, चुनाव का मामला है. जब कोई नामांकन के लिए आता है तो उस समय वह प्रत्याशी नहीं होता. हमारा क़ानून उस वक़्त लागू होता है, जब यह प्रत्याशी हो जाता है. मनी पॉवर हमारे लिए एक बड़ी समस्या है. बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में. किसी राज्य में कम, किसी में अधिक. इसके ख़िलाफ़ हमने मुहिम शुरू की है. बिहार में हम अपने मेजर को टेस्ट कर रहे हैं, ताकि दूसरी जगहों पर अधिक सख्ती कर सकें. जो चीज़ें देखने में आती हैं, उन्हीं पर अमल किया जाता है. हमारी टीमें घूमती हैं. हम जगह–जगह रेड करते हैं, लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम ब्लैक मनी पर कंट्रोल कर लें. हमारी अपनी टीम है, लेकिन हम मीडिया पर भी निर्भर हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा मीडिया की टीमें घूमती रहती हैं. पूरे भारत में लगभग 4500 आईएएस अधिकारी हैं, उनमें से 10–15 प्रतिशत अधिकारी बिहार में लगे हुए हैं, 150–200 पर्यवेक्षक लगे हुए हैं. हम शराब के लिए भी तीन माह पूर्व से कार्यवाही करते हैं. कहां–कहां शराब बनती है और कहां–कहां से आती है, इसकी लिस्ट तैयार करते हैं. बिहार में दूसरे राज्यों से भी शराब आती है. रास्ते में हम नाकाबंदी करते हैं. बावजूद इसके काफ़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई. हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बटन दबाते ही सारे लोग साधु हो जाएं. हम तीन–चार बार बिहार गए, क्योंकि हम एक साल पूर्व से ही चुनाव पर नज़र रखते हैं. सबसे पहले वोटिंग कार्ड पर ध्यान देते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा अधिकारी कैसा है, उनमें कोई ग़द्दार तो नहीं है. आवश्यकता के अनुसार अधिकारियों का तबादला भी करते हैं, ताकि कोई गड़बड़ न हो. हमने देखा कि वहां का माहौल अच्छा है, अधिकारी अच्छे हैं, हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है. यही कारण है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है. हमने बूथ लेवल पर रणनीति बनाई, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की सूची तैयार की और कई लोगों की गिरफ़्तारियां भी हुईं. चुनाव बहुत पारदर्शी हो रहे हैं.

हर राजनीतिक पार्टी मानती है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग इतना प्रतिक्रियावादी क्यों है? जब इस पर कोई सवाल उठाता है तो उसे मौक़ा देने के बजाय गिरफ़्तार कर लिया जाता है. अगर ईवीएम सही हैं तो उनके संबंध में आप लोगों को खुलेआम चैलेंज क्यों नहीं करते, ताकि लोगों को पूरा भरोसा हो जाए?

सभी पार्टियां हमारे पास आई थीं. सबने कहा कि इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम कर रही है. उन्होंने एक बात कही कि जब हम बटन दबाते हैं तो वोट स्टोर हो जाता है, लेकिन यह पता नहीं कि वह कहां स्टोर हो रहा है. यह यक़ीन की बात है. इसका हमारे पास सबूत नहीं होता. अगर इसका सबूत हो जाए और इसकी रसीद मिल जाए तो इससे हमें संतुष्टि होगी. हम यह नहीं मानते कि छेड़छाड़ होती है. ईवीएम पर हमें पूरा भरोसा है.

पचास साल पूर्व आयोग के पास जितनी सुविधाएं थीं और अब जिस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, उनमें ज़मीन–आसमान का फ़र्क़ है. ऐसे में बिहार में 6 चरणों में चुनाव कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

आयोग बहुत ख़ुश होगा, अगर पूरा चुनाव एक ही चरण में हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत आयोग को ही करनी पड़ती है. हमारी कोशिश यह होती है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों. अगर गुंडागर्दी और बूथ कैप्चरिंग की कोशिश होगी तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे. जब–जब हम बिहार गए, वहां हमने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की. सभी पार्टियों ने कहा कि सीआरपीएफ़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय पुलिस पर दबाव रहता है. 6 चरणों में चुनाव कराने का मक़सद सिर्फ़ और सिर्फ़ निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है.

एक आरोप यह है कि आयोग ने इतने सारे क़ानून लागू कर दिए हैं कि देश में चुनाव महज़ एक तकनीकी काम रह गया है. आयोग ने ऐसा कोई क़दम नहीं उठाया, जिससे लोगों की हिस्सेदारी बढ़े. क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है?

इस बार चुनाव में पहले के मुक़ाबले वोटिंग में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जो लोगों के उत्साह को उजागर करती है. शोरशराबे और ढोल–तमाशे पर हमने पूरा कंट्रोल किया है. रात के 10–11 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि परीक्षार्थियों और बीमार– बूढ़े लोगों को दिक़्क़तें होती थीं. हम पहले केवल तीन गाड़ियां चलाने की अनुमति देते थे, लेकिन इस बार हमने 10 गाड़ियों की अनुमति दी. हम पाबंदियां सिर्फ़ इसलिए लगाते हैं कि ख़र्चों पर क़ाबू पाया जा सके और चुनाव शांतिपूर्ण तरीक़े से हों.

आप देश के पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इतना बड़ा पद प्राप्त करके कैसा महसूस कर रहे हैं?

भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है. यहां सभी धर्म बराबर हैं. इस तरह की बातें करना कि पहले मुसलमान, पहले सिख या ईसाई, अच्छा नहीं लगता. जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, उसमें हर तरह के पद होते हैं. उन्हीं में से एक पद यह भी है और मुझे इस पर गर्व है. यह काम बहुत अहम है, क्योंकि पूरा देश इस पर भरोसा रखता है. इस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इसी संस्था पर टिका हुआ है. इस संस्था की जितनी ज़िम्मेदारी है, उस पर हमें गर्व है और उसका पूरा एहसास भी. हमारी कोशिश यही है कि हम संस्था की शान में इज़ाफ़ा करें. हमारी यही दुआ है कि लोकतंत्र की इस संस्था की छवि और प्रतिष्ठा हमेशा बुलंद रहे.

editorurdu@chauthiduniya.com

त्यौहारों की सौगात

8.25% प्रति वर्ष

गृह ऋण अब घटी हुई ब्याज दरों पर

लें त्यौहारों का आनंद अब देना बैंक के साथ. अपने सपनों का घर अब प्राप्त कर सकते हैं. आप देना बैंक की आकर्षक ब्याज दरों पर अपने घर के सपनों को जल्दी साकार करें. इसके साथ आपको मिलता है ग्राहक संतुष्टि एवं आसान प्रक्रिया का भरोसा. हमारे साथ अब आपके सपनों का घर केवल सपना ही नहीं रहेगा.

ऑफ़र 31 दिसंबर 2010 तक.

अवधि	ब्याज दर
प्रथम वर्ष	8.25% (फिक्स्ड)
द्वितीय वर्ष	8.50% (फिक्स्ड)
तृतीय वर्ष	8.75% (फिक्स्ड)
चौथे वर्ष से	₹ 15 लाख तक : बेस दर + 1.25% + टर्म प्रीमियम ₹ 15 लाख से अधिक बेस दर + 1.50% + टर्म प्रीमियम

*शर्तें लागू.

देना है तो भरोसा है

देना बैंक DENA BANK
(भारत सरकार का उद्यम)
विश्वस्त पारिवारिक बैंक
www.denabank.com

नीतीश बिहारियों को सम्मान नहीं दिला सके : कल्बे रूशैद रिज़वी

लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मशहूर इस्लामिक स्कॉलर एवं धर्मगुरु मौलाना कल्बे रूशैद रिजवी स्पष्ट, बेझिझक और तथ्यपरक टिप्पणियों-विचारों के लिए जाने जाते हैं. जब वह बिहार विधानसभा के वर्तमान चुनाव के पूर्व विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके वापस पटना लौटे तो *चौथी दुनिया* ने उनसे राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन की कामयाबी-नाकामयाबी जैसे अनेक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

फोटो-प्रभात पाण्डेय

विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा, क्या इस बार भी मतदाता सत्ता स्थानांतरण के पक्ष में मतदान करेंगे?

निस्संदेह बिहार के लोग इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान करेंगे. नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार को जिस तरह से बढ़ावा मिला है और बेलगाम अफसरशाही ने जनसंवेदनाओं को जिस प्रकार रौंदा है, उससे अवाम में बड़ी नाराज़गी और आक्रोश है. मैं स्वयं बिहारी हूं, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करता रहता हूं, सभी समुदायों एवं जातियों के लोगों से मिलता और बातें करता रहता हूं. वर्तमान चुनाव के अवसर पर भी मैंने कई क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान मैंने जो चीज शिद्दत के साथ महसूस की है, वह यह है कि लोग नीतीश कुमार की दोहरी नीतियों, जनविरोधी फ़ैसलों एवं नीचे से ऊपर तक फैले भ्रष्टाचार से बेहद खफा हैं और इस सरकार से मुक्त होना चाहते हैं.

क्या नीतीश सरकार में राज्य का विकास नहीं हुआ है और क्या मतदाता विकास के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे?

इस बात में कोई शंका नहीं है कि बिहार ने तरक़्क़ी की है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह विकास सामान्य ढंग से होने वाला विकास है या वर्तमान नीतीश कुमार सरकार कोई जादू की छड़ी घुमाकर या अपने बलबूते पर राज्य को विकास के रास्ते पर लाई है. राज्य में जो भी काम हुए हैं, वे केंद्र सरकार की देन हैं. राज्य सरकार ने केंद्रीय राशि का पूरा और सही ढंग से उपयोग किया होता तो आज विकास की सूरत कुछ दूसरी नज़र आती. विकास के कामों के लिए राज्य को जो धनराशि मिली, उसका सिर्फ 68 प्रतिशत हिस्सा ही उपयोग में लाया जा सका है. ऐसे में यह सरकार अगली योजना में कितनी धनराशि दिला सकेगी, यह एक बड़ा सवाल है. इसलिए इस सरकार को विकास के लिए पुरस्कृत करने के बजाय प्राप्त धनराशि का सदुपयोग न करने और राज्य को वास्तविक विकास से काफी दूर रखने की सजा दी जानी चाहिए. राज्य के समझदार मतदाता निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे. जनता एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार चाहती है और विगत 5 वर्षों के दौरान नीतीश सरकार की जो कार्यशैली रही है, क्या उससे ऐसी उम्मीद की जा सकती है? राज्य का युवा वर्ग तो वर्तमान सरकार से कुछ ज़्यादा ही मायूस है. बिहार की बागडोर संभालने के बाद नीतीश कुमार ने यह वादा किया था कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह राज्य में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे. उन्हें शिक्षा और रोज़गार के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने यह भी दावा किया था कि राज्य के युवा वर्ग को अब दूसरे राज्यों के अपमान और नफरत का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर नीतीश सरकार में हुआ इसके ठीक विपरीत. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के नौजवानों को मुंबई और दूसरे शहरों में सबसे अधिक अत्याचार सहना पड़ा. मुख्यमंत्री के रूप में मात्र राजनीतिक बयानबाजी करके नीतीश चुप हो गए. उन्होंने बिहार और बिहारियों के सम्मान की बात तो जरूर की, मगर वह सम्मान दिलाने में पूरी तरह से असफल रहे. नतीजा यह है कि आज भी राज्य के बच्चे शिक्षा एवं रोजी-रोटी के लिए घर और राज्य छोड़ने पर मजबूर हैं.

विगत विधानसभा चुनाव में राज्य के मुसलमानों का मामूली झुकाव हुआ था तो नीतीश कुमार सत्तासीन हो गए थे. इस बार मुसलमानों का रुख़ क्या रहेगा?

नीतीश की पार्टी और उनका गठबंधन एनडीए, दोनों ही मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं. वे समझते हैं कि टोपी पहन कर मुसलमानों को टोपी पहनाई जा सकती है. आप ख़ुद सोचें कि नीतीश कुमार की हुकूमत ने 5 वर्षों के दौरान मुसलमानों के हक में क्या किया है. उन्होंने न तो मुसलमानों को सत्ता में सम्मानजनक और उचित भागीदारी दी और न पार्टी ने उन्हें इज़्ज़त दी. जो लोग उनकी पार्टी या सरकार में थोड़ी-बहुत जगह बनाने में सफल भी हुए, उन्हें अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, जिनकी वजह से उन्हें ख़ुद ही पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा. नरेंद्र मोदी का मुद्दा बार-बार उठाकर मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने और सेक्युलर पहचान बनाए रखने की कोशिश की गई, मगर मुसलमानों और कल्याणकारी योजनाओं को नज़रअंदाज किया गया. नीतीश कुमार ने अपनी ही सरकार के 10 सूत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम पर अमल नहीं किया. मुसलमानों से संबंधित केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति वह उदासीन रहे. राज्य की दूसरी राजभाषा उर्दू को न केवल उन्होंने नुक़सान पहुंचाया, बल्कि माध्यमिक परीक्षा में इसकी अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया. उर्दू निदेशालय निष्क्रिय हो गया.

अशरफ अस्थानवी
feedback@chauthiduniya.com

नालंदा : जातीय समीकरण हावी रहेगा

आफरीन सुल्ताना

सतीश कुमार

हैदर आलम

जितेंद्र कुमार

भगवान महावीर और बुद्ध की नगरी नालंदा में मतदाताओं को रिझाने में प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं. ज़िले में नए परिसीमन के बाद आठ विधानसभा क्षेत्रों में से चंडी विधानसभा क्षेत्र विलोपित होने से अब केवल सात विधानसभा क्षेत्र रह गए हैं. यह क्षेत्र नीतीश कुमार का गृह ज़िला है, इसलिए लोगों का इस पर विशेष ध्यान है. इस क्षेत्र से कुल 97 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. हिलसा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक राम चरित्र प्रसाद सिंह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जदयू ने उषा सिन्हा, लोजपा ने रीना यादव और कांग्रेस ने अरुण कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. नए परिसीमन में कई नए क्षेत्र जुड़े हैं तो कई क्षेत्रों को हटा दिया गया है. राजद-लोजपा गठबंधन इस क्षेत्र में मज़बूत स्थिति में है. उसके आधार मतों के साथ यदि भूमिहार मत भी जोड़ दिए जाएं तो नीतीश के गढ़ में सेंधमारी की जा सकती है.

इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र अपनी भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए चर्चित रहा है. यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है. इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर यदि नज़र डाली जाए तो यहां 1977 से अब तक 9 बार विधानसभा चुनाव हुए. शुरुआती दौर में यहां भाकपा और कांग्रेस का वर्चस्व देखा गया, लेकिन वर्ष 2000 से यहां की राजनीतिक तस्वीर बदल गई. इस क्षेत्र से वर्तमान जदयू विधायक प्रतिमा सिन्हा का टिकट भी आलाकामान ने काट दिया और उनकी जगह झारखंड बिजली बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है. राजीव रंजन को टिकट दिए जाने के बाद भीतर ही भीतर असंतोष का स्वर बुलंद हो रहा है. एक तो वर्तमान विधायक प्रतिमा सिन्हा को टिकट से वंचित किया गया, वहीं इस क्षेत्र से शैलेंद्र कुमार मुखिया, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं चंद्रसेन जैसे लोगों को टिकट न देना जदयू को महंगा पड़ सकता है. पिछले लोकसभा चुनाव में राजीव रंजन ने जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार का खुलकर विरोध किया था. इस क्षेत्र से कांग्रेस ने विवेक यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राकेश रोशन एवं राजद ने वीरेंद्र गोप को अपना प्रत्याशी बनाया है. ऐसी स्थिति में यहां मुक़ाबला दिलचस्प और बहुकोणीय होने की संभावना है.

हरनौत विधानसभा क्षेत्र से जदयू के वर्तमान विधायक इंजीनियर सुनील कुमार को भी इस बार टिकट से वंचित रखा गया. चंडी विधानसभा क्षेत्र समाप्त होने के बाद वहां के विधायक हरि नारायण सिंह खाली थे, इसलिए जदयू ने सुनील की जगह हरि नारायण सिंह को टिकट दे दिया. कांग्रेस ने चंडी प्रखंड की पूर्व प्रमुख वसुंधरा देवी और लोजपा ने अरुण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है.

मृणाल पासवान

डॉ. सुनील

इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र अपनी भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए चर्चित रहा है. यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है. इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर यदि नज़र डाली जाए तो यहां 1977 से अब तक 9 बार विधानसभा चुनाव हुए. शुरुआती दौर में यहां भाकपा और कांग्रेस का वर्चस्व देखा गया, लेकिन वर्ष 2000 से यहां की राजनीतिक तस्वीर बदल गई.

बिहारशरीफ विधान सभा क्षेत्र से डॉ. सुनील कुमार जदयू के प्रत्याशी हैं तो वहीं राजद लोजपा ने आफरीन सुल्ताना उतारा है. कांग्रेस से हैदर आलम प्रत्याशी बनाए गए हैं. इस क्षेत्र का वृहत आकार एवं मुस्लिम बहुल्य मतदाता होने से जदयू प्रत्याशी डा. सुनील कुमार को इस बार मुश्किल हो सकती है. आफरीन सुल्ताना के पति सैयद नौसादुनवी उर्फ पप्पू खां पूर्व में इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. पप्पू खां एक हत्या के मामले में बिहारशरीफ मंडल कारा में बंद हैं. लेकिन पप्पू खां जेल से अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने में सफल रहे. जदयू को पूर्व के चुनाव में सहयोग करने वाले प्रद्युम्न कुमार एवं जदयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार अकेला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप खड़े हो जाने से डॉ. सुनील कुमार को विधान सभा पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी.

नालंदा विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने श्रवण कुमार, राजद ने अरुण कुमार एवं कांग्रेस ने दिलीप कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है. अस्थावां विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में जदयू के विधायक डॉ. जितेंद्र कुमार के कब्जे में है. इस क्षेत्र से राजद-लोजपा ने कपिल देव सिंह और कांग्रेस ने सतीश कुमार को उतारा है. पिछले लोकसभा चुनाव में सतीश कुमार नालंदा संसदीय क्षेत्र से लड़े थे, लेकिन जदयू के कौशलेंद्र कुमार से हार गए थे. इस क्षेत्र से कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें जदयू के कई बाग़ी भी शामिल हैं. इस क्षेत्र में मुक़ाबला जदयू, कांग्रेस और राजद-लोजपा के बीच है. राजगीर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र अभी भाजपा के कब्जे में है. यहां से कांग्रेस ने मानो देवी पासवान और लोजपा ने मृणाल कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है. लोजपा प्रमुख के दामाद मृणाल चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के दिन से ही विवादों के घेरे में हैं. स्थानीय लोजपा नेताओं का मानना है कि राजगीर क्षेत्र के ही लोगों को प्रत्याशी बनाना चाहिए था, परंतु रामविलास पासवान ने अपने दामाद को टिकट देकर जनता से छल किया है. अब देखना है कि इस क्षेत्र में मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं.

कुमार प्रशांत
feedback@chauthiduniya.com

वसुंधरा देवी

अरुण बिंद

वीरेंद्र गोप

हरिनारायण सिंह

कपिल देव सिंह

अरुण कुमार

रीना देवी

उषा सिंह

सत्यदेव नारायण

श्रवण कुमार

राजीव रंजन

दिलीप कुमार

इस गुलदार जोड़े की दर्दनाक मौत की सूचना से वनाधिकारियों के भी होश उड़ गए. सूचना मिलते ही ज़िला वन अधिकारी मीनाक्षी जोशी दल बल सहित घटनास्थल पर पहुंची.

गुलदारों की मौत का अंतहीन सिलसिला

राजकुमार शर्मा

देवभूमि उत्तराखंड सरकार की उपेक्षा एवं मानवीय दखल के कारण वन्य क्षेत्र गुलदारों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है. पिछले दिनों करंट लगने से दो गुलदारों की दर्दनाक मौत ने वन्यजीव प्रेमियों को एक बार फिर हिला कर रख दिया. राजधानी के वीरपुर सैन्य क्षेत्र में पेड़ के पास से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक गुलदार जोड़े ने दम तोड़ दिया. वन विभाग के कर्मचारियों ने दोनों गुलदारों का मालसी डियर पार्क में शव परीक्षण कराया. इस साल अब तक मृत गुलदारों की संख्या एक दर्जन के क़रीब पहुंच चुकी है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 7 जनवरी को ही वर्ष के पहले गुलदार शावक की मौत ऋषिकेश–देहरादून मार्ग पर वाहन के चपेट में आने से हुई थी, दूसरी मौत 22 जनवरी को झाझरा में शिकारियों द्वारा हुई था. तीसरी मौत 30 जनवरी को हुई जब एफआरआई के पास से वन विभाग द्वारा पकड़े गए नन्हें गुलदार शावक ने वन कर्मियों की लापरवाही के कारण दम तोड़ दिया था. चौथी मौत 11 फरवरी को हुई, जिसमें आशारोड़ी के झीवरेहाड़ी में स्थित फार्म हाउस में फंदा डाल कर एक गुलदार को मौत के घाट उतार दिया गया था. 12 फरवरी को झाझरा के मैदान में ही फंदे के सहारे पेड़ से लटकी एक गुलदार की लाश मिली, छठी मौत 20 मार्च को लच्छीवाला रेंज के माजरीग्रांड स्थित शेरगढ़ में फंदा लगा कर एक गुलदार को मौत के घाट उतारा गया था. इसके ठीक एक दिन बाद 21 मार्च को बड़ोवाला में फंदे में फंसे गुलदार ने दम तोड़ा. 17 अक्टूबर को ओल्ड मसूरी मार्ग पर वाहन की चपेट में आकर एक गुलदार ने दम तोड़ दिया था. 25 अक्टूबर को वीरपुर सैन्यक्षेत्र में करंट लगने से गुलदार जोड़े की हुई मौत ने वन्यजीव प्रेमियों को हिला कर रख दिया है. इस गुलदार जोड़े की दर्दनाक मौत की सूचना मिलते ही वनाधिकारियों के भी होश उड़ गए. सूचना मिलते ही ज़िला वन अधिकारी मीनाक्षी जोशी दल बल सहित घटनास्थल पर पहुंची. वन कर्मियों ने दोनों गुलदारों के शव को अपने क़ब्ज़े में लेकर उसका शव परीक्षण कराया. एक गुलदार के पिछले हिस्से व दूसरे के शरीर के अगले हिस्से में चोट के निशान थे. मीनाक्षी जोशी इनकी मौत के पीछे जो कहानी बताती हैं, वह कुछ इस प्रकार है. उनका कहना है कि मेटिंग के लिए गुलदार परिपक्व होकर अपना जोड़ा बनाते हैं, इसी क्रीड़ा के लिए यह जोड़ा सेमल के पेड़ पर चढ़ा होगा जिसके चलते बगल से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया. करंट लगते ही दोनों सिर के बल नीचे गिरे और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. दोनों मृत गुलदारों की उम्र 8–9 वर्ष के करीब आंकी जा रही है. इस वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि मात्र दून इलाक़े में ही नौ गुलदारों की मौत हो चुकी है, जिसमें पांच को फंदे में फंसा कर मारा गया, जबकि दो की मौत वाहनों से टक्कर के चलते हुई. काग़ज़ों पर सरकार ने रात में वन्य क्षेत्र में वाहनों के संचालन पर रोक लगा रखी है, लेकिन वन क़ानून की धज्जियां उड़ा कर रात को सैरसपाटा करने वाले लोग इन वन्यजीवों के लिए काल बन जाते है. जब सरकारी आंकड़े ही इतनी बड़ी संख्या में गुलदारों की मौत की तस्दीक करती हैं, फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सूबे में इनकी मौत की वास्तविक संख्या क्या हो सकती है. भारत सरकार एक ओर वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग को तमाम सुविधाओं से लैस कर रही है, साल 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टाइगर वर्ष ही घोषित कर रखा है, हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी कॉरिडोर बनाया गया है, फिर भी उत्तराखंड में वन्य जीवों की मौत का अंतहीन सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. उत्तराखंड खासतौर पर कस्तूरी मृग, टाइगर , हाथी गुलदार मोर सहित अनेक वन्यजीवों के लिए जाना जाता है. सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य के गठन के बाद पर्यटकों की मनमानी के कारण वन क्षेत्र में बढ़ा मानवीय दखल वन्यजीवों के लिए आफत बन गई है. राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते वन्यजीवों एवं वनों को क्षति पहुंचाने वालों पर नकेल नहीं लग रही है. पूरे राज्य के वनों में तैनात अधिकांश वनाधिकारियों ने अपने आलीशान मकान राजधानी देहरादून में ही बना रखे हैं. इन वनाधिकारियों की कोठी–गाड़ी ही इनके भ्रष्टाचार की कहानी बयां करते हैं. ये अधिकारी वन क्षेत्र मुख्यालय में जाने की भी ग़लती कम ही करते है. आला अफसरों की ग़ैर मौजूदगी के कारण वन्यजीव तस्कर मनमानी करके इन वन्यजीवों को अपना शिकार बनाते हैं. वन विभाग के छोटे कर्मचारी इनके प्यादे के रूप में नज़र आते हैं. सरकार के आलाधिकारी–राजनेता इस सारे खेल को जान कर भी मुंह नहीं खोलते, न उच्चाधिकारियों के ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई ही होती है.

feedback@chauthiduniya.com

गुलदार परिपक्व होकर अपना जोड़ा बनाते हैं, इसी क्रीड़ा के लिए यह जोड़ा सेमल के पेड़ पर चढ़ा होगा, जिसके चलते बगल से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया. करंट लगते ही दोनों सिर के बल नीचे गिरे और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. दोनों मृत गुलदारों की उम्र 8–9 वर्ष के करीब आंकी जा रही है. इस वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि मात्र दून इलाक़े में ही नौ गुलदारों की मौत हो चुकी है, जिसमें पांच को फंदे में फंसा कर मारा गया, जबकि दो की मौत वाहनों से टक्कर के चलते हुई.

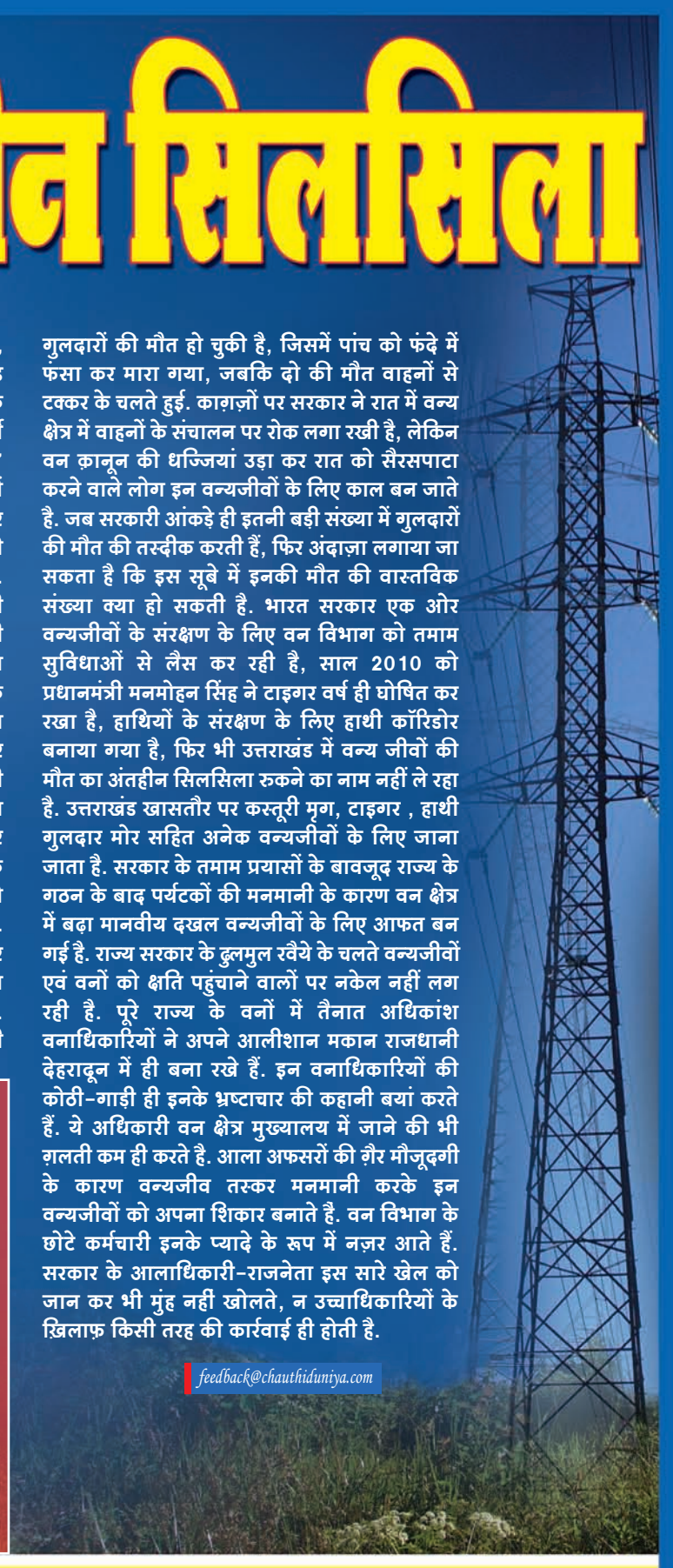

मध्य प्रदेश

विकास के नाम पर लूटखसोट

अरविंद कुमार

आज देश ही नहीं, दुनिया भर में विकास की मौजूदा अवधारणा, दिशा और प्रक्रिया एवं उसके नतीजों को प्रकृति, पर्यावरण तथा आम जन विरोधी साबित करते हुए उन पर गंभीर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं. लेकिन देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के राजनीतिक व प्रशासनिक शासनकर्ताओं को इस बात की बेहद जल्दबाज़ी है कि इन सुलगते सवालों की आग इस राज्य में भी जहां–तहां सर उठाने लगे, इससे पहले ही यहां के तमाम प्राकृतिक संसाधनों को जन साधारण के हाथों से छल–बल पूर्वक छीनकर उन्हें बड़े–बड़े देशी–विदेशी पूंजीपतियों–उद्योगपतियों को बेच दिया जाए. इसके पीछे की असली मंशा यह है कि दलाली के ज़रिए जितना अधिक से अधिक माल बटोरा जा सके, वह किनारा कर लिया जाए.

एक शर्मनाक तथ्य यह है कि कालाहांडी में वेदांता के एक प्रोजेक्ट पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी वहां का दौरा कर दिल्ली में आदिवासियों का सिपाही होने का दावा करते हुए भारी प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अमर कंटक और उसके आस–पास अपनी तरह के अद्वितीय जैव विविधता वाले एक बहुत बड़े इलाक़े में विकास के नाम पर विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं की विनाशलीला पर उनकी अथवा उनकी पार्टी की नज़रें इनायत नहीं हो रहीं. वह भी तब जबकि पिछले 4 से 6 अक्टूबर तक राहुल तीन दिनों की मध्य प्रदेश यात्रा पर आए थे. इस विषय में यह भी ग़ौरतलब है कि बैगा जनजाति की दुर्दशा और स्थानीय प्रभावशाली लोगों द्वारा सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें इलाक़े से खदेड़ने की जानकारी देने वाली सामाजिक संस्थाएं और उनके कार्यकर्ता भी अब राज्यसत्ता के दलालों के सीधे निशाने पर आ गए हैं.

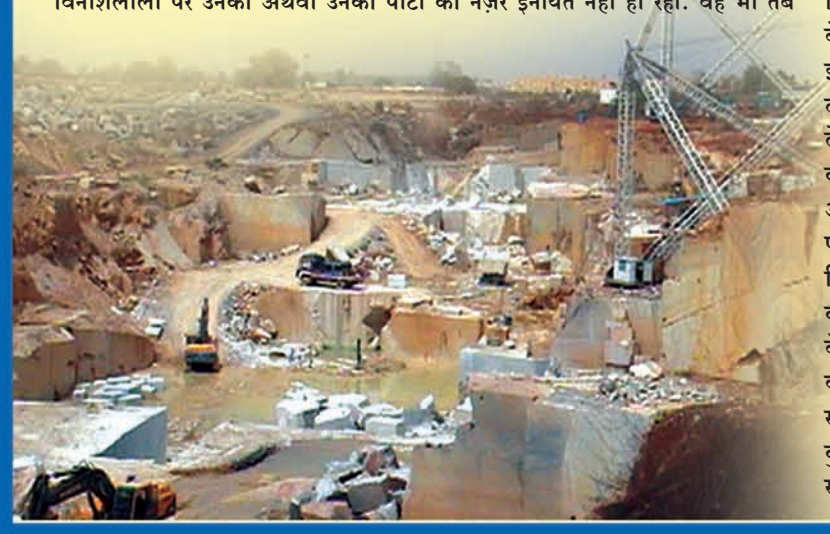

देश के केंद्रीय भूभाग में स्थित तथा लाइमलाइट स्टोन, बॉक्साइट, संगमरमर, आयरन व मैग्नीज और डोलोमाइट तथा तमाम बड़े उद्योगों में बतौर कच्चा माल इस्तेमाल होने वाले ऐसे ही अन्य कई बेशक़ीमती खनिजों को अपने भूगर्भ में समेटे कटनी ज़िले के सुरक्षित आदिवासी विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के मौजूदा भाजपा विधायक तथा पिछली शिवराज सरकार में मंत्री रहे मोती कश्यप जैसे नेता तो ज़िले में प्रस्तावित उद्योगों की तरफ़दारी में औद्योगिक घरानों के छुटभैये प्रतिनिधियों तक की जी हुजूरी करते नज़र आने लगे हैं. मोती कश्यप द्वारा इस शांत इलाक़े में नक्सलियों की आहट का सुनियोजित शिगूफ़ा इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा रहा. इस शिगूफ़े को हवा देने में एक बड़ा अख़बार समूह भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

कटनी ज़िले में क़रीब एक शताब्दी से सीमेंट उत्पादन का बड़ा उद्योग संचालित कर रही और अभी भी अपने कारखानों को निरंतर विस्तार देने में जुटी निजी क्षेत्र की एसीसी हो या फिर नवरत्न कंपनियों में शामिल स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) अथवा पिछले क़रीब दस सालों से बहुमूल्य संगमरमर उत्खनित कर दुनिया भर के बाज़ारों में बेच कर भारी–भरकम मुनाफ़ा कमा रही स्विल, ओजस्वी, आर के आदि, इन औद्योगिक इकाइयों ने इस क्षेत्र का कितना विकास किया है और कितना लूटा–खसोटा है और किस दर्जे तक भ्रष्टाचार फैलाया है, इसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती. अब ऐसे ढेरों उद्योग जल्द ही कटनी के अलावा विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल अंचल का हिस्सा कहलाने वाले सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर आदि आसपास के तमाम ज़िलों की लाखों हेक्टेयर ज़मीन पर बेख़ौफ़ व बेरोकटोक अपने पैर पसारने जा रहे हैं. इनकी आरंभिक गतिविधियों का जायज़ा लेने की कोशिश करते हुए पिछले दिनों कटनी ज़िले में प्रस्तावित एलायंस एनर्जी एंड स्पंज आयरन तथा रिलायबल कंपनी के साथ ही मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अनुपपुर ज़िले में मोज़र बेयर एवं न्यूज़ोन नामक कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले कल कारखानों से प्रभावित होने वाले अनेकानेक गांवों का चौथी दुनिया ने दौरा किया. सल्हना, सकरीगढ़, बसाड़ी, सांधी, सरई, गुड़ाकला एवं खुर्द तथा गुंवारी, मुर्रा, जैतहरी, अमगंवा, तिलिया, रक्सा, कुलमी आदि का दौरा करने और वहां के रहवासियों से रूबरू होने के बाद इस भयावह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जितनी जल्दबाज़ी इन कंपनियों के कारिंदों को यहां के जल, जंगल और ज़मीन आदि नैसर्गिक संसाधनों को जैसे तैसे हथियाने की है, उससे कहीं ज़्यादा उतावली राज्य की सरकार और प्रशासन में बैठे हुए राजनेता तथा अधिकारी हैं. इस उतावलेपन में इनकी ओर से नियम–क़ानूनों को अंगूठा दिखाने से लेकर अमानवीय हथकंडे अपनाने तक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है.

ऐसे सभी उद्योग जिनकी प्रक्रिया अभी प्रारंभिक दौर में है, उनमें से ज़्यादातर वही हैं जिनके एमओयू मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने का दम भर रही शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा पिछले इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित किए गए थे. इन्हें बड़ी मात्रा में ज़मीनें उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी कर सरकार और उसका अमला जितनी तेज़ी बरत रहा है, वह संदेहास्पद है. इसका कारण यह है कि इस प्रक्रिया में ग्राम सभा से लेकर अन्य सभी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की कोई भागीदारी नहीं है. इतना ही नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण एवं पर्यावर्णीय आधारों पर निर्देशित जन सुनवाई जैसे महत्वपूर्ण व संवेदनशील आयोजनों को भी एक गंदे मज़ाक की तरह भाड़े के टट्टुओं एवं असामाजिक तत्वों की भीड़ जुटाकर खानापूर्ति के तौर पर निपटाया जा रहा है.

राज्य में सत्तारूढ़ दल होने के नाते भाजपा तो इस सारे खेल में जमकर चांदी काट ही रही है, कांग्रेस भी यहां पीड़ितों, प्रभावितों के पक्ष में कहीं कोई आवाज़ सुनने को राजी नहीं है. कुछ छोटे राजनीतिक दल और उनके स्थानीय क्षेत्रीय नेता ज़मीनों का दाम बढ़वाने की बिचौलिया गिरी में अपना कुछ हिस्सा बटोरने की जुगत भिड़ाते अवश्य देखे जा रहे हैं. ऐसे गिने–चुने लोग जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें पहले ही विकास विरोधी अथवा नक्सल बताकर ठिकाने लगाने की रणनीति तैयार कर ली गई है. क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर की मीडिया भी इस पर चुप्पी साधे हुए है. लिहाज़ा सारी अंधेरगर्दियां बेधड़क जारी हैं. मगर इन सबके बीच प्रबुद्ध नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा प्रतिबद्ध पत्रकारों का एक छोटा सा वर्ग इन ज़्यादतियों को उजागर करने में जुटा हुआ है. इनकी कोशिशों से कई स्थानों पर ग्रामीणों के समूह जनजीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों के विनाश की क़ीमत पर विनाशक कल कारखानों को इन इलाक़ों में कतई नहीं लगने देने के लिए तत्पर होने लगे हैं. देखना होगा कि सत्ता और पूंजी की अकूत ताक़त के समक्ष ससम्मान तथा आत्मनिर्भर होकर ज़िंदा रहने की स्थानीय वाशिंदों की यह जद्दोज़हद किस सीमा तक अपना असर दिखा पाती है.

feedback@chauthiduniya.com

माल्या के नेतृत्व में बैंक की क्रेडिट कार्ड सेवा उपलब्ध कराने वाली बॉबकार्ड योजना भी दोबारा पटरी पर लौटने लगी है.

एम डी माल्या

दूरदर्शिता और समझदारी ने रचा कामयाबी का इतिहास

मंगलोर देवदास माल्या, देश में बैंकिंग क्षेत्र का ऐसा नाम, जो अपनी लगनशीलता, दूरदर्शिता और बाज़ार के मामलों की व्यापक समझ जैसे गुणों के बूते सफलता की नई–नई कहानियां लिख रहा है. पिछले क़रीब तीन सालों से बैंक ऑफ बड़ौदा में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्य करते हुए माल्या ने नई और दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के बल पर इस बैंक को उपभोक्ता व्यवहार के मामले में निजी बैंकिंग कंपनियों से भी दो क़दम आगे खड़ा कर दिया है. बाज़ार की नब्ज़ को समझते हुए नीतियों का निर्माण और तकनीक के साथ उनका मेल कर माल्या ने बैंक ऑफ बड़ौदा को उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया है कि आज वह देश के शीर्ष चार बैंकों में शामिल है.

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मार्केटिंग और फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त करने वाले माल्या ने अपना करियर कॉरपोरेशन बैंक के साथ बतौर ऑफिसर ट्रेनी शुरू किया था. इतनी छोटी शुरुआत के साथ 27 साल बाद जब उन्होंने कॉरपोरेशन बैंक को छोड़ा तो वह क्रेडिट ऑफिसर के पद तक का सफर तय कर चुके थे. इसमें उनकी अन्य योग्यताओं के अलावा तकनीकी ज्ञान की भी बड़ी भूमिका रही. 1990 में बैंक की नेपथाया शाखा में जब वह ब्रांच मैनेजर थे, तो यह शाखा सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी बैंक की पहली ऐसी शाखा बनी, जो पूरी तरह कंप्यूटरीकृत थी. उनका अगला पड़ाव मुंबई था, जहां पहले उन्हें कॉरपोरेशन बैंक के ट्रेजरी विभाग में तैनात किया गया और फिर वर्ष 2001 में उन्हें जनरल मैनेजर (आईटी) नियुक्त किया गया. वर्ष 2005 में माल्या ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर का पदभार संभाला. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण था. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का अभी–अभी विलय हुआ था और कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं के अलावा तकनीक के इस्तेमाल से संबंधित समस्याएं भी मुंह बाए खड़ी थीं, लेकिन माल्या ने बिना घबराए इन मुश्किलों का बख़ूबी सामना किया और ओबीसी को अनिश्चितता के भंवर से बाहर निकालने में अपना योगदान दिया. नौ महीनों के भीतर ही वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, जहां वह क़रीब दो साल तक रहे. बीमा और म्यूचुअल फंड क्षेत्र की कंपनियों के साथ नए करारों के चलते उनके कार्यकाल के दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल लाभ 51 करोड़ से 271 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंच गया और सेल्स का सालाना टर्नओवर 44 हज़ार करोड़ से 66 हज़ार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. 2008 में माल्या बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए. यहां उनके पास करने के लिए काफी मौक़े थे और बैंक ऑफ बड़ौदा का नेटवर्क पूरे देश में मौजूद था. उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और आज यह बैंक कुल परिसंपत्तियों, मुनाफ़ा और लोन उपलब्ध कराने के लिहाज़ से देश का चौथा सबसे बड़ा, जबकि कुल व्यापार और जमा के लिहाज़ से तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है. देश के सभी क्षेत्रों में फैली इसकी सभी 3200 शाखाओं में कोर बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है.

फोटो– *सुनील मल्होत्रा*

बैंक ऑफ बड़ौदा को सफलता के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए माल्या ने होलसेल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग के लिए अलग–अलग तरीक़ा अख्तियार किया. होलसेल बैंकिंग के क्षेत्र में उनकी नई पहलों का नतीजा यह है कि आज देश की 20 से ज़्यादा बड़ी–बड़ी कंपनियां इस बैंक के साथ जुड़ चुकी हैं. होलसेल बैंकिंग से मिलने वाले कुल राजस्व में पिछले साल के मुक़ाबले 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि कुल लाभ में 88 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह 1585 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू चुका है. रिटेल बैंकिंग में उनकी रणनीति का केंद्र बिंदु होम लोन है. एक सोची–समझी रणनीति के तहत रिटेल क्षेत्र में कुल अग्रिम का आधा हिस्सा होम लोन के लिए आरक्षित रखा गया है, जबकि बाक़ी का आधा हिस्सा ऑटो और एजुकेशन लोन के लिए आरक्षित है. माल्या का मानना है कि रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा जोखिम ज़रूर है, लेकिन यह ज़्यादा मुनाफ़ा भी देता है. रिटेल क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा की पकड़ मज़बूत करने के लिए उन्होंने उपभोक्ता सेवाओं के विस्तार और ब्रांड के निर्माण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए उपभोक्ताओं से अपने स्तर पर संपर्क साधना और मदद के लिए पूछना भारत में अनोखी बात थी, लेकिन माल्या ने ऐसा ही किया. मेट्रो शहरों में बैंक की शाखाओं में बिरला सन के लोगो की जगह बड़ौदा नेक्स्ट के लोगों लगाए जा रहे हैं. अगले एक साल में मेट्रो और अन्य शहरी क्षेत्रों की 1200 से भी ज़्यादा शाखाएं बड़ौदा नेक्स्ट नेटवर्क के अंदर में आ जाएंगी. नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भी माल्या ने अनोखी रणनीति अपनाई. उन्होंने दवा कंपनियों द्वारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भेजने की तर्ज पर सिटी सेल्स आउटलेट्स की योजना बनाई, जहां बैंक के प्रतिनिधि संभावित ग्राहकों से संपर्क साधकर उन्हें अपनी योजनाओं और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं से परिचित कराते हैं. अब तक ऐसे 15 आउटलेट्स खोले जा चुके हैं और जल्द ही यह संख्या 50 के आसपास पहुंच जाएगी.

माल्या के नेतृत्व में बैंक की क्रेडिट कार्ड सेवा उपलब्ध कराने वाली बॉबकार्ड योजना भी दोबारा पटरी पर लौटने लगी है. बॉबकार्ड देश में शुरू की गई सबसे पहली क्रेडिट कार्ड योजनाओं में शामिल है, लेकिन लगातार घाटे के चलते यह खटाई में पड़ गई थी. माल्या के कुशल दिशानिर्देशन का नतीजा यह है कि कई सालों बाद बैंक पहली बार 25 हज़ार नए कार्ड बेचने की योजना बना रहा है. नई योजनाओं के साथ तकनीक को जोड़ते हुए माल्या ने कई ऐसी चीजों की शुरुआत की है, जो भारत में पहले नहीं हुईं, लेकिन अब दूसरे बैंक भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं. समय की नब्ज़ को पहचानना तो जैसे माल्या की फितरत का एक हिस्सा है. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित नौवीं मंजिल के अपने जिस ऑफिस में वह बैठते हैं, उसके ठीक सामने आईसीआईसीआई और सिटी बैंक का मुख्य कार्यालय भी स्थित है. उसे देखते हुए माल्या अक्सर बैंक ऑफ बड़ौदा के सुनहरे भविष्य के सपने देखते थे, साथ ही इससे उन्हें बाज़ार की प्रतियोगिता का एहसास भी होता था. मंदी के दौर में जब आईसीआईसीआई और सिटी बैंक की माली हालत कमज़ोर पड़ी, माल्या ने मौक़ा ताड़ा और नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं शुरू कर दीं. उनका यह तीर निशाने पर बैठा और केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी बैंक ऑफ बड़ौदा आज इस हालत में है कि अपने उपभोक्ताओं का चुनाव कर सके. विदेशों में अपने पैर पसारने के मामले में यह बैंक वैसे भी कभी पीछे नहीं रहा है. इसी का परिणाम है कि आज 26 देशों में इसकी 81 शाखाएं काम कर रही हैं. फिजी जैसे देशों में तो इसे स्थानीय बैंक का दर्जा हासिल है, जबकि यूगांडा में यह शेयर मार्केट का एक हिस्सा है. इस साल जुलाई में लंदन स्थित कार्यालय से माल्या ने एक साल, तीन साल और पांच साल की अवधि वाली ऑनलाइन टर्म डिपोजिट स्कीम की शुरुआत की, जिस पर मिलने वाला ब्याज लिबोर से निर्धारित होता है. भारतीय बैंकों में इससे पहले केवल आईसीआईसीआई बैंक ने ही इस क्षेत्र में क़दम रखा था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की इस योजना के अंतर्गत पहले सप्ताह में ही 720 करोड़ रुपये की राशि जमा हो गई और दो महीनों के अंदर यह आंकड़ा 2100 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

माल्या की एक और बड़ी खासियत है, भविष्य पर नज़र टिकाए रखना. उन्हें पता है कि 2015 तक आते–आते बैंक के टॉप मैनेजमेंट का करीब आधा हिस्सा सेवानिवृत्त हो चुका होगा. बैंक के प्रबंधन में नेतृत्व का संकट न पैदा हो, इसके लिए उन्होंने उड़ान नामक एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है. इसमें यह व्यवस्था है कि छोटे स्तर के कर्मचारियों की प्रतिभा की भी पहचान संभव हो सकेगी. जब नेतृत्व इतना दूरदर्शी हो और अपने कर्मचारियों का इतना ध्यान रखता हो, तो फिर ऐसे किसी संस्थान की कामयाबी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बेवल की यह घटना अद्भुत है, अनुकरणीय है. बेवल की सफलता ने देश की बाक़ी पंचायतों को एक संदेश दिया है.

बेवल का प्रयोग

ग्रामसभा की ताक़त साबित हुई

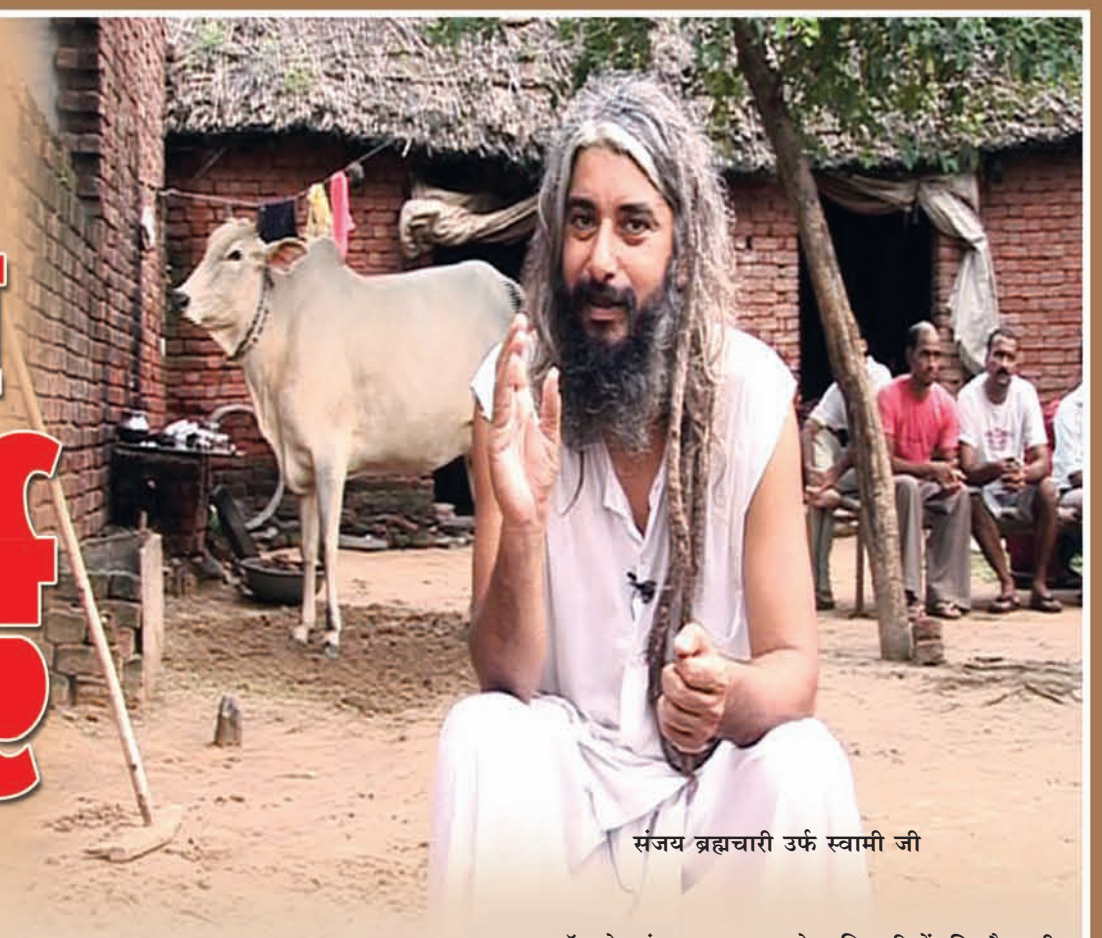

संजय ब्रह्मचारी उर्फ स्वामी जी

शशि शेखर

बेवल का यह प्रयोग अद्भुत है, अनुकरणीय है, देश की बाक़ी पंचायतों के लिए, क्योंकि इसने साबित किया कि ग्रामसभा से बढ़कर कोई नहीं, न विधायिका और न कार्यपालिका. जनता सबसे ताक़तवर है. यह प्रयोग गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करता है. इसने बताया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं. ज़रूरत बस एकजुट होने की है, एक ईमानदार कोशिश करने की है.

दिल्ली और मुंबई में हमारी सरकार, लेकिन हमारे गांव में हम ही सरकार. यानी हमारा गांव हमारी सरकार. एक अच्छे लोकतंत्र की इससे सच्ची परिभाषा शायद दूसरी नहीं हो सकती. गांधी जी का भी यही सपना था. रामराज, सुराज या स्वराज या कहें पंचायती राज. पंचायती राज नामक इस संस्था को कमज़ोर बनाने की हरसंभव सरकारी और ग़ैर सरकारी कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन 13 सितंबर, 2010 की रात हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले की बेवल पंचायत में जो कुछ हुआ, वह पंचायती राज के इतिहास में दर्ज हो गया. एक ऐसा इतिहास, जो आने वाले समय में देश की पंचायती राज संस्था का भविष्य बदल सकता है. उस रात पूरा गांव जाग रहा था. पंचायत भवन में गांव के लोग जमा थे. ज़िले के दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी जागने के लिए मजबूर होना पड़ा.

महेंद्रगढ़ ज़िला मुख्यालय से लगभग तीस किलोमीटर दूर बेवल गांव भी आम भारतीय गांवों की तरह ही है. एक पारंपरिक गांव. कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां समेटे. एक ऐसा गांव, जहां विकास दिखता नहीं, सिर्फ़ काग़ज़ों पर दौड़ता है. गांव के ज़्यादातर लोगों के लिए जीने का सहारा खेती ही है, लेकिन सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है. आप इससे आसानी से गांव वालों की माली हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं. बेवल पंचायत भी अब तक देश की बाक़ी पंचायतों की तरह ही काम कर रही थी. सरपंच का प्रपंच, भ्रष्टाचार और विकास राशि का दुरुपयोग, ये सारी बुराइयां इस पंचायत के लिए कोई नई बात नहीं थीं. बावजूद इसके गांव का सरपंच लगातार दो बार से चुनाव जीत रहा था. समस्या यह थी कि लोग आख़िर चुनें किसे, अगर ईमानदार व्यक्ति का विकल्प हो ही न. लोगों के पास कोई अच्छा व्यक्ति विकल्प के तौर पर नहीं था. लेकिन जून 2010 में हुए पंचायत चुनाव के समय विकल्पहीनता की यह स्थिति ख़त्म हो गई. गांव के लोगों को एक ईमानदार एवं योग्य उम्मीदवार मिल चुका था. इस बार के चुनाव में निवर्तमान सरपंच महावीर सिंह का मुक़ाबला नए उम्मीदवार संजय ब्रह्मचारी उर्फ स्वामी जी से हुआ. दरअसल, गांव के लोगों ने ही स्वामी जी को सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था. उम्मीदवार बनते ही 40 वर्षीय स्वामी जी ने ऐलान किया कि सरपंच बनने पर वह गांव से जुड़े सभी फ़ैसले ग्रामसभा की खुली बैठक में लेंगे. यह घोषणा गांव वालों के लिए किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं थी.

दरअसल बेवल में ग्रामसभा की खुली बैठक कभी हुई ही नहीं थी. गांव वालों को यह बात समझ में आ गई कि ग्रामसभा की खुली बैठक होने से उन्हें ही फ़ायदा होने वाला है. नतीजतन, स्वामी जी को जनता का पूर्ण समर्थन मिला. पंचायती राज को लेकर स्वामी जी के विचारों से गांव वाले इतने प्रभावित हुए कि प्रचार पर बिना पैसा ख़र्च किए स्वामी जी क़रीब पांच सौ वोटों से सरपंच का चुनाव जीत गए. ध्यान देने की बात यह है कि सरपंच का चुनाव पांच सौ वोटों से जीतना अपने आपमें बड़ी बात है. चुनाव जीतने के बाद नए सरपंच यानी स्वामी जी ने अपना वादा याद रखा. अपना काम शुरू करने से पहले स्वामी जी ने कहा कि वह सरपंच का कार्यभार संभालने की कार्यवाही ग्रामसभा की खुली बैठक में करना चाहते हैं.

पंचायती राज क़ानून कहता है कि जो सरपंच चुनाव हारता है, उसे नवनिर्वाचित सरपंच के हाथों में कार्यभार सौंपना होता है. इस हस्तांतरण के तहत पुराना सरपंच अपने कार्यकाल के दौरान रखे गए खातों और काग़ज़ातों को नए सरपंच के हवाले करता है. एक चली आ रही परंपरा (हालांकि इसे सही नहीं माना जा सकता) के मुताबिक़, अधिकारी इन खातों को सरपंच को अकेले में सौंपकर उससे कार्यभार संभालने संबंधी काग़ज़ पर हस्ताक्षर करा लेते हैं. इस मामले में भी उसी परंपरा को दोहराने की कोशिश की गई, लेकिन स्वामी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया. महीना बीत गया. अधिकारी ग्रामसभा की खुली बैठक में कार्यभार सौंपने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे. एक दिन ग्राम सचिव समेत कुछ अधिकारी कार्यभार सौंपने के लिए पहुंचे. स्वामी जी ने ग्रामसभा की बैठक बुला ली. जब काग़ज़ों का मिलान शुरू हुआ तो उनमें भारी गड़बड़ी पाई गई. जमा शेष और वास्तविक राशि में बहुत अंतर था.

दरअसल बेवल में ग्रामसभा की खुली बैठक कभी हुई ही नहीं थी. गांव वालों को यह बात समझ में आ गई कि ग्रामसभा की खुली बैठक होने से उन्हें ही फ़ायदा होने वाला है. नतीजतन, स्वामी जी को जनता का पूर्ण समर्थन मिला. पंचायती राज को लेकर स्वामी जी के विचारों से गांव वाले इतने प्रभावित हुए कि प्रचार पर बिना पैसा ख़र्च किए स्वामी जी क़रीब पांच सौ वोटों से सरपंच का चुनाव जीत गए.

स्वामी जी के मुताबिक़, गांव के तमाम फंडों से लगभग साढ़े तीन लाख रुपये की राशि सरपंच ने अपना कार्यकाल ख़त्म होने के बाद निकाल ली. जबकि नियम के मुताबिक़, कार्यकाल ख़त्म होने के बाद सरपंच गांव के किसी भी फंड से पैसे नहीं निकाल सकता और उसे सारे काग़ज़ात उसी वक़्त प्रखंड विकास अधिकारी के पास जमा करने होते हैं. इसके अलावा रिकॉर्ड में कई और गड़बड़ियां थीं. स्वामी जी ने कहा कि वह कार्यभार तभी संभालेंगे, जब इन सारी गड़बड़ियों को अधिकारी लिखित रूप में देंगे. अधिकारी अगले दिन आने और सब कुछ लिखित रूप में देने का आश्वासन देकर चले गए, लेकिन अगले कई दिनों तक वे आए ही नहीं. उल्टे स्वामी जी को नोटिस मिल गया कि उन्होंने अधिकारियों को गांव में बंधक बनाकर रखा. प्रशासन की मनमर्जी यहीं ख़त्म नहीं हुई. कार्यभार न सौंपे जाने के लिए स्वामी जी को ज़िम्मेदार ठहराते हुए ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें एक कारण बताओ नोटिस थमा दिया कि क्यों न उन्हें निलंबित कर दिया जाए. जबकि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 ऐसे किसी आधार पर एक निर्वाचित सरपंच को निलंबित करने का अधिकार डीसी को नहीं देता. दिलचस्प रूप से इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्वामी जी के साथ पूरा गांव खड़ा था, इसलिए प्रशासन को झुकना ही पड़ा.

13 सितंबर को सुबह दस बजे ज़िले के दो आला अधिकारी मामले को निपटाने के लिए गांव पहुंचे. ज़िला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) दीपक यादव और अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) पंकज. स्वामी जी ने अधिकारियों के पहुंचते ही ग्रामसभा की बैठक बुला ली. गांव के एक प्राचीन मंदिर के पास एक हॉल के अंदर सुबह 11 बजे अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामसभा की बैठक शुरू हुई. काग़ज़ों से भरी दो बोरियां सबके सामने रखी गईं. इसके बाद एक-एक करके उन रिकॉर्ड्स और वाउचरों का मिलान करने का काम शुरू हुआ. हर काग़ज़ात की जांच हुई. एक के बाद एक गड़बड़ियां सामने आ रही थीं. कैशबुक में दिखाई गई राशि से कहीं ज़्यादा पैसे निकाले गए थे. कई जगहों पर वाउचर एंट्री की गई, लेकिन उसकी रसीदें नहीं थीं. कहीं कैशबुक में एंट्री थी, लेकिन मस्टररोल का पता नहीं चल रहा था. गांव के कई फंडों से लाखों रुपये अवैध रूप से निकाले जाने की बात सामने आई.

पूर्व सरपंच महावीर सिंह इस पूरी कार्यवाही के दौरान ग़ायब रहा. अधिकारी क़रीब नौ घंटे तक ग्रामसभा में बैठे रहे. कई घंटे से चल रही कार्यवाही के बावजूद यह तय नहीं था कि कार्यभार सौंपा जा सकेगा या नहीं. क़रीब नौ घंटे बाद यह पाया गया कि कार्यभार संभालने के लिहाज़ से महत्वपूर्ण ज़्यादातर मुख्य रिकॉर्ड्स का मिलान किया जा चुका है, लेकिन अब भी एक सवाल यह था कि सामने आई धांधलियों की ज़िम्मेदारी कौन लेगा. अधिकारी कुछ भी लिखित में देने से कतरा रहे थे, लेकिन स्वामी जी तब तक कार्यभार संभालना नहीं चाहते थे, जब तक अधिकारी सब कुछ लिखित रूप में न दे दें. ग्रामसभा में मौजूद लोगों की तरफ़ से उन्हें मिलने वाले समर्थन के कारण अधिकारी गड़बड़ियों के बारे में लिखित देने के लिए तैयार हो गए. अंतत: रात सवा आठ बजे यानी नौ घंटे से ज़्यादा समय बीतने के बाद नवनिर्वाचित सरपंच स्वामी जी ने कार्यभार संभालने की घोषणा की. देश के पंचायती राज इतिहास में संभवत: यह पहली घटना है, जब किसी सरपंच को ग्रामसभा की खुली बैठक में कार्यभार सौंपा गया हो.

बेवल की यह घटना अद्भुत है, अनुकरणीय है. बेवल की सफलता ने देश की बाक़ी पंचायतों को एक संदेश दिया है. इसने साबित किया कि ग्रामसभा से बढ़कर कोई नहीं, न विधायिका और न कार्यपालिका. जनता सबसे ताक़तवर है. लोकतंत्र में होगा वही, जो जनता चाहेगी. यह प्रयोग गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करता है. इसने बताया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, जरूरत बस एकजुट होने की है, एक ईमानदार कोशिश करने की है. शायद तभी सही मायने में हम सुशासन, और स्व-शासन का आनंद ले सकेंगे.

shashishekhar@chauthiduniya.com

जिन देशों को देखकर यूपीए सरकार ने यह महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, अब उन्होंने भी धीरे-धीरे इस परियोजना से किनारा करना शुरू कर दिया है.

एक बार फिर कश्मीर

मेघनाद देसाई

कश्मीर की अशांति के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को वहां गए डेढ़ महीने से ज़्यादा समय गुज़र चुका है और ऐसा लग रहा है, जैसे हम एक बार फिर उसी हालत में पहुंच चुके हैं. केंद्र द्वारा नियुक्त तीन वार्ताकारों के सामने निस्संदेह एक मुश्किल चुनौती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे न तो किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं और न ही उन्हें कोई आधिकारिक दर्जा हासिल है. इसका फ़ायदा यह है कि वे पिछले 63 सालों से चली आ रही इस समस्या के प्रति विस्तृत और लचीला रवैया अपना सकेंगे. भारत में मुश्किल यह है कि यदि आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं तो किसी भी मुद्दे को लेकर आपका नज़रिया पहले से ही तय होता है. कश्मीर भारत का है और उसका एक अभिन्न अंग है. बात यहीं आकर ख़त्म हो जाती है. यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप या तो देशद्रोही हैं या फिर पाकिस्तान के एजेंट. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के रुखों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं. दोनों ही पार्टियों के प्रधानमंत्री हुए हैं, जिन्हें लगा कि वे इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और पाकिस्तान के साथ एक टिकाऊ समझौता कर सकते हैं. लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मंजिल तक पहुंचते, इससे पहले ही एनडीए सत्ता से बाहर हो गया और मनमोहन सिंह समाधान की तलाश करते-करते निराश होने लगे हैं.

इतिहास की अपनी अहमियत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह भी सत्य है कि ऐतिहासिक तथ्यों पर मतैक्य नहीं होता. हम 1947 के उस दौर में वापस नहीं लौट सकते, जब रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो रहा था. जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तीन ऐसी रियासतें थीं, जो भारत के साथ जुड़ने में आनाकानी कर रही थीं. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि कोई भी रियासत अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती थी, लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी थीं. जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. जूनागढ़ की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसे भारत के साथ रहना है. हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि युद्ध की आशंका बनने लगी थी. जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान से सैनिक सहायता की मांग की, लेकिन पाकिस्तान समय रहते ऐसा नहीं कर पाया और ख़ूनख़राबा होते-होते रह गया.

हैदराबाद में भी जनता की भावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण थीं. वहां का निजाम अपनी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के पक्ष में था. निजाम के सलाहकार वाल्टर मांकटन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना. आख़िर में पुलिस बल के प्रयोग के बाद ही हैदराबाद का भारत में विलय हो पाया, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला इन दोनों रियासतों से अलग था. हैदराबाद और जूनागढ़ के विपरीत कश्मीर के राजा हिंदू थे, जबकि अधिसंख्य जनता मुसलमान. भौगोलिक रूप से भी कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों के ही नज़दीक था और इस आधार पर उसे दोनों में से किसी भी देश में विलय के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था. पाकिस्तान से कबायली लड़ाकू दस्ते अचानक ही कश्मीर में घुस आए और उनका एक ही मक़सद था, पाकिस्तान में कश्मीर का विलय, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने ऐन मौक़े पर भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए. हालांकि इस समय तक पाकिस्तानी सेना के जवान भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन भारतीय सेना ने पहले रियासत की राजधानी की घेराबंदी की और फिर घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के बाहर खदेड़ दिया. इसके बाद मामला संयुक्त राष्ट्र के पास पहुंचा और तबसे यह अभी तक एक समस्या ही बना हुआ है. कांग्रेस पार्टी का यह मानना था कि पूर्ण विलय से पहले जनता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए. हैदराबाद और जूनागढ़ के मामलों में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी. जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते ही जनमत संग्रह कराया जाना था. हालांकि कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था, लेकिन सभी संबद्ध पक्ष इस बात पर एकमत थे कि पूर्ण विलय से पहले जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए. इसी उद्देश्य से संविधान में धारा 370 को जगह दी गई थी.

1953 में शेख अब्दुल्ला ने जवाहर लाल नेहरू को पाकिस्तान से बात करने के लिए कहा, ताकि कश्मीर के दोनों हिस्सों में एक साथ जनमत संग्रह कराया जा सके और भारतीय संघ में उसके विलय की प्रक्रिया पूरी हो सके, लेकिन इसके ठीक बाद शेख अब्दुल्ला को उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया. जम्मू कश्मीर विधानसभा ने जब विलय को मंजूरी दी तो अब्दुल्ला गृहकैद में ही थे. उस समय इस विवाद को ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश की गई और यह आज तक सुलझ नहीं पाया. भारत में अधिकतर लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन यही सच्चाई है. कश्मीर की जनता अभी भी उस घटनाक्रम को याद करती है. उसे अच्छी तरह याद है कि शेख अब्दुल्ला को किस तरह बिना किसी अदालती कार्रवाई के बार-बार नज़रबंद किया गया और छोड़ा गया. यह न्याय व्यवस्था का खुलेआम मज़ाक था. उन्हें बेवजह दंडित किया गया, क्योंकि उन्होंने सच बोलने की ग़लती की थी. कमोबेश यही बात उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों दोहराई और वह सही थे. हालांकि उन्हें इसका कोई फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आता. मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि उन्हें भी कहीं उनके दादा की तरह नज़रबंद न कर दिया जाए. मैं यह भी मना रहा हूं कि केंद्र के वार्ताकारों का भी कहीं यही हश्र न हो.

feedback@chauthiduniya.com

यूनिक आइडेंटिफिकेशन: आधार पर आशंकाएं

ज़ाहिद खान

यूपीए सरकार ने देश के सभी निवासियों को एक विशिष्ट पहचान नंबर यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हाल में पश्चिमी महाराष्ट्र के आदिवासी इलाक़े तेंभली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 आदिवासियों को 12 अंकों वाले विशिष्ट पहचान नंबर की योजना आधार सौंप कर इसकी शुरुआत की. आधार दुनिया की पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें एक अरब से ज़्यादा की आबादी को विशिष्ट नंबर देने के लिए बायोमीट्रिक डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा. अपने तरह की इस अनोखी योजना से देश के हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान नंबर मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल सरकार जहां नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहतर तरीक़े से कर सकेगी, वहीं नागरिक भी सरकारी योजनाओं-सेवाओं का लाभ सुविधाजनक तरीक़े से ले सकेंगे.

आधार के अमल में आने के बाद भारतीय नागरिकों को राशनकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वग़ैरह अलग-अलग पहचान पत्र रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. सिर्फ़ आधार से काम चल जाएगा. यह नागरिकों के लिए एक पक्का सबूत होगा. इसमें नाम, जन्मतिथि और पते जैसी बुनियादी जानकारियों के अलावा व्यक्ति की शारीरिक पहचान जैसे उंगलियों के निशान, चेहरे और शरीर की कोई विशेषता या निशान (बायोमीट्रिक) भी शामिल होगा. रक्त समूह, यदि कोई एलर्जी, बीमारी है या कोई दवाई लेता है तो उसे भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि आपात स्थिति में दवाई दी जा सके और इलाज किया जा सके. यही नहीं, आधार में व्यक्ति के बैंक खातों और लिए गए कर्ज की जानकारी, यदि व्यक्ति कभी गिरफ़्तार हुआ हो, मुजरिम क़रार दिया गया हो जैसी सारी जानकारियां मौजूद होंगी. कुल मिलाकर आधार में नागरिक से संबंधित सभी सूचनाएं एक साथ होंगी. कार्ड के रूप में उक्त सूचनाएं हर समय नागरिक के पास तो रहेंगी ही, केंद्रीय सूचना भंडारण स्थल पर भी जमा कर रखी जाएंगी. यानी एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार होगा, जिसका इस्तेमाल सरकार अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ कर सकेगी. आधार हर नागरिक का पंजीयन और फिर उसका सत्यापन करने का सबसे सरल और सटीक तरीक़ा होगा. यह एक अधि प्रमाणन प्रक्रिया होगी, जिसमें दोहराव और जालसाज़ी कतई नहीं हो सकेगी. वर्तमान में मौजूद पैनकार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, एमएनआईसी जैसे किसी भी डाटाबेस से पंजीयन तो किया जा सकता है, लेकिन इसका सत्यापन आसानी से नहीं हो पाता. फिर दोहरे पहचान पत्रों की वजह से जालसाज़ी होती है. डुप्लीकेट पहचान पत्र बनते हैं, तिस पर कुछ हमारा सिस्टम इस तरह का हो गया है, जहां डुप्लीकेटिंग की आशंका हमेशा बनी रहती है. लिहाज़ा आधार के अंतर्गत एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा रहा है, ताकि पहचान पत्र का सत्यापन और प्रमाणन एक साथ किया जा सके. कोई इसका डुप्लीकेट न बना सके. बायोमीट्रिक या फिंगर प्रिंट के प्रमाणन से जालसाज़ी बिल्कुल नहीं हो पाएगी. जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह फलां है, इसकी तस्दीक आसानी से हो जाएगी. भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण आधार के बहाने देश में राष्ट्रीय प्रमाणन और पंजीयन के साथ पहचान का एक तंत्र खड़ा करना चाहता है, जिसकी बिना पर केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने काम को अच्छी तरह से अमल में ला सकें. देश में आधार के अमल

में आने के तुरंत बाद बैंकिग प्रणाली के दायरे से बाहर खड़े 80 करोड़ से ज़्यादा लोग बैंक व्यवस्था से जुड़ जाएंगे. सरकार एवं नागरिक के बीच सीधा वित्तीय सरोकार क़ायम किया जा सकेगा, जिसका सीधा असर सर्व समावेशी विकास की गति पर होगा और देश की बचत दर पर भी इसका व्यापक असर होगा. हर नागरिक के पास ऐसा वित्तीय खाता बन जाएगा, जिसमें सरकार सीधे धन हस्तांतरित कर पाएगी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना यानी मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का फ़ायदा वास्तविक लोगों तक पहुंचेगा. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें सबसे ज़्यादा खामियां हैं, वह भी दुरुस्त होगी. कोई चाहकर भी उसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएगा. यही नहीं, सरकार यदि कोई योजना बनाती है तो उस पर एक राष्ट्रीय डाटाबेस होगा, जिसके दम पर वह लाभार्थियों को पहचान सकती है. ज़ाहिर है कि आधार के चलते तमाम सरकारी योजनाएं सही तरीक़े से अमल में आ पाएंगी.

एक तरफ़ आधार से आम आदमी को फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आते हैं, वहीं दूसरी तरफ़ इस परियोजना को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं, जो कहीं से निराधार नहीं हैं. जैसा कि सभी को मालूम है कि यह परियोजना देश की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है. इसका कुल बजट फिलहाल 10 हज़ार करोड़ रुपये आंका गया है, लेकिन यह जितनी महंगी परियोजना है, उतनी गंभीरता से इस पर देश के अंदर कहीं भी चर्चा-बहस नहीं हुई. न विधानसभाओं में और न ही संसद में. सैद्धांतिक रूप से यह परियोजना हर लिहाज़ से अच्छी जान पड़ती है, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है और इसके अमल में आने के बाद किस तरह की परेशानियां-दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी तरफ़ सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. यह परियोजना जहां व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन करती है, वहीं इसके व्यवसायिक दुरुपयोग से भी इंकार नहीं किया जा सकता. आधार सीधे-सीधे तौर पर आरटीआई क़ानून का विरोधाभास नज़र आती है. मसलन, सूचना के अधिकार के तहत आम नागरिक सरकार की गतिविधियों और उसकी योजनाओं पर नज़र रख सकता है, वहीं आधार के ज़रिए इसका उलटा हो जाएगा. यानी परियोजना के अमल में आने के बाद सरकार के पास हर नागरिक की निजी पहचान का पूरा ब्योरा आ जाएगा, जिसका वह अपने हित में ग़लत इस्तेमाल भी कर सकती है. परियोजना को लागू करते समय इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा गया कि कैसे बड़े तौर पर सूचनाओं को संगठित करने की धारणा चुपके-चुपके सामाजिक नियंत्रण, युद्ध के उपकरण और जातीय समूहों को निशाना बनाने तथा उन्हें प्रताड़ित करने के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है. जैसा कि अतीत में जर्मनी में नाजियों ने इस सूची का इस्तेमाल यहूदियों के कत्लेआम के लिए किया था. भारत सरकार क्या कोई ऐसी गारंटी दे सकती है कि भविष्य में यदि नाजियों जैसी कोई पार्टी हमारे यहां सत्ता में आती है तो आधार के आंकड़े उसे हासिल नहीं होंगे और वह इंतकाम की भावना से इनका इस्तेमाल नागरिकों के किसी खास तबके के ख़िलाफ़ नहीं करेगी.

देश के मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता यदि इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं तो इसके कुछ ठोस कारण हैं. आधार नागरिकों की निशानदेही की बात करती है, लेकिन नागरिकों की शिनाख्त का जो रास्ता सरकार ने अख्तियार किया है, उसकी बुनियाद 2000 में पारित सूचना तकनीक क़ानून है, जिसे पारित करते समय नागरिकों के निजी जीवन के तथ्यों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया. यही नहीं, आधार सरकार द्वारा नागरिकों पर नज़र रखने का औज़ार मात्र है. यह परियोजना न तो अपनी संरचना और न ही अमल में निर्दोष है. यह बात विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण के कार्ययोजना प्रपत्र पढ़ने से ज़ाहिर हो जाती है. उसमें साफ-साफ लिखा है कि विशिष्ट पहचान अंक सिर्फ़ पहचान की गारंटी है, अधिकारों, सेवाओं या हकदारी की गारंटी नहीं. इसमें आगे यह बात भी बड़ी चालाकी से जोड़ी गई है कि यह पहचान की भी गारंटी नहीं है, बल्कि पहचान तय करने में सहयोगी है.

आखिर में एक बात और, जिन देशों को देखकर यूपीए सरकार ने यह महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, अब उन्होंने भी धीरे-धीरे इस परियोजना से किनारा करना शुरू कर दिया है. संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने सबसे पहले यानी आज से 5 दशक पहले अपने यहां नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रदान किए और उसकी देखादेखी छठवें-सातवें दशक में आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अपने यहां यह प्रणाली लागू की, वे भी अब इस तरह की परियोजना के विचार को लागत और व्यक्ति की निजता के सवाल पर छोड़ चुके हैं. फिर हमारी सरकार को इस परियोजना में ऐसा क्या दिखा कि उसने इस पर संसद और उससे बाहर बात करना भी गवारा नहीं समझा. यह परियोजना देश की सारी आबादी से सीधे-सीधे तौर पर जुड़ी हुई है. इसमें देश का करोड़ों रुपया ख़र्च होना है. लिहाज़ा इसके व्यवहारिक पक्षों की तरफ़ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. कुल मिलाकर परियोजना की तमाम अच्छाइयों के बावजूद आधार के प्रति ये कुछ आशंकाएं भी हैं, जिन्हें दूर किया जाना बेहद ज़रूरी है. जब तक कोई सरकार अपने नागरिकों को यह यक़ीन नहीं दिला देती कि जो योजना शुरू की जा रही है, वह उसके हित में है, तब तक ऐसी कोई भी योजना पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकती.

(लेखक अल्पसंख्यक मामलों के जानकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

सटीक टिप्पणी

25 अक्टूबर-31 अक्टूबर अंक की आवरण कथा-किसी भी क़ीमत पर इन्हें वोट मत दीजिए ने बहुत प्रभावित किया. आपने बिहार के राजनीतिक हालात को बख़ूबी समझते हुए बिल्कुल सही कहा कि दागियों, सौदेबाज़ों और बहुरूपियों को विधानसभा नहीं भेजा जाना चाहिए. यह वास्तव में लोकतंत्र का अपमान है. और यह काम जनता को ही करना होगा. जब वह पूरी तरह सतर्क रहेगी तो अयोग्य लोग किसी भी सदन में नहीं जा सकेंगे.

-त्रिलोक कुमार झा, *जनकपुरी, नई दिल्ली.*

अयोध्या फ़ैसले का आधार

संदीप पांडेय का आलेख-राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद प्रकरण: फ़ैसला न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं (25 अक्टूबर-31 अक्टूबर) पढ़ा. लेखक सही कहते हैं कि यह फ़ैसला संविधान की भावना और क़ानून की दृष्टि से दोषपूर्ण है. यह अलग बात है कि फ़ैसले के माध्यम से विवाद का हल निकालने का प्रयास हुआ. समाधान की राह में इसे एक बड़ा क़दम माना जा सकता है, लेकिन हमें इस सच को भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए कि आस्था किसी फ़ैसले का आधार नहीं बन सकती.

-शैलेंद्र कुमार शर्मा, *श्यामनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

अनिर्णीत फ़ैसला

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर फ़ैसला अनिर्णीत रह गया है. कोई भी न्यायालय इस विषय पर फ़ैसला दे सकने में सक्षम नहीं है. न्यायालय ने राम का जन्म अयोध्या में होना माना है, जो ग़लत है. राम ने अयोध्या जन्म नहीं लिया था. खुदाई में राम कालिक कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं. राम भारत के अविभाजित खंड राजस्थान और दिल्ली वाले भूभाग में जन्मे थे. राम पूर्णरूपेण अहिंसक देवता थे. राम-रावण का युद्ध भी मनगढ़ंत और काल्पनिक है. चौथी दुनिया के साहित्य पृष्ठ पर अनंत विजय महत्वपूर्ण मुद्दों को बेबाकी से उठाकर काफी धारदार लिखते हैं. साहित्य में नैतिकता विषय पर उन्होंने अशोक वाजपेयी की अच्छी ख़बर ली. उधर गैसकांड की त्रासदी और इधर कविता पाठ! वास्तव में वाजपेयी का लेखन भी छद्म है. हरिशंकर परसाई एवं मुक्तिबोध इससे हमेशा अछूते रहे. अशोक वाजपेयी का सारा लेखन ड्राइंगरूम में उपजा लेखन है, जो आगे जाकर धराशायी हो जाता है.

-के के सिंह, *डीएनके कालोनी, कोंडागांव, महाराष्ट्र.*

देशवा में प्रकोप बा

देशवा मा सूखा-बाढ़ दुहनौ कै प्रकोप बा,
दयनीय दशा कै बनत बाइस्कोप बा.
देखौ राहत सरकार कै दरियादिली,
पता नाहीं सामान के बैठ अहैं नई दिल्ली.
कुछ मरिहैं, कुछ बुड़िहैं तौ सरकार चेताए,
जनिहैं तबै, जब मीडिया रोज चिल्लाए.
वै करैं हिसाब तू सहौ भूख पीरा,
मिले राहत जैसे ऊंट के मुंह जीरा.
गोरू बछरू बहिगे, बूड़िगा ट्रैक्टर,
मरा जिया देखै अइहैं लै हेलीकाप्टर.
आउब जाब खाना खर्च बन जाए राहत
मिले कुछू न, कहकै जइहैं आहत.

-शिवराम शुक्ल, *इनायत नगर, फ़ैजाबाद, उत्तर प्रदेश.*

बाहुबलियों का बोलबाला

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची देखकर यह बात साफ हो जाती है कि इस बार भी बाहुबलियों का ही बोलबाला है. सारे दलों ने टिकट वितरण में बाहुबलियों को प्राथमिकता दी है. नतीजा यह होगा कि धन और बाहुबल वाले लोग किसी तरह चुनाव जीत लेंगे और जनता अच्छे, सद्चरित्र उम्मीदवारों को पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि धनाभाव के चलते वे अपना पर्याप्त प्रचार कर नहीं पाएंगे. और जब जनता से जुड़े लोग विधानसभा पहुंचेंगे ही नहीं, तो उसकी समस्याओं को सदन में आवाज कौन देगा? जो लोग पैसा और ताकत का इस्तेमाल करके जीतेंगे, वे तो अपनी ताकत बढ़ाने और पैसा कमाने का ही काम करेंगे. यह स्थिति सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरनाक है.

-शंकर शर्मा, *चिलमिल, बेगूसराय, बिहार.*

निर्भीक पत्रकारिता

26 जुलाई-01 अगस्त का अंक देखने का अवसर मिला. आपकी लेखन शैली से लगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी के बाद आप दूसरे निर्भीक पत्रकार हैं, जिन्होंने वास्तविकता को जनता के सामने रखा. हमारी ओर से आपको साधुवाद. हम भविष्य में भी आपसे इसी तरह निर्भीक लेखन की अपेक्षा रखते हैं.

-अवधेश प्रसाद मिश्र, *माधवगढ़, सतना, मध्य प्रदेश.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

सच्चा धर्म वही, जो आगे बढ़ाए

अयोध्या पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला आने के बाद कई लोग इस सवाल पर बोल रहे हैं. न केवल बोल रहे हैं, बल्कि राजनीति को नए सिरे से मोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं. लेकिन देश की जनता, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और हिंदू भी, इस सवाल से बहुत परेशान नहीं हैं. फ़ैसला आने से पहले देश के, खासकर उत्तर भारत के मंदिरों में भजन-कीर्तन हुए, लोगों को संगठित करने की कोशिश हुई, पर आम आदमी इससे नहीं जुड़ा. दूसरी ओर मुस्लिम समाज ने कहा था कि अदालत का जो फ़ैसला आएगा, वह स्वीकार्य होगा. अदालत से मतलब हाईकोर्ट भी है और सुप्रीमकोर्ट भी.

इसमें कोई दो राय नहीं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला गले से नीचे नहीं उतरता. पहले यह मुक़दमा चला कि यह ज़मीन किसकी है, फिर उसमें विषय जुड़ते चले गए. ज़मीन के विवाद का मुक़दमा राम कहां जन्मे थे, इस पर आकर टिक गया. जजों की समझदारी को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने बताया कि राम बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे पैदा हुए थे. तीनों जज अगर यह भी बता देते कि तीनों रानियों के महल एक थे या अलग-अलग, वे एक कोठरी में रहती थीं या अलग-अलग कोठरियों में, राजा दशरथ का दरबार, उनका शयनकक्ष और उनका भोजनकक्ष कहां था. उनके दरबारी, उनके गुरु, उनकी सेना कहां रहती थी तो देश का बहुत भला होता. लेकिन जज साहबान ने यह सब नहीं बताया.

एक तथ्य और है. गोस्वामी तुलसीदास से पहले देश में वाल्मीकि रामायण चलती थी, जिसमें राम एक पात्र थे, आदर्श पात्र थे और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था. तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखकर उन्हें भगवान बना दिया. भाषा की वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी रामायण उत्तर भारत के घर-घर में लोकप्रिय हो गई और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम में बदल गए. गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समय में थे और रामायण भी तभी लिखी गई थी. राम से जुड़ी आस्था जिसने उन्हें भगवान बनाया, इसी समय पैदा हुई.

देश का कोई हिंदू संगठन वाल्मीकि रामायण की बात नहीं करता. इसका पहला कारण है कि महर्षि वाल्मीकि दलित महात्मा थे, जिन्हें भारतीय मनुवादी समाज ने कभी श्रेष्ठ रूप में स्वीकारा ही नहीं, दूसरे उन्होंने रामकथा को, जैसी थी वैसा लिखा. उस पूरी रामायण में राम की अच्छाइयां, उनकी कमज़ोरियां, उनकी रणनीति की बड़ाइयां और खामियां विस्तार से कही हैं. गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण थे तथा उन्होंने राम के चरित्र को भगवान के रूप में इसलिए रखा, क्योंकि वे तत्कालीन शासन के ख़िलाफ़ आम लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहते थे. रामायण लोगों के इकट्ठा होने, रावण के अत्याचारों पर बात करने का उन दिनों एक माध्यम बन गई थी. जिस कथा को महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पर वह भी जन्म स्थान न लिख पाए, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जब अयोध्या गए तो वह वहां किसी मंदिर में नहीं ठहरे, वह एक मस्जिद में ठहरे. लोगों का कहना है कि वह जगह बाबरी मस्जिद ही थी, जहां गोस्वामी तुलसीदास ठहरे थे. पर गोस्वामी जी के किसी ग्रंथ में राम कहां पैदा हुए थे, वर्णन नहीं मिलता. हमारे तीन महान जजों ने जब यह निर्णय दिया है तो ज़ाहिर है, हमें उनका सम्मान महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास से ज़्यादा करना चाहिए.

पिछली छब्बीस नवंबर को अयोध्या में रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण ने सूफी जिलानी कत्ताल को अपनी पीठ पर बुलाया. यहां राम जानकी का बड़ा मंदिर है और यह क्षेत्र बड़ा स्थान कहलाता है. यहां काफी साधु-संत और सूफी इकट्ठे हुए. महंत जन्मेजय शरण और सूफी साहब को आगे कर सभी लोग उस स्थान की ओर गए, जहां का फ़ैसला हाईकोर्ट ने किया है तथा जिस ज़मीन को तीन बराबर हिस्सों में बांटने की बात कही है. सारे बाज़ार ने उनका स्वागत किया. इन्होंने पहले विवादित और अब फ़ैसले के बाद सारे स्थान को देखा और वहां उपस्थित लोगों से कहा कि मंदिर और मस्जिद बनते रहेंगे, पर अगर लोगों के दिल न बनें तो इनके बनने का मतलब क्या. दोनों ने कहा कि देश में रहने वालों का प्यार और उनका भाईचारा किसी भी मंदिर और मस्जिद जितना ही महत्वपूर्ण है.

देश की जनता यही चाहती है, क्योंकि लड़ने के लिए बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बीमारी, विकास, असमानता जैसे सवाल हैं. यही धर्म की कसौटी है, क्योंकि जो धर्म इंसान को, उसे मानने वालों को ज़िंदगी में आगे न बढ़ाए, वह धर्म इंसान के लिए नए दरवाजे नहीं खोलता. अब सरकार को आगे आना चाहिए और संविधान संशोधन का प्रस्ताव देश के सामने रखना चाहिए. मुसलमानों के बीच समझदार लोगों और देश की सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ सालों पहले हुए एक्सीडेंट को भूल आगे बढ़ने के लिए देश की जनता को आवाज़ देनी चाहिए.

अयोध्या में महंत जन्मेजय शरण के साथ सूफी जिलानी के जाने ने उन्हें घबड़ा दिया, जो इस सवाल का राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं. विश्व हिंदू परिषद के लोगों का बयान आने लगा कि जिस दरवाजे से शंकराचार्य को नहीं जाने दिया गया, उससे ये दोनों कैसे गए. यह वही मानसिकता है, जिसने महर्षि वाल्मीकि को इस देश में सर्व स्वीकार्य नहीं होने दिया. ऐसे लोगों को सूफी का अयोध्या में फ़ैसला दिए स्थान पर जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर ये कुछ सौ साल पहले यदि ज़िंदा होते तो इन्हें गोस्वामी तुलसीदास का मस्जिद में रहकर राम के दोहे रचना भी अच्छा नहीं लगता, ये बयान देते, आंदोलन करते.

पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले ने एक रास्ता दिखाया है, जिससे यह विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है. मेरी प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मौलाना कल्बे रूशैद रिज़वी से बात हुई तथा सूफी जिलानी तथा महंत जन्मेजय शरण से भी बात हुई. सभी का मानना है कि यदि संसद संविधान संशोधन करे कि 15 अगस्त 1947 को देश के जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, वही रहेगी या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले के दिन जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, वही रहेगी और मुसलमान इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को जैसे का तैसा मान लें, तो इस समस्या का हमेशा के लिए निबटारा संभव है. लेकिन इससे वे स्थल अलग हैं जिन्हें सुप्रीमकोर्ट ने अवैध कहा है तथा जिन्हें हटाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को आदेश दिया है.

देश की जनता यही चाहती है, क्योंकि लड़ने के लिए बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बीमारी, विकास, असमानता जैसे सवाल हैं. यही धर्म की कसौटी है, क्योंकि जो धर्म इंसान को, उसे मानने वालों को ज़िंदगी में आगे न बढ़ाए, वह धर्म इंसान के लिए नए दरवाजे नहीं खोलता.

अब सरकार को आगे आना चाहिए और संविधान संशोधन का प्रस्ताव देश के सामने रखना चाहिए. मुसलमानों के बीच समझदार लोगों और देश की सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ सालों पहले हुए एक्सीडेंट को भूल आगे बढ़ने के लिए देश की जनता को आवाज़ देनी चाहिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

अमेरिका : शांति स्थापना की कोशिशों की दरकार

संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभ्य समाज के काफी रूप-गुण विकसित कर लिए हैं. अमेरिकी समाज विकास और बदलाव के एक लंबे दौर से गुजरा है. उसने अंतर्धार्मिक एवं अंतर्सांस्कृतिक रिश्तों का रंगोली मॉडल अपनाया है. यह उस मॉडल से भिन्न है, जिसमें सभी संस्कृतियां देश की मुख्यधारा में घुल-मिल जाती हैं और अपनी अलग पहचान खो देती हैं, जैसे समुद्र में मिलने के बाद नदियों का अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है. इस पृष्ठभूमि में लोरिडा के पॉस्टर टेरी जोंस द्वारा 9/11 की बरसी पर कुरान जलाने की धमकी देने का हालिया घटनाक्रम दु:खद है. पॉस्टर का कहना था कि कुरान एक शैतानी किताब है, जिसने आतंकवाद को जन्म दिया है. अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने उससे यह इरादा त्यागने की अपील की, कई दूसरे तरीकों से भी इस दिशा में प्रयास किए गए. अंतत: वह अपने इस कुत्सित इरादे को छोड़ने के लिए इस शर्त पर राजी हुआ कि ग्राउंड जीरो के निकट मस्जिद बनाने की योजना त्याग दी जाएगी. किसी कारणवश उसकी यह मांग भी अस्वीकार कर दी गई.

पहले ग्राउंड जीरो के नज़दीक मस्जिद के निर्माण का विरोध और फिर कुरान एवं मुसलमानों पर निशाना साधे जाने की यह मुहिम क्या प्रतिबिंबित करती है? यही कि मुसलमान ही आतंकवाद के लिए ज़िम्मेदार हैं. इस समय सब तरफ़ मुसलमानों का दानवीकरण करने का अभियान चल रहा है. इसमें इंटरनेट वेबसाइटों, ब्लॉगों एवं ई-मेल से लेकर मुंह ज़ुबानी प्रचार तक यानी हर तरीक़ा इस्तेमाल हो रहा है. यह लगभग वही रणनीति है, जो भारत में सांप्रदायिक तत्वों द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है. सांप्रदायिक ताक़तों ने अपने अनवरत प्रचार से यह भ्रम फैलाने में सफलता प्राप्त कर ली है कि भारत के अल्पसंख्यक मुसलमान यहां के बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए ख़तरा हैं. अमेरिका से भी मस्जिदों में तोड़फोड़ और मुसलमानों को घृणा जनित हिंसा का शिकार बनाए जाने की ख़बरें आती रहती हैं. अमेरिका में दबी ज़ुबान से यह प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमान देश पर क़ब्ज़ा करने की तैयारी कर रहे हैं. यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा मुसलमानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिससे उनकी हिम्मत और ताक़त बढ़ रही है. इस संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि इस्लाम अमेरिका का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ धर्म है. अमेरिका में इस बढ़ते टकराव के पीछे प्रभुत्वशाली श्वेतों और दबे-कुचले अफ्रीकी अमेरिकियों का आपसी संघर्ष है. इस्लाम की आक्रामकता की इस टकराव में कोई भूमिका नहीं है.

9/11 के बाद अमेरिकी मीडिया ने इस्लामिक आतंकवाद शब्द गढ़कर दुनिया भर के 135 करोड़ मुसलमानों को कठघरे में खड़ा कर दिया. जहां तक कम्युनिस्ट विरोधी अभियान का प्रश्न है, उसने सामाजिक ढांचे पर अधिक कुप्रभाव नहीं डाला, क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म से कम्युनिस्ट नहीं होता, परंतु कोई व्यक्ति जन्म से मुसलमान हो सकता है.

भारत में भी यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बहुपत्नी प्रथा एवं परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग न करने के कारण मुसलमानों की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. इस दुष्प्रचार के ज़रिए बहुसंख्यक समुदाय में यह डर पैदा किया जा रहा है कि वे देर-सबेर अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे. कहने की ज़रूरत नहीं कि आंकड़े और तथ्य इस आशंका को पूरी तरह नकारते हैं. यह भी कहा जाता है कि मुसलमानों को कुरान यह आदेश देता है कि वे काफिरों का वध करें. यह सफेद झूठ है. कुरान तो यह कहता है कि एक निर्दोष इंसान की हत्या पूरी मानवता की हत्या के समकक्ष है. प्रचार किया जा रहा है कि ओबामा ने यह घोषित किया है कि अमेरिका अब ईसाई देश नहीं रह गया है. अगर ओबामा ने ऐसा कहा भी है तो उसका अर्थ मात्र यह है कि अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में सभी धर्मों को बराबरी का स्थान प्राप्त है. ओबामा के इस कथित वक्तव्य के अर्थ को तोड़-मरोड़ कर अमेरिकी जनता को आतंकित किया जा रहा है.

इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध चल रहे इस योजनाबद्ध एवं अनवरत दुष्प्रचार के कारण एक आम मुसलमान आज स्वयं को उतना सुरक्षित, सुखी और प्रसन्न अनुभव नहीं करता, जितना वह पच्चीस-तीस साल पहले तक करता था. अमेरिका में मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस दुष्प्रचार से अत्यंत व्यथित है और खुद को असहज महसूस कर रहा है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पंथ है और मुसलमान देशभक्त अमेरिकी नहीं बन सकते तथा यह भी कि मस्जिदें जिहादी मुसलमानों की पनाहगाह हैं. ग्राउंड जीरो के निकट मस्जिद निर्माण के मुद्दे ने मुसलमानों के विषय में आम अमेरिकियों के पूर्वाग्रह सामने ला दिए हैं. अमेरिका में आज जिस तरह का इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार चल रहा है, उसकी तुलना केवल 1920 एवं 1930 के दशक में जर्मन मीडिया द्वारा यहूदियों के विरुद्ध चलाए गए प्रचार अभियान से की जा सकती है. न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि भले ही यह निश्चित तौर पर न कहा जा सके कि अमेरिका में पिछले साल की तुलना में इस साल मुसलमानों के विरुद्ध घृणा से प्रेरित अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है या नहीं, परंतु यह पक्का है कि आम अमेरिकी पिछले साल की तुलना में आज मुसलमानों से ज़्यादा घृणा करने लगा है. हम भारतीयों ने भी पिछली एक सदी और विशेषकर 1980 के दशक के बाद से इसी प्रक्रिया को देखा-भोगा है. अमेरिका में 9/11, 2001 के बाद से यह प्रक्रिया शुरू हुई.

भारत और अमेरिका के मुस्लिम विरोधी अभियानों में कई समानताएं हैं तो कई अंतर भी हैं. भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ घृणा फैलाने के नतीजे में मुसलमानों के कत्लेआम हुए, वे अपने मुहल्लों में सिमट गए और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिशें हुईं. अमेरिका में इस अभियान, जिसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, से प्रजातांत्रिक संस्थाओं एवं परंपराओं का क्षरण हो रहा है. 1980 के दशक में अमेरिका ने ही पाकिस्तान में स्थापित मदरसों में अलक़ायदा के लड़ाके तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम बनाया था. उद्देश्य था, अफ़ग़ानिस्तान पर क़ाबिज़ रूसी सेनाओं से लड़ने के लिए कट्टर मुस्लिम युवकों की फौज तैयार करना. इसी उद्देश्य से काफिर एवं जिहाद जैसे शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा गया. इन मदरसों से निकले भस्मासुरों ने केवल इस्लामिक मूल्यों पर कालिख पोती, बल्कि मुसलमानों की छवि को गहरा आघात पहुंचाया. यही लड़ाके अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं.

यह दिलचस्प है कि मुसलमानों के दानवीकरण ने कम्युनिस्टों के दानवीकरण का स्थान लिया है. 1950 से 1980 तक अमेरिकी मीडिया कम्युनिस्टों को क्रूर खलनायक और सोवियत संघ को शैतान का साक्षात रूप सिद्ध करने में लगा हुआ था. मेकार्थीवादियों का नारा था, कम्युनिस्टों से घृणा करो. अमेरिका में कम्युनिस्टों को कॉमीज कहा जाता था. उन्हें देश में आने का वीजा नहीं मिलता था. अमेरिकी प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि न तो देशी और न ही विदेशी कम्युनिस्टों के लिए अमेरिका में कोई जगह है. इस मामले में सभी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को ताख पर रख दिया गया था. ईरान में अमेरिकी पिट्ठू शाह रजा पहलवी को अपदस्थ कर अयातुल्लाह खुमैनी के शासन में आने के बाद अमेरिकी मीडिया का स्वर बदल गया. अब उसे इस्लाम में नया ख़तरा नज़र आने लगा. 9/11 के बाद अमेरिकी मीडिया ने इस्लामिक आतंकवाद शब्द गढ़कर दुनिया भर के 135 करोड़ मुसलमानों को कठघरे में खड़ा कर दिया. जहां तक कम्युनिस्ट विरोधी अभियान का प्रश्न है, उसने सामाजिक ढांचे पर अधिक कुप्रभाव नहीं डाला, क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म से कम्युनिस्ट नहीं होता, परंतु कोई व्यक्ति जन्म से मुसलमान हो सकता है. हर मुस्लिम बच्चे के माथे पर उसके पैदा होते ही आतंकवादी, काफिरों का हत्यारा और जिहादी जैसा स्टिकर चस्पा हो जाता है. और यह उसके एक महाशक्ति के प्रभुत्व वाले इस विश्व के क्रूर राजनीतिक यथार्थ को समझने से बहुत पहले हो जाता है. अमेरिका में मुसलमानों एवं इस्लाम के चेहरे पर कालिख पोतने के अभियान के गंभीर और दूरगामी प्रभाव होंगे. इससे अंतर्धार्मिक रिश्तों एवं प्रजातांत्रिक मान्यताओं को गहरा आघात पहुंचेगा. क्या अमेरिकी शासन-समाज प्रजातंत्र के लिए इस बड़े ख़तरे के प्रति जागरूक होगा? मुस्लिम विरोधी अभियान से मुसलमान तो मुसीबतें झेल ही रहे हैं, इससे अमेरिकी प्रजातंत्र की नींव भी कमज़ोर हो रही है. यह अभियान मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है.

राम पुनियानी
feedback@chauthiduniya.com
(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

चीन में पैदा होने वाली हर 100 लड़कियों के मुक़ाबले 119 लड़कों का जन्म होता है. शहरी इलाक़ों में रहने वाले कई चीनी युवा इन दिनों बच्चे नहीं चाहते, जिससे समस्या और बढ़ गई है.

अभी और आगे जाना है

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई के पांच साल

मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के 78 में से 71 मंत्री महज़ साढ़े तीन सालों में 786 बार विदेश यात्राओं पर रहे. इन मंत्रियों ने कुल मिलाकर एक करोड़ दो लाख किलोमीटर की हवाई यात्राएं कीं. 15 दिनों के कॉमनवेल्थ खेल तमाशे के लिए जनता के टैक्स के वे 725 करोड़ रुपये भी लगा दिए गए, जो अनुसूचित जाति–जनजाति कल्याण के लिए बजट में रखे गए थे. कश्मीर में तैनात एक मेजर की मां जानती है कि उसके बेटे की आत्महत्या की कहानी झूठी है और अब उसकी जानकारी के आगे मजबूर भारतीय सेना को मामले की पुन: जांच करानी पड़ रही है. गाज़ियाबाद ज़िले के सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे अध्यापक अपनी पहुंच और पैसों के बल पर अपनी तैनाती ज़िला मुख्यालय में ही करा लेते हैं, यह जानकारी जनता को जब होती है तो पहुंच और पैसों की ताक़त कमज़ोर पड़ जाती है.

ये सारे खुलासे सूचना क़ानून के ज़रिए ही हुए हैं. आप ज़रा सोचें कि क्या ये खुलासे आज से पांच साल पहले तक संभव थे? और अगर थे भी, तो क्या ये खुलासे आम आदमी कर सकता था? गुलामी के लंबे इतिहास के बाद इस देश में परिवर्तन की बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं और इनका आधार बन रहा है 2005 में लागू सूचना का अधिकार क़ानून. 13 अक्टूबर, 2010 को यह कानून पांच साल पुराना हो गया. बिहार के झंझारपुर गांव (जिला मधुबनी) में रिक्शा चालक मज़लूम ने 2006 में ही जिस तरह इस क़ानून का इस्तेमाल किया, उससे इसकी ताक़त एवं उपयोगिता को लेकर एक नया भरोसा पैदा होता है. इंदिरा आवास योजना के तहत 25,000 रुपये देने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर (बीडीओ) के दफ्तर में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी. लाचार, अनपढ़ और ग़रीब मज़लूम तीन सालों से बीडीओ के दफ्तर के चक्कर लगा रहा था. मज़लूम की मदद गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का आवेदन बनाकर की. सवाल पूछते ही एक सप्ताह के भीतर मज़लूम को 15 हज़ार रुपये का चेक मिल गया. एक महीने बाद जब बाक़ी के 10,000 रुपये लेने गए मज़लूम से रिश्वत मांगी गई तो अनपढ़ मज़लूम ने बीडीओ से साफ–साफ कह दिया कि अगर मेरा पैसा नहीं दोगे तो फिर से सोचना की अर्जी लगा दूंगा. सोचना और सूचना में फ़र्क़ न समझने वाले निरक्षर मज़लूम को एक ही अनुभव में मालूम हो गया कि यह कोई बड़ा परिवर्तन हो गया है. ज़ाहिर है, यह परिवर्तन समाज के सशक्तिकरण में सहायक साबित हुआ है. बस ज़रूरत इस क़ानून के इस्तेमाल करने की है, बिना किसी डर के.

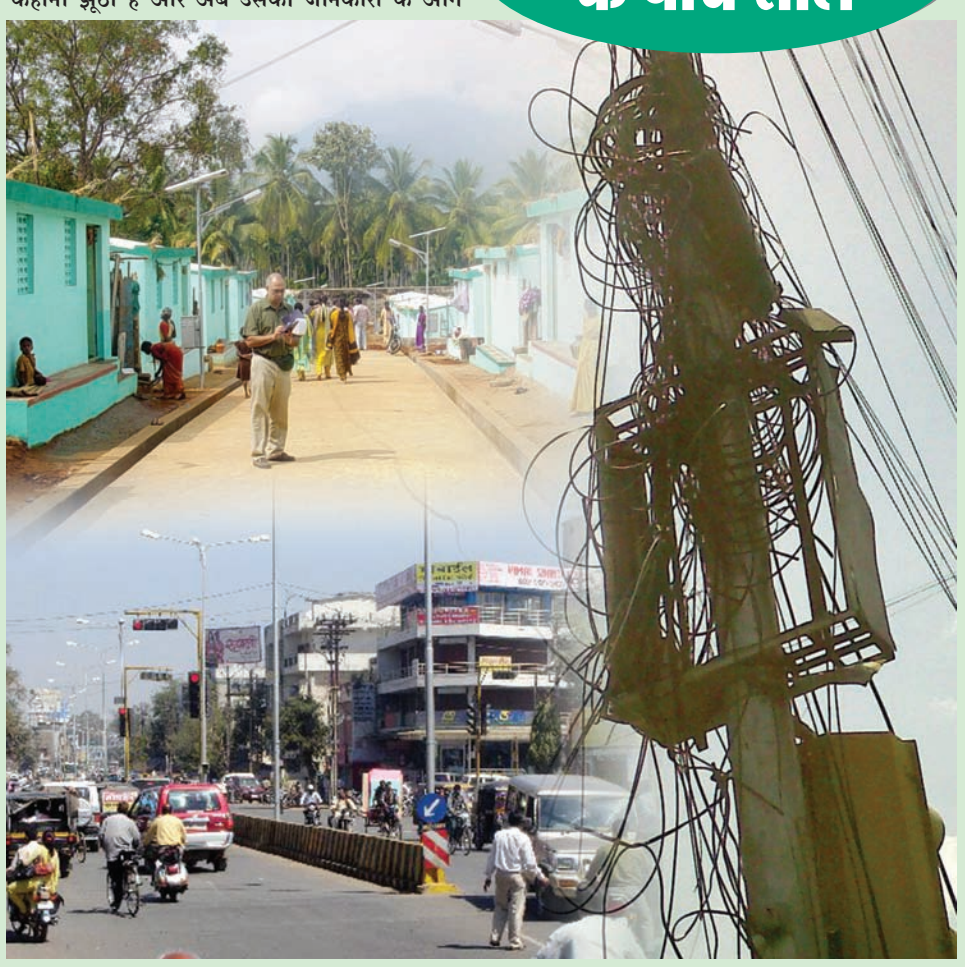

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301

ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

स्ट्रीट लाइट के संबंध में आवेदन

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

निम्नलिखित स्ट्रीट लाइट काफी दिनों से काम नहीं कर रही है.....
इसके लिए कई शिकायतें की जा चुकी हैं (प्रति संलग्न है), लेकिन उन शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. नगर निगम ने इस क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का ठेका किसे दिया है? उस ठेके की प्रति दें.
2. नागरिकों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद कितने दिनों के अंदर खराब लाइटों की मरम्मत हो जानी चाहिए? इससे संबंधित कांट्रैक्ट या यदि कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.
3. यदि लाइटों की मरम्मत उपरोक्त समय सीमा के अंदर नहीं होती है तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? इससे संबंधित कांट्रैक्ट या यदि कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.
4. किन परिस्थितियों में ठेकेदार के भुगतान में कटौती की जाती है? इससे संबंधित कांट्रैक्ट या यदि कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.
5. क्या मेरे द्वारा की गई शिकायतों के संदर्भ में ठेकेदार के भुगतान में कोई कटौती की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?
6. यदि हां, तो कितने दिनों के भीतर नगर निगम ठेकेदार के भुगतान में से कटौती कर लेगा?
7. किन परिस्थितियों में कांट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है? इससे संबंधित नियमों या यदि कोई आदेश दिया गया हो तो उसकी प्रति दें.
8. क्या मेरे द्वारा की गई शिकायतों के संदर्भ में कांट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है?
9. यदि हां, तो कितने दिनों के भीतर नगर निगम कांट्रैक्ट रद्द कर देगा?
10. अगर ठेकेदार अपना काम सही तरीके से नहीं करता है तो नगर निगम के पास कौन–कौन सी शक्तियां हैं, जिनका प्रयोग करके वह ठेकेदार को सही तरीके से काम करने के लिए बाध्य कर सकता है?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....
संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

100 साल की उम्र में पीएचडी

यह ख़बर एक प्रेरणा है उनके लिए, जो शिक्षा को ज़रूरी नहीं समझते. कुछ लोग प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था होने के बावजूद उम्र का बहाना बनाकर अशिक्षित होने की दुहाई देते हैं, लेकिन गुवाहाटी में अध्यापक, वकील एवं न्यायाधीश रह चुके सौ वर्षीय भोलाराम दास फिर से छात्र बने हैं. भोलाराम ने पीएचडी के लिए दाखिला लिया है. वह किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय के सबसे उम्रदराज छात्र हैं. उनके परिवारीजनों एवं दोस्तों ने हाल में उनका 100वां जन्मदिन मनाया. इस मौक़े पर आयोजित एक समारोह में दास ने बताया कि उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए दाखिला लिया है. दास ने कहा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती. दास के शोध का विषय उनके व्यक्तित्व की तरह ही आकर्षक है. दास नव वैष्णव आंदोलन के प्रसार में अपने गांव बोहोरी की भूमिका पर शोध करेंगे. उनका गांव पश्चिमी असम के बरपेटा ज़िले में पड़ता है. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले दास 19 साल की उम्र में दो महीने जेल में बिता चुके हैं. वाणिज्य में स्नातक करने के बाद उन्होंने क़ानून की पढ़ाई की. दास ने बताया, मेरे जीवन के 100 वर्ष काफी संतोषप्रद रहे. इस दौरान अध्यापक और अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए मैं वर्ष 1971 में न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ. उम्र के इस पड़ाव पर छड़ी का सहारा लिए दास को टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखना और पढ़ना पसंद है. दास के परिवार में पांच पुत्र, एक पुत्री, 10 पोते और एक प्रपौत्र हैं. असम के राज्यपाल एवं गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जे बी पटनायक ने कहा, आज के समय में भोलाराम जैसे लोगों के बारे में सुनकर प्रसन्नता होती है. मुझे पूरा विश्वास है कि वह अगली पीढ़ी के लिए एक आदर्श पुरुष साबित होंगे. गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति ओखिल कुमार मेधी का कहना है, विश्व में कहीं भी सौ वर्ष का छात्र मिलना मुश्किल है.

दुल्हन के लिए तरस जाएंगे

चीन सरकार को आगाह किया गया है कि वर्ष 2020 तक लिंग अनुपात में असंतुलन इतना बढ़ जाएगा कि क़रीब दो करोड़ चालीस लाख चीनी युवाओं को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी. यह अध्ययन चीन की सोशल साइंसेज़ अकादमी ने किया है. अकादमी के मुताबिक़, नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में असंतुलन चीन में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी समस्या है. अकादमी का कहना है कि समस्या का मुख्य कारण लिंग से जुड़ा गर्भपात है, क्योंकि चीन में पारंपरिक तौर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा पसंद किया जाता है.

अध्ययन में कहा गया है कि लड़के की तमन्ना के चलते चीन में गर्भपात कराना आम बात है. ग्रामीण इलाक़ों में यह बात ज़्यादा देखी गई है. 80 के दशक में आई अल्ट्रासाउंड स्कैन की सुविधा के बाद गर्भपात के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है. ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में पैदा होने वाली हर 100 लड़कियों के मुक़ाबले 119 लड़कों का जन्म होता है. शहरी इलाक़ों में रहने वाले कई चीनी युवा इन दिनों बच्चे नहीं चाहते, जिससे समस्या और बढ़ गई है. कुछ प्रांतों में तो हर 100 लड़कियों के जन्म की तुलना में 130 लड़कों का जन्म होता है. लिंग अनुपात के इस बढ़ते असंतुलन का मतलब है कि चीन के कुछ हिस्सों में मानव तस्करी और ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति कराने की घटनाएं बढ़

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 08 नवंबर–14 नवंबर 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
दोस्तों के साथ पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है. ज़रूरत का सामान ख़रीदने पर ख़र्च संभव है. किसी योजना को हाथ में लेने से पहले उसके बारे में विचार अवश्य कर लें. स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
व्यापारिक यात्रा के दौरान नए प्रस्ताव मिल सकते हैं. आप काम को टालने के बजाय उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. नए मित्र बनेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें. शांत रहें और छोटी–मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज़ करें.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं. समाज के कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे. परिवारीजनों का सहयोग मिलेगा. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
नया वाहन ख़रीद सकते हैं. तनाव से मन अशांत रहेगा. विरोधी नुक़सान पहुंचाने का प्रयास करेंगे. पुराना काम छोड़कर नया शुरू कर सकते हैं. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
राजकीय मामलों में अनुकूलता संभव है. जल्दी के चक्कर में काम और उलझ सकते हैं. उच्च अध्ययन में आ रही बाधा दूर होगी. समझदारी के साथ अपने काम को अंजाम दें, राह आसान होगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
बुज़ुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है. आकस्मिक लाभ के अवसर मिलेंगे. बिखरे काम समेटने में मदद मिलेगी. अपने लोगों के कारण परेशानी हो सकती है. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बनेगी. कार्यस्थल पर चल रही योजना में देरी हो सकती है. अधिकारियों के कारण बनते कार्यों में बाधा आएगी. जल्दबाज़ी में आपसे चूक हो सकती है. व्यय पर नियंत्रण रखें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
बच्चों के करियर से संबंधित समस्या का समाधान होगा. पुरानी बीमारी उभर सकती है. ले–देकर काम बनाने की नीति नुक़सानदायी रहेगी. नए समझौते होंगे. आय के नए अवसर प्राप्त होंगे. धार्मिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
सहयोगियों की उपेक्षा दु:खी कर सकती है. दूसरों के दखल से पारिवारिक मामले उलझ सकते हैं. व्यापारिक योजना खटाई में पड़ सकती है. पेट से संबंधी शिक़ायत हो सकती है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
भावुकता में आकर कोई ग़लत निर्णय लेने से बचें. कार्य के बीच रुकावटों से आप विचलित होंगे. सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना पड़ सकता है. पुराने मित्र मिलेंगे. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
प्रियजनों का विरोध दु:खी कर सकता है. ज़रूरत पूरी करने के लिए पूंजी की व्यवस्था हो जाएगी. बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा, लेकिन अपने सामान के प्रति सचेत रहें. रचनात्मक क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त होगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
महत्वपूर्ण कारणों से की गई यात्रा सफल होगी. युवाओं को कार्यक्षेत्र में गतिरोध का सामना करना पड़ेगा. आपके रूखे व्यवहार से क़रीबी लोग दु:खी हो सकते हैं. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

भुट्टो ने वह पत्र मुनीर अहमद को भेज दिया और मुनीर के कहने पर ही सुल्तान बशीर ने डॉक्टर अब्दुल क़दीर का इंटरव्यू लिया था.

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम

अब्दुल क़दीर ख़ान की असलियत

महमूद अयाज

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1954 में तब शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बौगरा ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति आइज़न हावर से भेंट करके एटम बराए अमन योजना में शामिल होने और परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन की घोषणा की थी. दरअसल यही शुरुआत थी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की और यह संकल्प था कि परमाणु ऊर्जा को हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. 1963 में ज़ुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने पेश किया, मगर वह ख़ारिज कर दिया गया. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सत्ता में आने के बाद जनवरी 1972 में दिवंगत मुनीर अहमद ख़ान को पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का पदभार सौंपकर इस काम का बाक़ायदा आग़ाज़ किया गया.

दिवंगत मुनीर अहमद उस वक़्त वियाना (आस्ट्रेलिया) में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (एईएआई) में न्यूक्लियर रिएक्टर डिवीज़न के इंचार्ज थे. उन्होंने आते ही परमाणु ऊर्जा आयोग के पुनर्गठन के साथ-साथ कई नए विभाग शुरू किए. यूरेनियम के संवर्धन के लिए कहूटा शोध परियोजना 1974-75 में शुरू की गई और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद उसके पहले अध्यक्ष बने. 1976 में अब्दुल क़दीर ख़ां, जो उस वक़्त हॉलैंड में रहते थे, ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पत्र लिखा. भुट्टो ने वह पत्र मुनीर अहमद को भेज दिया और मुनीर के कहने पर ही सुल्तान बशीर ने डॉक्टर अब्दुल क़दीर का इंटरव्यू लिया था. 1976 में क़दीर ख़ान ने पाकिस्तान आने के बाद सुल्तान बशीर की अध्यक्षता में कहूटा परियोजना पर काम शुरू किया. दिवंगत मुनीर ने परमाणु बम बनाने के लिए चार-पांच बड़े समूह बना दिए और पांच साल के छोटे अंतराल में यानी 1979 तक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल (एनएफसी) के सारे चरण पूरे कर लिए. याद रहे कि परमाणु बम बनाने के लिए दस बड़े चरणों से गुज़रना पड़ता है और कहूटा में केवल एक चरण पूरा होता है. बाक़ी चरण पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के निर्देशन में चलने वाली संस्थाओं में पूरे किए जाते हैं. श्याम भाटिया ने अपनी किताब शहजादी बाई गुड में बेनज़ीर की जुबानी यह ख़ुलासा किया है कि पाकिस्तान परमाणु आयोग 1979 तक न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका था और यही वजह है कि 1980 में चागी में सुरंगें भी तैयार की जा चुकी थीं. 1983 से लेकर 1990 तक विभिन्न स्थानों पर 24 बमों के कोल्ड टेस्ट भी किए गए. आख़िरकार पाकिस्तान के इतिहास में वह वक़्त आया, जब 13 मई, 1998 को प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने अपने मंत्रिमंडल की रक्षा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान एवं डॉक्टर समर मुबारकमंद भी मौजूद थे. डॉक्टर अशफ़ाक़ अहमद जो पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन थे, कुछ दिनों के लिए देश से बाहर गए हुए थे, इसलिए डॉक्टर समर मुबारकमंद पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. नवाज़ शरीफ़ के पूछने पर समर मुबारक ने कहा कि परमाणु धमाकों का काम पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग को ही करना है, लिहाज़ा बैठक में धमाके करने की तारीख़ 28 मई तय की गई. धमाके हो जाने के बाद डॉक्टर अब्दुल क़दीर ने 30 मई, 1998 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह सब उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि धमाके डॉक्टर समर मुबारकमंद की अध्यक्षता में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं तकनीशियनों की सामूहिक मेहनत का नतीजा थे. क़दीर ख़ान द्वारा इंटरव्यू में कही गई बातों का सच्चाई से दूर का भी वास्ता नहीं था. अब्दुल क़दीर ने परमाणु बम बनाने की बड़ी कोशिश की और एक नमूना चीन से भी हासिल किया, मगर वह कामयाब न हो सके. उनका दावा था कि उन्होंने एक कोल्ड टेस्ट किया और परमाणु बम भी बनाया, मगर वह परमाणु बम है कहां?

डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान पेशे के लिहाज़ से एक धातु शोधन करने वाले यानी मेटालार्जिस्ट थे, एटमी मामलों में उनका अनुभव न के बराबर था. वह कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी के सिर्फ़ प्रशासनिक प्रमुख थे. यूरेनियम के संवर्धन का काम पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा के संरक्षण में होता रहा और डॉक्टर जी डी आलम 1980 में कहूटा शोध प्रयोगशाला के प्रमुख थे. 10 जून, 1998 को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान ने पाकिस्तान आने से पहले सेनेटरी फ्यूजिज़ को काम करते नहीं देखा था और सेनेटरी फ्यूजिज़ की जो डिजायनें डॉक्टर क़दीर लाए थे, वे अपूर्ण थी, उन्हें यहां के वैज्ञानिकों ने पूरा किया. इन डिजायनों का विवरण कोरिरा गार्डन ने अपनी किताब बॉम्ब ऑफ शॉपिंग में बयान किया है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्ट्रेटचिंग स्टडीज़ (आईआईएसएस) ने डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान के नेटवर्क के बारे में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ (डोजियर) तैयार किया है, जिसमें उनके कारनामों और परमाणु फैलाव का ज़िक्र है.

दरअसल परमाणु बम बनाने के लिए कई चरणों से गुज़रना पड़ता है. यूरेनियम धातु का खनन, कुटाई-पिसाई और फिर सफ़ाई के बाद इसे केक यलो में परिवर्तित किया जाता है, जिसे बाद में गैस की शक्ल में परिवर्तित किया जाता है. यूरेनियम हस्का फ्लोराइट, जिसके बग़ैर यूरेनियम का संवर्धन संभव ही नहीं, के साथ-साथ यूरेनियम डाईऑक्साइड की रॉड बनाकर उसे परमाणु बिजलीघर के लिए ईंधन के तौर पर तैयार किया जाता है. परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम के अधिक सीमा तक संवर्धन की आवश्यकता होती है और गैस (यूएफबी) को धातु (मेटल) की शक्ल दी जाती है और इन्हीं धातु छड़ों को हथियारों में प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाया जाता है और आख़िर में परमाणु हथियारों को चलाने के लिए उनका भूमिगत परीक्षण किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में केवल यूरेनियम हक्सा फ्लोराइड का 90 प्रतिशत संवर्धन कहूटा में किया जाता था और शेष चरण पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के संरक्षण में चलने वाले संस्थानों में पूरे होते थे. ये सारे काम पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग ने दिवंगत मुनीर अहमद की अध्यक्षता में 1979 में ही पूरे कर लिए थे. डॉक्टर अब्दुल क़दीर जो कहूटा के प्रशासनिक प्रमुख थे, उन्होंने इस हैसियत का ग़ैर ज़िम्मेदाराना प्रयोग किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई और पाकिस्तान को ग़ैर ज़िम्मेदार देश समझा जाने लगा. 1974 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए पश्चिमी दुनिया ने पाबंदी लगा दी थी, इसीलिए परमाणु आयोग ने सभी काम पर्दे के पीछे रहकर बड़ी ख़ामोशी से किए, लेकिन क़दीर ख़ान ने ज़रदारी का फ़ायदा उठाया और न्यूक्लियर कार्यक्रम के कर्ताधर्ता बन बैठे.

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के असल कर्ताधर्ता दिवंगत अहमद ही थे, जिनके संरक्षण में न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के सभी चरण पूरे किए गए, 24 कोल्ड टेस्ट हुए, चाग़ी की सुरंगें तैयार की गईं, खुशाब परमाणु रिएक्टर की बुनियाद रखी गई, चश्मा न्यूक्लियर प्लांट लगाने का अनुबंध चीन से किया गया और न्यूक्लियर स्टडीज़ सेंटर को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया. इन सारे कामों में मुनीर अहमद के साथ एक बड़ी टीम शामिल थी. आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया को यक़ीन दिलाया जाए कि अब्दुल क़दीर का यूरेनियम के संवर्धन के अलावा कोई और योगदान नहीं रहा. पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम (पीएईसी) पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के संरक्षण में है, जो कि साफ और पाक है और यह कार्यक्रम सुरक्षित हाथों में है.

feedback@chauthiduniya.com

डॉक्टर अब्दुल क़दीर ने 30 मई, 1998 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह सब उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि धमाके डॉक्टर समर मुबारकमंद की अध्यक्षता में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं तकनीशियनों की सामूहिक मेहनत का नतीजा थे. क़दीर ख़ान द्वारा इंटरव्यू में कही गई बातों का सच्चाई से दूर का भी वास्ता नहीं था. अब्दुल क़दीर ने परमाणु बम बनाने की बड़ी कोशिश की और एक नमूना चीन से भी हासिल किया, मगर वह कामयाब न हो सके. उनका दावा था कि उन्होंने एक कोल्ड टेस्ट किया और परमाणु बम भी बनाया, मगर वह परमाणु बम है कहां?

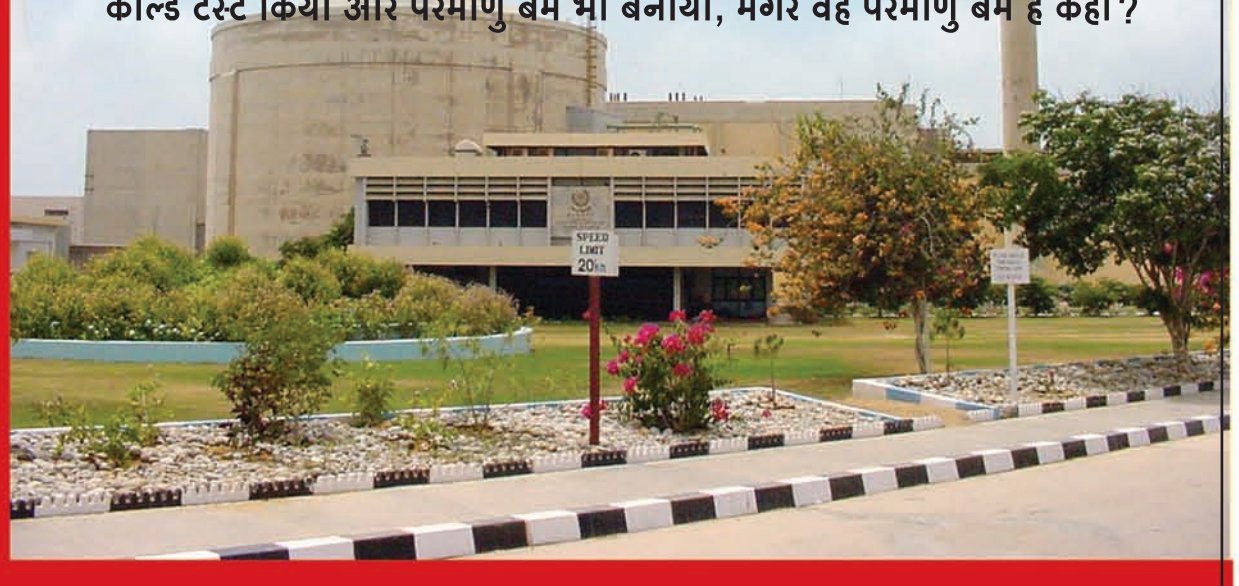

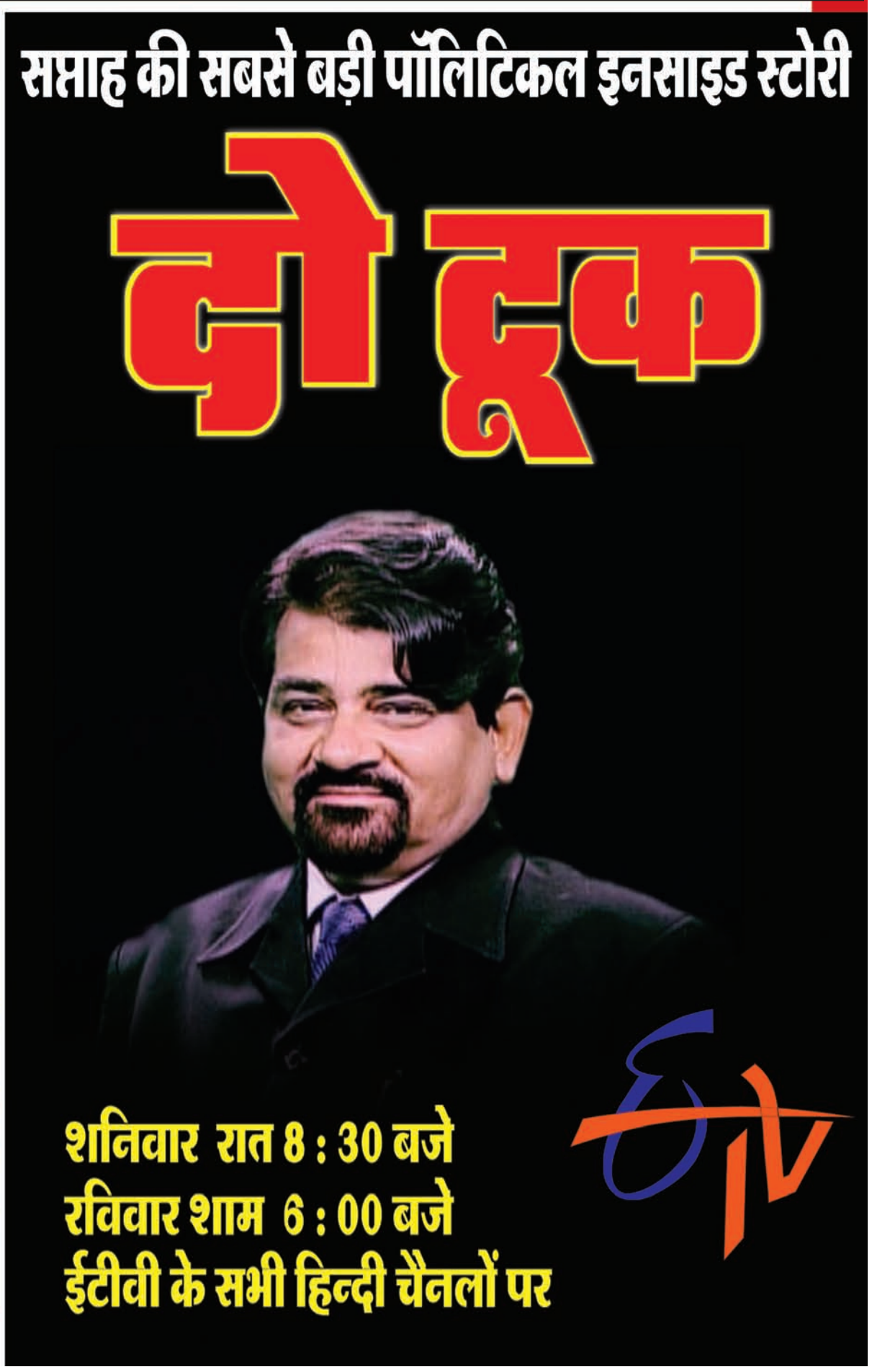

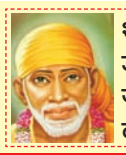

शामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया, जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा. बाबा का एक बड़ा चित्र, जो कि मकान के अग्रिम बाग के ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए.

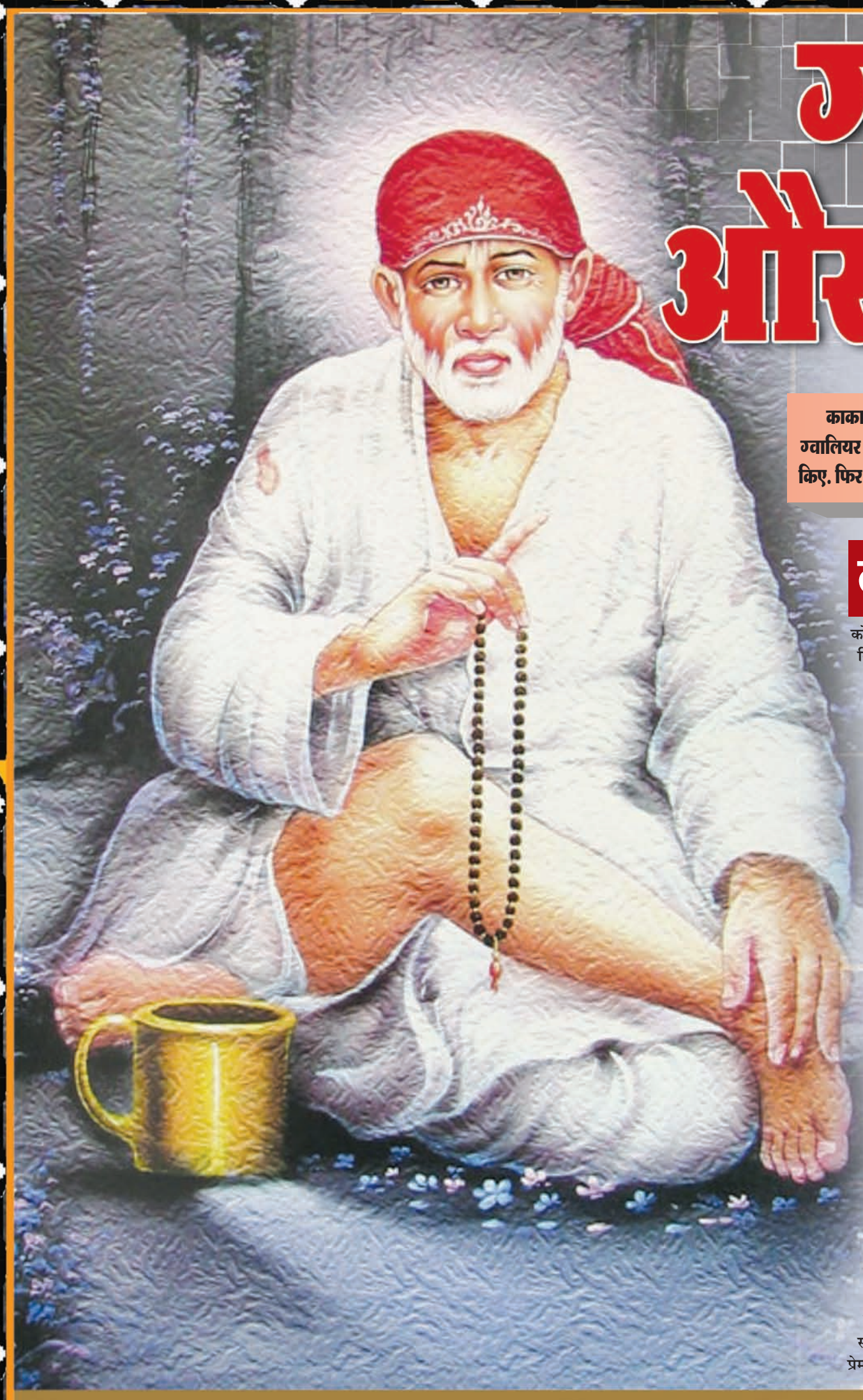

गया यात्रा और साईं बाबा

काका साहेब ने शामा को दो सौ रुपये ख़र्च के निमित्त दिए. वहां से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गए. वहां नाना साहेब चांदोरकर ने सौ रुपये और उनके संबंधी जठार ने भी सौ रुपये शामा को भेंट किए. फिर शामा काशी पहुंचे, जहां जठार ने लक्ष्मी-नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया.

बा से परिचय होने के कुछ समय पश्चात ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया और लगभग उसी समय नाना साहेब चांदोरकर ने भी ग्वालियर में अपने ज्येष्ठ पुत्र की शादी करने का कार्यक्रम बनाया. दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेमपूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया. इस पर उन्होंने उनसे अपने प्रतिनिधि शामा को ले जाने के लिए कहा, परंतु जब उन दोनों ने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं शामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा.

बाबा की आज्ञा प्राप्त कर शामा ने इन उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए पहले नागपुर, ग्वालियर और इसके बाद काशी, प्रयाग एवं गया जाने का निश्चय किया. अप्पा कोते भी शामा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए. पहले तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे. वहां काका साहेब ने शामा को दो सौ रुपये ख़र्च के निमित्त दिए. वहां से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गए. वहां नाना साहेब चांदोरकर ने सौ रुपये और उनके संबंधी जठार ने भी सौ रुपये शामा को भेंट किए. फिर शामा काशी पहुंचे, जहां जठार ने लक्ष्मी–नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया. अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी शामा का अच्छा स्वागत किया. शामा और कोते अयोध्या में 21 दिन और काशी (बनारस) में दो माह ठहर कर फिर गया के लिए रवाना हो गए. गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता सी होने लगी. फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे. प्रातःकाल गया वाला पुजारी (पंडा), जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था करता था, आया और कहने लगा कि सारे यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए अब आप भी शीघ्रता करें. शामा ने सहज ही उससे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है? इस पर पुजारी ने कहा कि नहीं, आप मेरे यहां पधार कर वस्तुस्थिति का स्वयं अवलोकन कर लें. तब वे दोनों उसके मकान पर पहुंचे. उसका मकान क्या, एक विशाल महल था, जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम कर सकते थे. शामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया, जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा. बाबा का एक बड़ा चित्र, जो कि मकान के अग्रिम बाग के ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए. उनका हृदय भर आया और उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो आई कि मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात शामा से आगे ही पहुंच जाऊंगा. शामा की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा कंठ रुंध गया और रोते–रोते उनकी घिग्घियां बंध गईं. पुजारी ने शामा की ऐसी स्थिति देखी तो उसने सोचा कि यह व्यक्ति प्लेग की सूचना पर भयभीत होकर रुदन कर रहा है, परंतु शामा ने उसकी कल्पना के विपरीत प्रश्न किया कि यह बाबा का चित्र तुम्हें कहां से मिला. उसने उत्तर दिया कि मेरे दो–तीन सौ दलाल मनमाड और पुणतांबे श्रेत्र में काम करते हैं और उस क्षेत्र से गया आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हैं. वहां शिरडी के साई महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी. लगभग बारह वर्ष हुए, मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया था और वहीं शामा के घर में लगे हुए उनके चित्र से मैं आकर्षित हुआ था. तब बाबा की आज्ञा से शामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था, यह वही चित्र है. शामा की पूर्व स्मृति जागृत हो आई और जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि यह वही शामा हैं, जिन्होंने उसे यह चित्र भेंट किया था और आज उसके यहां अतिथि बनकर ठहरे हैं तो उसके आनंद की सीमा न रही. दोनों बड़े प्रेमपूर्वक मिलकर हर्षित हुए. फिर पुजारी ने शामा का बादशाही ढंग से भव्य स्वागत किया. वह एक धनाढ्य व्यक्ति था. स्वयं डोली में और शामा को हाथी पर बैठाकर ख़ूब घुमाया तथा हर प्रकार से उनकी सुख–सुविधा का ध्यान रखा. इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले. उनके मन में अपने भक्तों के प्रति अपार स्नेह था. वे सभी प्राणियों से प्रेम करते थे और उन्हें अपना ही स्वरूप समझते थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बाबा की द्वारकामाई

सच्चिदानंद सद्गुरु साई नाथ महाराज को शिरडी के साई बाबा के नाम से आज हर व्यक्ति जानता है. विक्रम संवत 1975 (सन् 1918 ई.) की विजयादशमी के अपरान्ह काल में महासमाधि लेकर यद्यपि साई बाबा ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनके भक्त उनकी उपस्थिति को आज भी महसूस करते हैं. शिरडी में बाबा की समाधि–मंदिर में पहुंचने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उनका शुभाशीर्वाद अवश्य मिलता है. साई बाबा के कारण ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव ताल्लुका में स्थित शिरडी नामक स्थान महातीर्थ बनकर संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गया. साई नाथ ने शिरडी में एक पुरानी वीरान मस्जिद को अपना निवास बनाया. यहां बाबा लगभग 60 साल रहे. साई बाबा की अलौकिक शक्तियों को धीरे–धीरे लोग पहचानने लगे और उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने लगे. साई नाथ से मिलने वालों में दीन–हीन, साधु–संत, पंडित–विद्वान, सिद्ध–अवधूत, उच्चाधिकारी एवं राजघरानों के सदस्य यानी सभी प्रकार के लोग होते थे. मस्जिद को बाबा ने द्वारकामाई नाम दिया, जहां सबको आश्रय मिला. समाज के सभी वर्ग के लोग साई नाथ के दर्शनार्थ द्वारकामाई आते थे. यहां बाबा का खुला दरबार लगता था.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

डॉ. भटनागर ने अपने लेखन के ज़रिए इतिहास को वर्तमान और उसकी समस्याओं के निदान से जोड़ने जैसा महत्वपूर्ण काम किया.

अप्रासंगिक लेखक संगठन

अनंत विजय

वर्ष 1935 में लंदन के नानकिंग रेस्तरां में बैठकर सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता एवं मोहम्मद दीन तासीर जैसे लेखकों ने एक संगठन की बुनियाद रखने की बात पर विचार विमर्श किया था और यही विमर्श बाद में इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का आधार बना और इसी नाम से संगठन की नींव पड़ी. अपनी किताब यादें में सज्जाद ज़हीर ने लिखा है, हमको लंदन और पेरिस में जर्मनी से भागे, निकाले हुए मुसीबत के मारे लोग रोज मिलते थे. फासिज्म के अत्याचार की दर्दभरी कहानियां हर तरफ़ सुनाई पड़ती थीं. जर्मनी में स्वाधीनता प्रेमियों और कम्युनिस्टों को पूंजीवादियों के गुंडे तरह–तरह की शारीरिक यातनाएं पहुंचा रहे थे. वे भयानक तस्वीरें, जिनमें जनता के प्रिय नेताओं की पीठ और कूल्हे कोड़ों के निशान से काले पड़े हुए दिखाई देते. वे दहशतनाक घटनाएं, जो समय–समय पर अख़बारों में छपतीं, उन सबने हमारे दिलोदिमाग़ की आतंरिक शांति और संतोष को मिटा दिया था, फलस्वरूप हम धीरे–धीरे समाजवाद की ओर झुकते जा रहे थे. मार्क्स और दूसरे साम्यवादी लेखकों की पुस्तकें हमने बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू किया. जैसे–जैसे हम अपने अध्ययन को बढ़ाते, हमारे दिमाग़ रोशन होते और हमारे मन को शांति मिलती. बाद में इन्हीं सज्जाद जहीर ने 1936 में लंदन से भारत लौटकर यहां प्रगतिशील लेखक संगठन की बुनियाद रखी. संगठन बनाने में उन्हें भारत में मुंशी प्रेमचंद, डॉ. अशरफ एवं हीरेन मुखर्जी आदि का सहयोग मिला. प्रेमचंद ने 1936 में हंस के अंक में इस संगठन का घोषणापत्र भी प्रकाशित किया. शुरुआत में इस संगठन से उर्दू के लेखक सक्रियता से जुड़े, लेकिन कालांतर में हिंदी के दिग्गजों ने इस आंदोलन से जुड़कर इसे मज़बूत किया. पहले तो इस संगठन का झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर रहा, लेकिन बाद के दिनों में यह वामपंथी पार्टियों का पिछलग्गू बनकर रह गया.

पिछले कुछ वर्षों से लेखकों की सामाजिक भूमिका लगभग ख़त्म हो गई है. कहीं से भी यह लगता ही नहीं है कि समाज और उसकी समस्याओं से उनका कोई जुड़ाव भी है. किसी भी बड़े सामाजिक प्रश्न पर उनकी एकजुटता नज़र नहीं आती है. चाहे वह तस्लीमा नसरीन को भारत में स्थायी वीजा न देने का मामला हो, उन्हें पश्चिम बंगाल से बाहर निकालने का वामपंथी सरकार का फ़ैसला हो,

नक्सलियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या का मामला हो, उक्त लेखक संगठन चुप्पी साधे रहते हैं. लेखक संगठन दरअसल कुछ ग़ैर लेखकों के जेबी संगठन बनकर रह गए हैं और वे छोटे–छोटे गुटों में बनाई अपनी ही दुनिया में संतुष्ट नज़र आते हैं, जबकि साहित्य और संस्कृति के सामने संकट गहराता जा रहा है. जब 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी तो दो दशकों तक इसने सभी भारतीय भाषाओं में समान रूप से लेखकों को जोड़कर गंभीरता से काम किया, लेकिन समय बीतने के साथ यह संगठन कमज़ोर होता गया और आज तो हालत यह है कि कुछ शहरों को छोड़ दें तो यह लगभग मृतप्राय: है. सज्जाद ज़हीर के उपरोक्त कथन से यह साफ है कि लेखकों की सामाजिक सक्रियता को लेकर लेखक संगठनों की स्थापना की गई थी, लेकिन अब वह सामाजिक निष्क्रियता में तब्दील हो गई है. कहने के लिए तो आज हिंदी में तीन लेखक संगठन हैं और तीनों अलग–अलग कम्युनिस्ट पार्टियों से संबद्ध हैं. प्रगतिशील लेखक संघ सीपीआई से, जनवादी लेखक संघ सीपीएम से और जन संस्कृति मंच सीपीआई–एमएल से. लेकिन संबद्धता के चोले में उक्त लेखक संगठन इन पार्टियों के पिछलग्गू हैं और हर अहम मसले पर अपने आकाओं का मुंह ताक़ते हैं. हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यह तक पता नहीं चलता है कि इनके अध्यक्ष और सचिव कौन हैं.

आज तो हालत यह हो गई है कि बड़े सामाजिक और साहित्यिक मुद्दों पर चुप्पी साधने वाले इन लेखक संगठनों के होने का पता तब चलता है, जब किसी लेखक की मृत्यु होती है. इसके बाद लेखक संगठन एक शोकसभा का आयोजन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं. मुद्दों को लेकर लेखकों ने आपस में मिलना बंद कर दिया है. दूसरी सबसे शर्मनाक बात यह है कि इन लेखक संगठनों को किसी भी लेखक के मरने के बाद ही उसकी महत्ता समझ में आती है. उक्त संगठन किसी भी लेखक के जीवित रहते उसकी रचनाओं के संदर्भ में कुछ भी कहने–करने से कतराते रहते हैं, लेकिन उसके मरते ही ये उसे महान और उसकी रचनाओं को बेहद अहम बताने लग जाते हैं. इससे लगता है कि उक्त लेखक संगठन लेखकों की मरने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं. कई साल पहले हिंदी के एक वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल ने एक बातचीत में कहा था कि लेखक संगठन लेखकों की यूनियन नहीं हैं, जो कॉपीराइट आदि के मुद्दे पर संघर्ष करें. उनका मानना था कि ये वैचारिक संगठन हैं, जिनका काम साहित्य की दुनिया में वैचारिक संवेदना का प्रचार करना है. अगर मंगलेश की बातों को मान भी लिया जाए तो सवाल यह उठता है कि वैचारिक संवेदना के प्रचार के लिए भी लेखक संगठन क्या कर रहे हैं? जवाब शायद ही मिल पाए. लेकिन इन लेखक संगठनों से जुड़े लेखक की रचनाओं पर अगर किसी आलोचक या समीक्षक ने प्रतिकूल टिप्पणी कर दी तो पूरा का पूरा संगठन उस पर टूट पड़ता है. कुछ दिनों पहले पटना से निकलने वाली एक पत्रिका में जसम से जुड़े एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त एक कवि की कविताओं पर संपादक ने टिप्पणी क्या कर दी, मानो भूचाल आ गया. जन संस्कृति मंच से जुड़े लेखकों ने संपादक के ख़िलाफ़ हल्ला बोल दिया.

आज जो लोग लेखक संगठन चला रहे हैं, वे उसे एक सिंडिकेट की तरह ऑपरेट करते हैं और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए बेहद सोची–समझी रणनीति बनाकर उसे अंजाम देते हैं. इस तरह से लेखक संगठन अब बड़े साहित्यिक सरोकारों से विमुख होकर पर्सनल स्कोर सेट करने का औज़ार बन गया है. आज ज़रूरत इन लेखक संगठनों की भूमिका पर पुनर्विचार की है. इन संगठनों की निष्क्रियता के पीछे वामपंथी राजनीति की अवसरवादिता की राजनीति है. लेखकों के बीच भी पद और पुरस्कार पाने की लोलुपता बढ़ती जा रही है. वैचारिकता पर अवसरवादिता हावी हो गई है. तमाम लेखक इस दंद–फंद में जुटे रहते हैं कि किस संगठन से जुड़कर उन्हें लाभ हो सकता है. यह तय करते ही वे उन संगठनों से जुड़कर साहित्यिक मठाधीशों का आशीर्वाद प्राप्त करने की जुगत में लग जाते हैं. सच तो यह है कि इन दिनों कोई भी लेखक इन संगठनों से न तो कोई ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे हैं और न ही कोई वैचारिक दिशा. इन लेखक संगठनों की इतनी ख़राब हालत है कि वे अपने ही साथी लेखकों के हित के लिए भी कोई संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं. कॉपीराइट और रॉयल्टी हिंदी में लेखकों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और तमाम लेखकों को इस मुद्दे पर शिक़ायत रहती है. प्रकाशकों द्वारा लेखकों के शोषण की बात अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन अभी तक लेखक संगठनों ने इस शोषण के ख़िलाफ़ कोई ठोस आवाज़ नहीं उठाई है, आंदोलन की बात तो दूर की कौड़ी है. इसके अलावा भी कई साहित्यिक मुद्दे हैं, जिन पर लेखक संगठनों की खामोशी चिंतनीय है. दरअसल अब प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच को आपसी भेदभाव भुलाकर एक नया साहित्यिक–सांस्कृतिक साझा मंच बनाना चाहिए और बदलते समय में लेखकों की समस्याओं पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए. इससे साहित्य और समाज के साथ–साथ साहित्यकारों का भी भला होगा. अगर लेखक संगठन समय के साथ नहीं बदल सके तो समय ही उन्हें किनारे लगा देगा.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

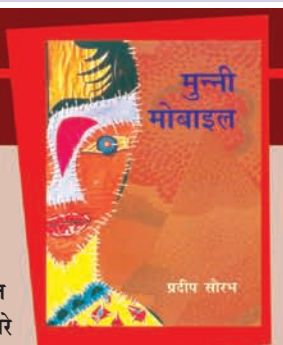

प्रदीप सौरभ

आनंद भारती को अंदर से एक ख़ास तरह का सुकून मिला. जोशी ने उन्हें थूकते देखा तो वह हतप्रभ था. वह भी जब–जब ट्रैफालगर स्क्वायर जाता था तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के भाव आते थे. उसका बस चलता तो वह स्टैचू को तोड़ देता. थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे. अचानक आनंद भारती को लखनऊ की याद आ गई. आजादी के साठ साल बाद भी लखनऊ के लोग हैवलॉक को ढो रहे थे. उसकी याद में लखनऊ में एक रोड है. कई बार लोगों ने रोड का नाम बदलने के लिए निवेदन और आवेदन सरकार से किए, लेकिन किसी के पास समय कहां है औपनिवेशिक जुए को अपने सिर से उतार कर फेंक देने का! सब अपने–अपने धर्म और जाति के लोगों के स्टैचू लगाने में मस्त हैं. लखनऊ शहर जीता–जागता म्यूज़ियम हो गया है. यह बात दीगर है कि अंग्रेजों ने जनरल हैवलॉक की अप्रसांगिकता समझ ली थी. 2003 में लंदन के मेयर केन लिविंगस्टोन ने मूर्ति को हटाने की मुहिम चलाई थी. उनका कहना था कि हमें इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रतीक चिन्ह इस स्क्वायर पर लगाना चाहिए, ताकि नौजवान पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके, लेकिन उनकी मुहिम कामयाब न हुई.

आनंद भारती सोचते हुए सोहो पहुंच चुके थे. सोहो बोले तो रेडलाइट एरिया. लंदन का रंडीखाना. छोटा–मोटा बाज़ार भी है यहां. गलियां पक्की और खुली–खुली हैं. वह चारों ओर नज़र दौड़ा रहे थे कि एक छह फुट के लंबे काले अफ्रीकी आदमी ने उनके पास आकर मुस्कराते हुए गुड ईवनिंग की. चाल–ढाल से वह दलाल लग रहा था. इशारों में उसने दोनों को टटोलने की कोशिश की. आनंद भारती ने भी उसके हर सवाल का सकारात्मक जवाब दिया. वह बोलने लगा, दुनिया के जिस देश की औरत चाहेंगे, हमारे पास है. बोल के तो

देखो. वह उनके साथ चलने लगा. जोशी काले अफ्रीकी से मज़ा लेने लगा. जोशी ने उस काले से इज़रायली औरत की मांग की. उसने अपनी असमर्थता ज़ाहिर कर दी. तिस पर जोशी उससे बोला, अब तुम्हीं बता दो कि तुम्हारे पास कौन से देश की लड़की है. इज़रायली को छोड़कर आप ही बता दें. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां की कहेंगे, पेश कर दूंगा. काले अफ्रीकी ने जोशी से आत्मविश्वास के लहज़े में कहा. सोहो में ओल्ड काम्पटन स्ट्रीट पर चलते हुए एक गे क्लब का बोर्ड चमका. उसके बाहर भी दो हट्टे–कट्टे काले अफ्रीकी पहरा दे रहे थे. शीशे से अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था. अंदर लड़के बियर पीते हुए एक– दूसरे से लपट–झपट रहे थे. शायद संगीत भी बहुत तेज बज रहा था. कुछ लड़के नाच भी रहे थे. दरवाजे बंद होने के चलते संगीत की आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी. दो कच्ची उम्र के लड़के तो एक–दूसरे होंठों में होंठ डाले मस्ती में झूम रहे थे. इस दृश्य को देखने के बाद आनंद भारती ने साथ चल रहे काले अफ्रीकी से पूछा, किसी भी देश के लड़के भी मिल सकते हैं क्या? उसने कहा, यस.

आनंद भारती को सब–कुछ अजीब सा लग रहा था. दिल्ली में भी यह सब होता है, लेकिन लुके–छिपे. समलैंगिकों को साथ रहने के अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ता है. लेकिन यहां सब खुल्लमखुल्ला चल रहा था. दिल्ली में एक गे पार्टी में आनंद भारती जा चुके हैं. हो–हल्ले वाले संगीत के बीच एक फिरंगी उन पर भी फिदा हो गया था. उन्हें आश्चर्य हुआ था कि फिरंगी को एक दढ़ियल आदमी के अंदर क्या दिख रहा है. उस पार्टी में लड़के लिपस्टिक लगाए थे. कुछ तो लड़कियों वाली ड्रेसेज भी पहने हुए थे. नाज–नखरे भी ऐसे कर रहे थे कि बस पूछिए मत. कुछ सुंदर लड़के, जिनकी त्वचा मक्खन की तरह मुलायम थी, दूसरे लड़कों के निशाने पर थे, लेकिन वे आसानी से हाथ नहीं रख रहे थे. उनके दलाल भी थे. वे नमकीन लड़कों के लिए कस्टमरों से लेनदेन की बात कर रहे थे. जलती–बुझती रोशनी के बीच आनंद भारती ने देखा था कि एक लड़के ने अपनी स्कर्ट ऊपर कर रखी थी और पीछे से दूसरा लड़का अपनी जीन्स की चेन खोले हुए उससे चिपटा हुआ था. विचित्र प्यास थी. अजीब दुनिया थी वह.

अगले अंक में जारी...

अतीत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण : राजेंद्र मोहन

मेरे लिए अतीत इसलिए जरूरी है जैसे पेड़ के लिए जड़. जड़ रहित पेड़ खड़ा नहीं रह सकता. संसार में भारत को इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व हासिल है, क्योंकि उसके पास वेदोपनिषद् जैसे ज्ञान के उत्कृष्ट भंडार हैं. वेद तो संसार के प्राचीनतम एवं आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो संसार को सदैव उज्ज्वल दृष्टि प्रदान करते रहे हैं, कहते हैं लेखक एवं साहित्यकार डॉ. राजेंद्र मोहन भटनागर. बकौल डॉ भटनागर, भारत के प्राचीन मूल ग्रंथों–मूर्तियों का विश्व में एक बहुत बड़ा बाज़ार है. दरअसल, हमारी धरोहरों की चोरी की जा रही है यानी हमारे गौरवशाली अतीत को चोरी–छिपे बेचा जा रहा है. बावजूद इसके हम अपने गत को उपेक्षा, अनादर और तटस्थ भाव से देखते हैं. यह जानकर भी कि जिनके पास गौरवशाली गत नहीं है, उन्हें हमारे अतीत की इतनी आवश्यकता है कि वे मोटी क़ीमत देकर चोरी से उसे ख़रीद रहे हैं. क्या यह सब जानकर भारतीयों को अपने अतीत पर गौरव नहीं करना चाहिए? क्या उसका समुचित संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए?

ज़िंदगी का एहसास, संध्या का भोर, सेनानी महाप्रयाण, सारथीपुत्र, ताम्रव्रत एवं रक्तध्वज आदि नाटकों और नारद का मोह, गांधी के तीन बंदर, इनसान बनो, नीलम देश का राजकुमार एवं बूंद–बूंद घट भर जैसी साहित्यिक कृतियों की रचना करने वाले, राजस्थान के मूल निवासी डॉ. राजेंद्र मोहन भटनागर हिंदी साहित्य जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. वह कहते हैं कि आज संसार में भारत का स्थान इसीलिए प्रमुख है, क्योंकि इसका विश्व में सर्वश्रेष्ठ गरिमापूर्ण इतिहास रहा है. यही कारण है कि मैंने भारत के अतीत की जांच–पड़ताल कर उस पर भी उपन्यास लेखन किया. मेरी राय

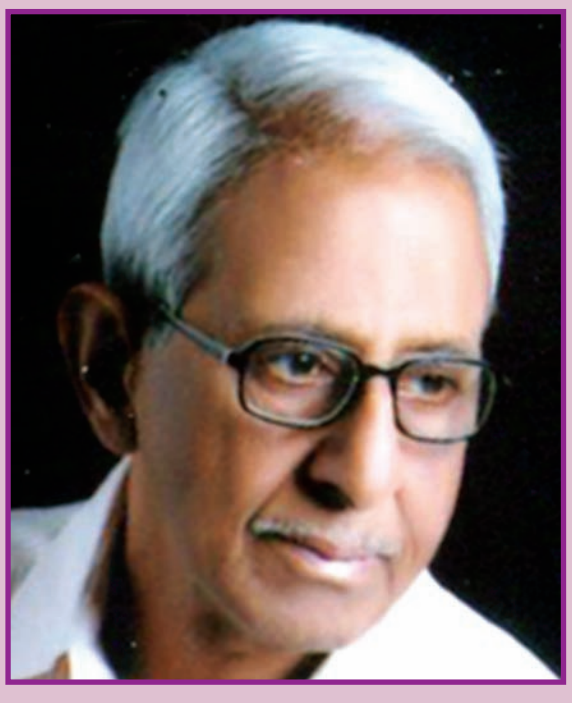

बस यह है कि जिस अतीत के पास अतीत होते हुए भी वर्तमान एवं भविष्य के लिए अथाह अंतरदृष्टि है, उससे पुन: भारत अपनी गरिमापूर्ण स्थिति में सामने आ सकता है और संसार के उत्कृष्ट आज एवं कल के लिए यह बेहतर पथ प्रदर्शक साबित हो सकता है तथा संसार को उच्चतम वर्तमान एवं भविष्य के लिए नूतन और सजग नज़र प्रदान कर सकता है. वजह, वर्तमान संसार जड़ रहित होकर ऐसे चौथे विश्व युद्ध की तैयारी कर बैठा है, जिसके बाद तमाम धरती ही मानव रहित हो जाएगी. उस महाविनाश से इस धरती को बचाने के लिए भी भारत का अतीत ही एकमात्र साधन है. इस दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में बड़ी उम्मीद के साथ मैंने स्वराज्य, विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार पटेल आदि पर उपन्यास लिखे. हाल में सोनिया गांधी पर भी उपन्यास लिखा.

डॉ. भटनागर ने अपने लेखन के ज़रिए इतिहास को वर्तमान और उसकी समस्याओं के निदान से जोड़ने जैसा महत्वपूर्ण काम किया. वह विश्व के पहले ऐसे साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक ही पात्र–एक ही कथा पर अनेक उपन्यास लिखे, जैसे महाराणा प्रताप, मीरा इत्यादि. इनके अब तक 79 उपन्यास, 13 नाटक, 12 कहानी संकलन एवं 17 समीक्षात्मक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं. उनके साहित्य पर अब तक 16 पीएचडी हो चुकी हैं. हाल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रेमचंद और राजेंद्र मोहन भटनागर के नारी पात्र का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक से एक शोधपत्र दाखिल हुआ है. डॉ. भटनागर राजस्थान साहित्य अकादमी के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, महाराणा कुंभ पुरस्कार, हिंदी भूषण सम्मान एवं विद्या वाचस्पति (साहित्य) आदि अनेक सम्मानों–पुरस्कारों के ज़रिए सम्मानित किए जा चुके हैं. इनके लेखन को साहित्य जगत एवं जनसाधारण द्वारा ने सराहा है. इनकी कई कृतियों का अंग्रेजी, फ्रेंच, मराठी, गुजराती एवं कन्नड़ भाषा में अनुवाद हो चुका है. डॉ. भटनागर लगातार लेखनरत हैं और देश एवं समाज के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील भी.

डॉ. वेणु गोपाल कृष्ण
feedback@chauthiduniya.com

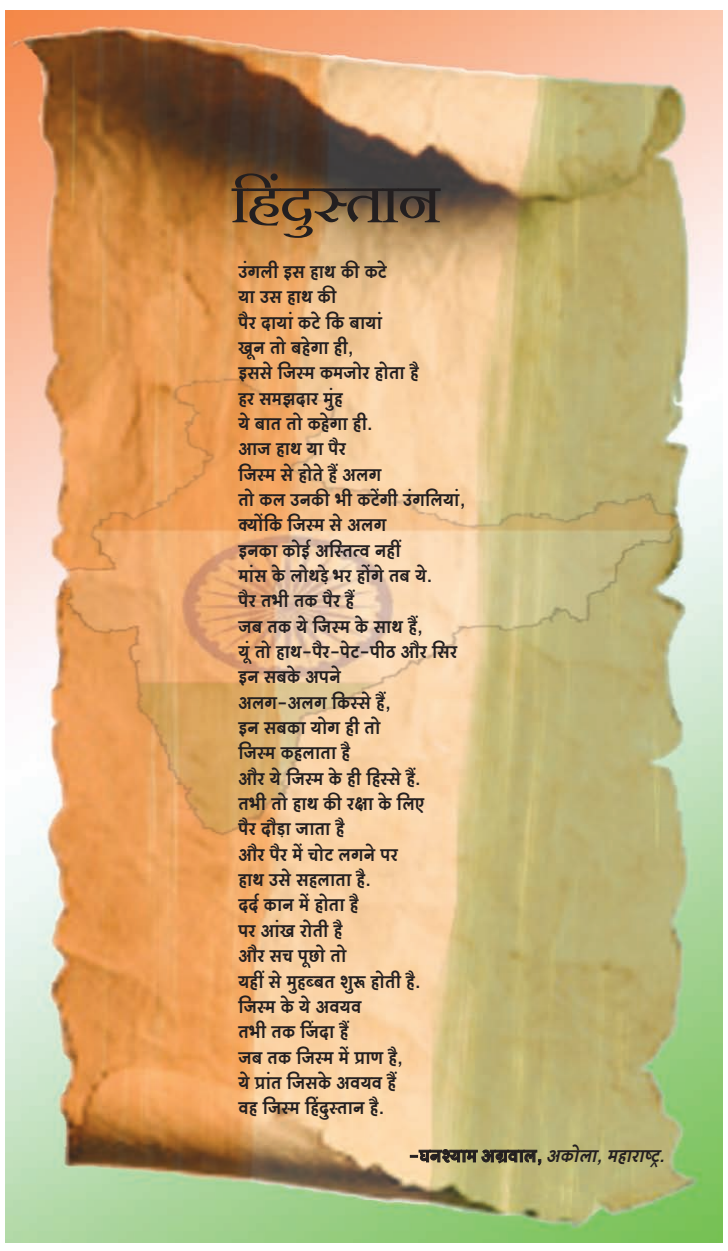

हिंदुस्तान

उंगली इस हाथ की कटे
या उस हाथ की
पैर दायां कटे कि बायां
खून तो बहेगा ही,
इससे जिस्म कमजोर होता है
हर समझदार मुंह
ये बात तो कहेगा ही.
आज हाथ या पैर
जिस्म से होते हैं अलग
तो कल उनकी भी कटेंगी उंगलियां,
क्योंकि जिस्म से अलग
इनका कोई अस्तित्व नहीं
मांस के लोथड़े भर होंगे तब ये.
पैर तभी तक पैर हैं
जब तक ये जिस्म के साथ हैं,
यूं तो हाथ–पैर–पेट–पीठ और सिर
इन सबके अपने
अलग–अलग किस्से हैं,
इन सबका योग ही तो
जिस्म कहलाता है
और ये जिस्म के ही हिस्से हैं.
तभी तो हाथ की रक्षा के लिए
पैर दौड़ा जाता है
और पैर में चोट लगने पर
हाथ उसे सहलाता है.
दर्द कान में होता है
पर आंख रोती है
और सच पूछो तो
यहीं से मुहब्बत शुरू होती है.
जिस्म के ये अवयव
तभी तक जिंदा हैं
जब तक जिस्म में प्राण है,
ये प्रांत जिसके अवयव हैं
वह जिस्म हिंदुस्तान है.

–घनश्याम अग्रवाल, *अकोला, महाराष्ट्र.*

सुधी कलेक्शन के उक्त गहने अंतरराष्ट्रीय डिज़ाइन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.

पैनासोनिक का इकोज कूल अभियान

यह कार्यक्रम दिल्ली और चंडीगढ़ में क्रमश: 14 सितंबर और 7 अक्टूबर को शुरू हुआ और फरवरी 2011 तक चलेगा. प्रथम चरण के तहत 7 स्कूलों में यह कार्यक्रम चलाया गया, जो काफ़ी सफ़ल रहा.

युवाओं को पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए पैनासोनिक ने इकोज कूल नामक एक कार्यक्रम चलाया है. इस कार्यक्रम के तहत देश भर के क़रीब 100 स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण की रक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा. यह कार्यक्रम दिल्ली और चंडीगढ़ में क्रमश: 14 सितंबर और 7 अक्टूबर को शुरू हुआ और फरवरी 2011 तक चलेगा. प्रथम चरण के तहत 7 स्कूलों में यह कार्यक्रम चलाया गया, जो काफ़ी सफ़ल रहा. पैनासोनिक इंडिया के निदेशक (ऑपरेशंस एंड प्लानिंग) अर्जुन बालकृष्णन कहते हैं कि यह प्रयास उन तमाम प्रयासों में से एक है, जिन्हें पैनासोनिक ने विश्व स्तर पर ग्रो गीन वादे के तहत चला रखा है. हम उम्मीद करते हैं कि लोगों में पर्यावरण के मुद्दे पर समझ विकसित होगी और युवा इसे काफ़ी मनोरंजनपूर्ण तरीक़े से सीखेंगे. कार्यक्रम के तहत बच्चों को उनके नियत पाठ्यक्रम से समय निकाल कर एक घंटे लंबे सेशन में ले जाया जाता है, जिसमें उन्हें पर्यावरण से संबंधित जानकारी दी जाती है और यह सिखाया जाता है कि उनके प्रयास से पर्यावरण में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें जीवनपर्यंत चलने वाली शिक्षा मिलती है. यही कारण है कि पैनासोनिक ने इसके लिए 9 से 12 साल तक के बच्चों का चयन किया है.

कार्यक्रम के तहत पहले चरण में छात्रों और उनके माता–पिता को शामिल किया जा रहा है. इसके बाद प्रमोटर लाए जाएंगे, जो बच्चों में इसके प्रति रुचि जगाएंगे. पैनासोनिक ने इसके लिए बच्चों को बैज और सर्टिफिकेट भी देने की योजना बनाई है, जिससे वे हरियाली और जीवन बचाने के इस काम को अधिक सहजता और गर्व की भावना के साथ पूरा करें. उनमें जोश जगाने के लिए उनके नाम के साथ एक ग्रेफिटी वाल भी बनाई जाएगी, जो उन्हें पर्यावरण बचाने की प्रेरणा देगी. इसके अलावा छात्रों को इको स्कूल ज्वाइन करने के लिए भी कहा गया है, जो फेसबुक की एक कम्युनिटी है. इस अवसर पर गुरुशरन स्कूल में ग्रेड 5 की छात्रा नव्या ने बताया कि वह फेसबुक पर इकोज कूल क्लब ज्वाइन करके बेहद उत्साहित है. वह इस सेशन को काफ़ी पसंद कर रही है, क्योंकि इसके माध्यम से वह पर्यावरण के प्रति अधिक ज़िम्मेदार बन रही है. वह लगातार इस कार्यक्रम का आनंद ले रही है. स्प्रिंगडेल्स स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा गेरवित सचदेवा ने बताया कि वह बहुत खुश है कि उसे इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौक़ा मिला. कार्यक्रम के ज़रिए उसने कई समस्याओं के बारे में जाना, जिनका आज धरती सामना कर रही है. उक्त सारी समस्याएं हमारी अनदेखी के कारण हुई हैं. कालका स्कूल की प्रिंसिपल ओनिका मल्होत्रा कहती हैं कि पैनासोनिक एक ऐसा संगठन है, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है और पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैला रहा है. स्प्रिंगडेल्स स्कूल की संचालिका सोमा बनर्जी ने बताया कि उनके यहां के बच्चे पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक हैं. मौजूदा पर्यावरण और वैश्विक समस्याओं के प्रति जागरूकता के लिए पैनासोनिक समूह के प्रयास से बच्चों के अंदर जिज्ञासा विकसित हुई है.

प्रियजनों को दें ख़ास उपहार

हिंदू धर्म में शादी–ब्याह और त्योहारों के पावन अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को विशेष स्थान दिया जाता है. दीपावली के पर्व पर घर में सुख–शांति के लिए भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है. शादी–ब्याह के अवसर पर कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न होने की कामना के साथ भगवान गणेश की पूजा होती है. कहते हैं कि किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले यदि गणेश जी की पूजा की जाए या उनका नाम लिया जाए तो उस कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता. अपने जीवन को मुश्किलों से दूर रखने और विघ्नहर्ता को अपने जीवन में शामिल करने के लिए कई लोग उनके आकार का लॉकेट पहनते हैं. इसी बात को ध्यान में रखकर द डायमंड डेस्टिनेशन ने विघ्नहर्ता गणेश जी के अलग–अलग अवतारों का संग्रह बाज़ार में उतारा है. त्योहारों और शादियों के इस मौसम में न सिर्फ़ आप इसे अपने क़रीबियों को बतौर तोहफ़ा दे सकते हैं, बल्कि ख़ुद के लिए भी ख़रीद सकते हैं.

यह संग्रह शांति, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करेगा. ओरा के विघ्नहर्ता गणेश संग्रह में आध्यात्मिक पेंडेंट की एक पूरी सीरीज है. इसमें भगवान गणेश के आठ अवतारों को शामिल किया गया है. 22 कैरेट सोने और प्लेटिनम वाले इन पेंडेंट में भगवान गणेश के वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, लंबोदर, विकट, विघ्नराजा, धूम्रवर्ण एवं गजानन नामक आठ अवतारों को ख़ूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया है. इन पेंडेंट को माणिक, पन्ना, मोती और बेल्जियम में पाए जाने वाले असली हीरों के मेल से तैयार किया गया है.

इसके साथ ही इन्हें आध्यात्मिक महत्व वाले रुद्राक्ष, मूंगा और पवित्र नवरत्न जैसे पत्थरों से सजाया गया है. ओरा ने इन्हें काफ़ी स्टाइलिश तरीक़े से गढ़ा है. यह युवाओं को भी आकर्षित करने में सक्षम हैं. ओरा हर वर्ष नए आध्यात्मिक संग्रह पेश करता है. उसका प्रत्येक संग्रह पूरी गहराई के साथ धार्मिक महत्व से जुड़ा है. वह इससे पहले नवग्रह, सूर्य शक्ति, पंचरत्न, सिद्धिदाता एवं स्वयंभू जैसे संग्रह जारी कर चुका है. विघ्नहर्ता गणेश संग्रह के पेंडेंट देश भर में मौजूद ओरा के सभी बुटीक पर उपलब्ध हैं. इनकी क़ीमत 9300 रुपये से शुरू होती है.

फंसकूल का नया गेम एजेंट नॉस

एक भी ग़लत क़दम आपको हार का मुंह दिखा सकता है. प्लेयर का यह रोल है कि वह इन एजेंटों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा.

छोटे बच्चों और संपूर्ण परिवार की ज़रूरत का सामान बनाने वाली कंपनी फंसकूल ने अपना नया गेम नॉस एजेंट के नाम से बाज़ार में उतारा है. यह आईआईटी मुंबई की पार्टनरशिप में बनाया गया है. गेम की थीम द्वितीय विश्वयुद्ध है. इसे दो से चार लोगों द्वारा खेला जाता है. इसमें चार एजेंट हैं, जिन्हें हेड क्वार्टर तक पहुंचना है, लेकिन कुछ सीमित साधनों द्वारा. एक भी ग़लत क़दम आपको हार का मुंह दिखा सकता है. प्लेयर का यह रोल है कि वह इन एजेंटों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा. जो प्लेयर या टीम हेड क्वार्टर तक पहुंचने में पहले क़ामयाब होगा, वही विनर कहलाएगा. इसमें चार कोनों पर स्टार्ट्स, मिसटर्न, फ्रीटर्न, कैफे, स्कूल और बीचोबीच हेड क्वार्टर जैसे स्थान हैं. यह गेम आठ साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है और इसकी क़ीमत है 499 रुपये.

सोने के गहनों का नया कलेक्शन

कला और परंपरा को संजोकर रखने के लिए सुधी कलेक्शन ने सोने के गहनों का नया कलेक्शन पेश किया है. ख़ास बात यह है कि इसे हर आयु वर्ग को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है. दीपावली के साथ–साथ शादी का मौसम भी चल रहा है. गीतांजली ने एमएमटीसी के सौजन्य से यह कलेक्शन पेश किया है. इस मौक़े पर अभिनेत्री रायमा सेन भी उपस्थित थीं. सुधी कलेक्शन के उक्त गहने अंतरराष्ट्रीय डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इनमें भारतीय कला–शिल्प की झलक भी मिलती है. इस कलेक्शन में गले की चेन, चॉकर, नेकलेस, टॉप्स, रिंग, चूड़ियां एवं ब्रेसलेट के साथ–साथ गहनों के फूल सेट भी शामिल हैं. इनमें हीरा, रूबी एवं पन्ना के अलावा कई अन्य बेशक़ीमती पत्थर लगे हैं. उक्त गहने अंतरराष्ट्रीय डायमंड टेस्टिंग लैब के मानकों पर भी ख़रे उतरते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

द संडे के खुलासे के बाद बीसीसीआई और आईसीसी ने भी यही बात कही थी कि रैना पर किसी तरह का संदेह नहीं है.

सच्चाई नहीं, यह साज़िश है

आदित्य पूजन

पिछले दिनों इंग्लैंड के अख़बार द संडे के एक खुलासे ने भारत ही नहीं, विश्व क्रिकेट में हलचल मचा दी. द संडे ने भारतीय टीम के पिछले श्रीलंका दौरे का ज़िक्र करते हुए यह बताया था कि युवा भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना एक ऐसी महिला के साथ जुड़े हैं, जिसके सटोरियों के साथ नज़दीकी रिश्ते हैं. अख़बार ने यह दावा भी किया था कि होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों ने रैना को उक्त महिला के साथ एक से ज़्यादा बार कैद किया और श्रीलंकाई बोर्ड ने इस बाबत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) एवं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपनी रिपोर्ट भी भेजी थी. द संडे के इस रहस्योद्घाटन के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में मानो भूचाल आ गया. एकबारगी ऐसा लगा, जैसे मैच फिक्सिंग का भूत भारतीय क्रिकेट को कहीं एक बार फिर न अपनी आगोश में ले ले. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि द संडे के इस खुलासे में कोई सच्चाई नहीं है. चौथी दुनिया ने इस मामले की गहन जांच-पड़ताल की और इससे यही बात उभर कर सामने आई कि रैना के साथ देखी गई महिला साफ-सुथरी छवि की है और उसके किसी सट्टेबाज़ से संबंध नहीं हैं. हमारी जांच से यह भी साबित होता है कि ब्रिटिश अख़बार का यह सनसनीखेज खुलासा भारतीय क्रिकेट को बदनाम करने की एक साज़िश है. द संडे के खुलासे के बाद बीसीसीआई और आईसीसी ने भी यही बात कही थी कि रैना पर किसी तरह का संदेह नहीं है. आईसीसी ने द संडे के इस दावे से भी इंकार किया कि उसकी भ्रष्टाचार रोधी इकाई रैना के ख़िलाफ़ जांच-पड़ताल कर रही है. वहीं, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एक बयान जारी कर कहा कि कैमरे में जिस महिला के साथ उन्हें दिखाया गया है, वह और कोई नहीं, बल्कि उनकी मार्केटिंग एजेंट है. बोर्ड ने इस संबंध में श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड से मिली किसी रिपोर्ट की ख़बर को भी सिरे से खारिज कर दिया. आईसीसी और बीसीसीआई के इस इंकार के बाद इंग्लैंड के अख़बार के दावों की असलियत उजागर हो गई. विदेशी मीडिया किस तरह उपमहाद्वीप की टीमों और खिलाड़ियों को बदनाम करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाता है, यह बात भी पूरी तरह स्पष्ट हो गई.

रैना भारत की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों में सबसे प्रतिभाशाली माने जाते हैं. हाल के दिनों में उनकी बल्लेबाज़ी ने कई मुक़ाबलों में टीम के लिए जीत का रास्ता तैयार किया है. क्रिकेट प्रशंसकों को भविष्य में उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, कई लोग उन्हें भविष्य का कप्तान भी मानते हैं. हाल के दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. टेस्ट मैचों में वह लगातार नौ सीरीज़ों में अपराजेय रही है और आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर है. वनडे मैचों में भी टीम शीर्ष की तीन टीमों में शामिल है. विदेशी, खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को यह बात पच नहीं रही है. इसीलिए वह भारतीय क्रिकेट को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहा है. चौथी दुनिया की जांच-पड़ताल से भी यही बात साबित होती है कि रैना को निशाने पर लेने का एकमात्र मक़सद इस युवा खिलाड़ी को परेशान करना और भारतीय टीम को अस्थिर करना है.

विदेशी मीडिया ही नहीं, विदेशी क्रिकेट बोर्ड भी उपमहाद्वीप की क्रिकेट टीमों को बदनाम करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं. क्रिकेट के मैदान पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि एशियाई टीमों के खिलाड़ी नाहक ही बदनाम हो जाते हैं. माइक डेनिस प्रकरण ने क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर तक को नहीं बख्शा. ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी विपक्षी टीम के ख़िलाफ़ स्लेजिंग करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन कभी किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को इसके लिए सज़ा नहीं मिलती. पर जैसे ही कोई एशियाई खिलाड़ी उनकी बातों का जवाब देता है तो आईसीसी की भौहें तन जाती हैं. मंकीगेट प्रकरण में हरभजन सिंह के साथ ऐसा ही हुआ था. एक और उदाहरण मुथैया मुरलीधरन का है. विदेशी खिलाड़ी उनकी फिरकी गेंदों को नहीं समझ पाए तो उन्हें चकर घोषित कर दिया. यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड ने भी उन्हें चकर कहने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की. अब यह बात और है कि मुरलीधरन के हाथों की बनावट ही ऐसी है कि गेंद फेंकते समय उनकी कलाइयां मुड़ जाती हैं. हालात ऐसे हो गए कि आईसीसी को नियम में बदलाव करना पड़ा, तब जाकर मुरली का करियर आगे बढ़ पाया, वरना विदेशी टीमों ने तो उनका करियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. हाल के सालों में एशियाई उपमहाद्वीप में क्रिकेट के बाज़ार का जिस तरह विस्तार हुआ है, उसके बाद से स्थितियां थोड़ी बदली ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपनी नापाक कोशिशों से बाज नहीं आते. सुरेश रैना की महिला एजेंट को सटोरियों का साथी बताना भी ऐसी ही एक कोशिश है. इसका एकमात्र उद्देश्य इस युवा खिलाड़ी की सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा करना है और भारतीय क्रिकेट को बदनाम करना है. हालांकि अब वह समय आ चुका है कि विदेशी मीडिया और टीमें अपनी ऐसी कोशिशों को लगाम दें. एशियाई उपमहाद्वीप में क्रिकेट एक धर्म का रूप ले चुका है और प्रशंसक अपने खिलाड़ियों को भगवान की तरह पूजते हैं. अपनी भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ वे अब शायद ही बर्दाश्त करें.

aditya@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 15,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 50,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 08 नवंबर–14 नवंबर 2010

विवाह जैसी फिल्म में सीधी-सादी लड़की का किरदार निभाकर वाहवाही लूटने वाली अमृता ने कुछ दिनों पहले अपना मेकओवर कराया था.

देर आए दुरुस्त आए

कुछ दिनों से फिल्मी पर्दे से लगभग ग़ायब अमृता राव जल्द ही फिल्म जाने कहां से आई है में नज़र आने वाली हैं. इसमें अमृता ने अतिथि भूमिका निभाई है. फिल्मों से ग़ायब होने की वजह उनका नया मेकओवर था. विवाह जैसी फिल्म में सीधी-सादी लड़की का किरदार निभाकर वाहवाही लूटने वाली अमृता ने कुछ दिनों पहले अपना मेकओवर कराया था, जिससे निर्माता-निर्देशकों ने उन्हें घास डालना बंद कर दिया था. अमृता अपनी पहचान एक हॉट एंड सेक्सी अभिनेत्री के रूप में बनाना चाहती हैं. इसके लिए उन्होंने शॉर्टकट द कनेक्शन इज ऑन और माई नेम इज एंथनी गोनसाल्विस में काफी ग्लैमरस रोल भी किया, कई फिल्म पत्रिकाओं के लिए बोल्ड फोटो शूट भी कराए, पर उन्हें मायूसी हाथ लगी. अमृता के नए अवतार से निर्माता-निर्देशक असमंजस में पड़ गए. सीधी-सादी भारतीय लड़की के किरदार के लिए परफेक्ट मानी जाने वाली अमृता सेक्सी और हॉट अभिनेत्रियों की जमात में खड़ी हो गई थीं. निर्माता-निर्देशकों के पास पहले से ही बिपाशा और मल्लिका जैसी अभिनेत्रियों का विकल्प था तो वे अमृता को भला क्यों लेते? लेकिन अब मैडम अमृता को अक्ल आ गई है कि उन पर भड़काऊ नहीं, बल्कि भारतीय पोशाक ही जंचती है. अब फिर से अमृता अपने पुराने परिधानों में दिखने लगी हैं. उन्होंने अपना लुक चेंज कर लिया है.

निर्माता-निर्देशक -2

उदारीकरण, अंडरवर्ल्ड और लालच की मार

कल का निर्माता-निर्देशक, जो कभी अभिनेताओं को अपने इशारों पर नचाता था, आज उन्हीं के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर है. इसी मुद्दे पर पिछले अंक में लिखा गया कि काले धन और तकनीक की वजह से भी निर्माता-निर्देशकों की भूमिका सिमटती चली गई और अभिनेताओं का रोल लंबा और लंबा होता गया. दरअसल, यहां मामला सिर्फ़ काले धन और विकसित तकनीक का नहीं है. नब्बे का दशक याद कीजिए, मल्टीनेशनल कंपनियों का आना अभी शुरू ही हुआ था, उसी दौर में फिल्म डीडीएलजे आती है. बॉलीवुड की प्रेम कहानी अचानक लंदन पहुंच जाती है. उसी दौर में भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित होती है. अचानक यूरोप और अमेरिका को भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार नज़र आने लगता है. केबल टीवी चैनलों की संख्या बढ़ने लगती है. फिल्मों की स्क्रिप्ट न सिर्फ़ भारतीयों, बल्कि प्रवासी भारतीयों को ध्यान में रखकर लिखी जाने लगी. इस तरह फिल्मों से सबसे पहले जो चीज ग़ायब हुई, वह कहानी थी. फिल्मों का सृजनात्मक पक्ष खो गया और यहीं से एक संवेदनशील निर्देशक की ज़रूरत कम होती गई.

आने वाले वक़्त में उदारीकरण और बॉलीवुड का रिश्ता क्या होगा, इसे सबसे पहले बिग बी ने समझा और एबीसीएल नाम से एक कंपनी बना डाली. यह एक नायक का नया अवतार था. नए जमाने में नायक के निर्माता बनने की शुरुआत हुई. यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है. शाहरुख़ की रेड चिली, पूजा भट्ट, आमिर ख़ान, अनिल कपूर, सलमान, अजय और अक्षय से लेकर जॉन अब्राहम तक, सबका ख़ुद का प्रोडक्शन हाउस है. ये सब ख़ुद का पैसा लगाते हैं, ख़ुद फिल्मों में काम करते हैं, फिर भाई या दोस्त से या ख़ुद ही फिल्म भी निर्देशित कर लेते हैं. यानी बॉलीवुड माने विशुद्ध पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ज़ाहिर है, जब पैसा अभिनेता का होगा तो निर्देशक को भी वही करना होगा, जो अभिनेता चाहेगा. एक और वजह है, जिसने निर्माता-निर्देशकों के पर कतरने में खलनायक की भूमिका निभाई यानी अंडरवर्ल्ड. जबसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगना शुरू हुआ, तभी से अभिनेता-अंडरवर्ल्ड का गठजोड़ भी बना. यह इतना मज़बूत जोड़ था कि इंडस्ट्री के जाने-माने नाम डॉन का जन्मदिन मनाने दुबई पहुंच जाते थे और इसका ख़ामियाजा भुगतना पड़ा बेचारे निर्माता-निर्देशक को. मशहूर निर्माता-निर्देशक राजीव राय को तो अपना देश तक छोड़ना पड़ा. राकेश रोशन अंडरवर्ल्ड के हमले में बच गए, लेकिन गुलशन कुमार इतने ख़ुशनसीब नहीं थे. मोनिका बेदी जैसी औसत से भी कम प्रतिभाशाली अभिनेत्री को आख़िर क्यों बड़े-बड़े अभिनेताओं के साथ एक के बाद एक फिल्में मिलती गईं?

एक और उदाहरण याद आता है. सर्वकालिक महान फिल्म मुगल-ए-आज़म को बनाने में के आसिफ को क़रीब 16 साल लग गए. आज के दौर में भी एक अच्छे निर्देशक हैं प्रियदर्शन. कभी साल में एक फिल्म बनाते थे. गर्दिश और सजा-ए-काला पानी जैसी संजीदा फिल्में. अब साल में उनकी दो से पांच फिल्में आती हैं और वह भी एक ही तरह की. इसे आप क्या कहेंगे? बाज़ार का दबाव या बाज़ार के मोहरे अभिनेताओं की ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और प्रचार पाने की होड़ का नतीजा. फिल्मों से होने वाली मोटी कमाई को देखते हुए देश-विदेश के औद्योगिक घरानों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय फिल्म कंपनियां बॉलीवुड में कूद चुकी हैं. इनमें सहारा, रिलायंस, फॉक्स, सोनी पिक्चर्स एवं वॉर्नर ब्रदर्स जैसे दिग्गज शामिल हैं. इनके लिए फिल्में सृजनात्मकता का माध्यम नहीं, बल्कि एक उत्पाद बन गई हैं. एक ऐसा उत्पाद, जिससे ढेर सारी कमाई की जा सके, चाहे जैसे भी हो. विदेशों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, म्यूज़िक राइट्स सब कुछ इन्हीं के पास होता है. इन्हें ऐसे निर्देशक चाहिए, जो चट मंगनी-पट ब्याह की तर्ज पर इनके लिए फिल्म बना सकें. ज़ाहिर है, ऐसे माहौल में किसी अच्छे निर्देशक से भी अच्छी फिल्म की आशा करना सरासर बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है.

शशिशेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

कहीं देर न हो जाए

भूलभुलैया के बाद फिल्मों से लगभग ग़ायब अमीषा की जल्द ही दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनसे उन्हें काफी उम्मीदें हैं. उनकी फिल्में रन भोला रन और चतुर सिंह टू स्टार रिलीज होने को तैयार हैं. इसके अलावा उनकी दो अन्य फिल्में पावर और राजधानी एक्सप्रेस भी नए साल की शुरुआत तक रिलीज होंगी. कहो ना प्यार है से अपनी शुरुआत करने वाली अमीषा ने कई हिट फिल्में दी हैं. यह माना जाने लगा था कि वह भविष्य में बॉलीवुड की स्थापित अभिनेत्रियों में शुमार होंगी, पर कुछ हिट फिल्मों के बाद उनके करियर को ग्रहण लग गया. बहुत कम लोग जानते हैं कि अमीषा जाने-माने बैरिस्टर एवं राजनेता रजनी पटेल की पोती हैं. अमीषा अर्थशास्त्र में गोल्डमेडलिस्ट हैं. भारत आने के बाद उन्होंने सत्यदेव दुबे का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया. यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई. 2002 में फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे के दौरान उनकी मुलाक़ात फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट से हुई. दोनों अपने अफेयर को लेकर काफी चर्चित रहे.

फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई यह है कि यहां रिश्ते रोज बनते हैं और रोज बिगड़ते हैं. दोनों ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है. इसके बाद अमीषा कनव पुरी के साथ नजर आईं और फिर कनव से अपने रिश्ते तोड़ने के बाद अमीषा बोलीं कि वह अब अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं. अपने करियर का सुनहरा दौर बेकार के कामों में बर्बाद कर चुकी अमीषा को कौन समझाए कि इस बढ़ती उम्र में उन्हें अब सिर्फ़ आंटी, दीदी या भाभी का रोल ही मिल सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

गुज़ारिश

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म गुजारिश की कहानी जादूगर इथान (रितिक रोशन) और नर्स सोफी डिसूजा (ऐश्वर्या राय) के इर्द-गिर्द घूमती है. जादूगर इथान पैरालाइसिस की बीमारी से जूझ रहे हैं. जादू दिखाने के दौरान गलत ट्रिक प्रयोग करने से इथान पैरालाइज्ड हो जाते हैं. इथान का पूरा दिन व्हील चेयर पर गुजरता है. वह हर काम के लिए सोफिया पर निर्भर हैं. वह अपने हाथ-पैर भी नहीं हिला सकते. उसके मन बहलाव के दो ही साधन हैं, रेडियो शो और खूबसूरत नर्स सोफिया. सोफिया अपने पति को एक एक्सीडेंट में खो चुकी है.14 सालों से पैरालाइज्ड इथान को लगने लगता है कि उसकी जिंदगी बोझ है. वह फैसला करता है कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा. वह आत्महत्या की योजना बनाता है, लेकिन मरने से पहले वह अपनी जादूगरी विद्या किसी योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता है. इसके लिए वह उमर सिद्दीकी (आदित्य राय कपूर) को अपना शिष्य बनाता है. बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली का नाम बेहतरीन पिक्चराइजेशन के लिए जाना जाता है. शादी से पहले ऐश्वर्या संजय लीला भंसाली के

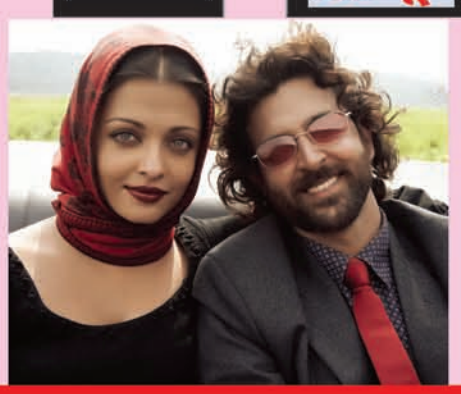

साथ फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास में काम कर चुकी हैं. ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहीं. वहीं रितिक के साथ भी ऐश्वर्या फिल्म धूम-2 और जोधा अकबर में काम कर चुकी हैं. अब देखना यह है कि फिल्म गुजारिश में दर्शकों को इन दोनों की जोड़ी कितनी पसंद आती है. ऐश्वर्या अपनी हालिया रिलीज फिल्मों रोबोट और एक्शन रीप्ले में बढ़ती उम्र के बावजूद बेहतरीन अभिनय करके अभी भी नंबर वन की दौड़ में शामिल हैं. रोबोट में जहां वह अपने ग्लैमरस लुक में बेहद खूबसूरत नजर आईं, वहीं एक्शन रीप्ले में 70 के दशक के मेकअप और फैशन ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए. फिल्म गुजारिश में वह एक ईसाई महिला की पोशाक और मेकअप में नजर आएंगी. फिल्म को प्रोड्यूस किया है रॉनी स्क्रूवाला ने. संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली, ए एम तुराज एवं विधु पुरी. मुख्य भूमिका में हैं रितिक रोशन, ऐश्वर्या राय, आदित्य कपूर, मोनी कंगना दत्ता, रजत कपूर, शेरनाज पटेल, संजय लाफोंट एवं नफीसा अली. यह फिल्म आगामी 19 नवंबर को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 08 नवंबर–14 नवंबर 2010

www.chauthiduniya.com

जनता के संकेत को समझें

शुक्रिया बिहार की जनता, क्योंकि आपने माओवादियों की बुलेट का जवाब बैलेट से दिया, उनकी धमकी को आपने सिरे से ख़ारिज़ कर दिया. साबित हो गया कि बिहार में माओवादियों के पास कोई ज़मीनी आधार नहीं है. उनके पास आम जनता का समर्थन नहीं है. आपने उन्हें संकेत दे दिया है कि लोकतंत्र में हथियार के ज़ोर पर सत्ता नहीं मिलती और न ही विनाश के रास्ते पर चलकर विकास का सपना देखा जा सकता है.

शशि शेखर

बिहार में दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव ऐसे क्षेत्रों में था, जो माओवादियों के प्रभाव वाले माने जाते हैं. पोस्टर एवं पर्चों के ज़रिए माओवादी पहले से ही आम मतदाता को मतदान केंद्र तक न पहुंचने की धमकी दे चुके थे. दूसरे चरण के चुनाव के ठीक दो दिन पहले शिवहर ज़िले के श्यामपुर भटहा में माओवादियों ने एक पुल पर विस्फोट कर पुलिस जीप को उड़ा दिया. इस हमले में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. ऐन मतदान के दिन सीतामढ़ी में नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी के कुछ सदस्यों को अगवा कर लिया, लेकिन माओवादियों की इस पूरी कवायद का नतीजा क्या निकला? दूसरे चरण में लगभग 53 फ़ीसदी मतदाताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर ही लिया. वहीं तीसरे चरण के मतदान में भी मतदाताओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 54 फ़ीसदी मतदाताओं ने मतदान केंद्रों तक पहुंच कर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया. ग़ौरतलब है कि मतदान का यह प्रतिशत पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से कहीं ज़्यादा रहा. 2005 के अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में जहां सिर्फ़ 47.36 फ़ीसदी ही मतदान हुआ था, वहीं इस बार यह प्रतिशत 53 से 54 तक जा पहुंचा. दूसरी ओर 2009 के लोकसभा चुनाव में महज़ 43.74 फ़ीसदी वोट ही पड़े थे. इस तरह देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुक़ाबले इस विधानसभा चुनाव में लगभग 10 फ़ीसदी अधिक वोट ईवीएम में क़ैद हुए. ज़ाहिर है, वोटों के इस बढ़ते प्रतिशत ने बहुत कुछ साफ़ कर दिया है. बिहार के जागरूक मतदाताओं ने माओवादियों की धमकियों, अपीलों और बुलेट की आवाज़ को बैलेट की ताक़त के आगे कमज़ोर साबित कर दिया.

चंपारण की मधुबन सीट पर भी मतदान शांतिपूर्ण रहा. यह वहीं मधुबन है जहां कुछ साल पहले माओवादियों ने दिनदहाड़े एक सांसद के घर, पुलिस थाना, बैंक और पूरे बाज़ार पर एक साथ हमला बोल दिया था. 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पुलिस और माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई थी.

दरअसल, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के दौरान लगभग 54 फ़ीसदी मतदान करके बिहार की जनता ने माओवादियों को एक संदेश दे दिया है. इस संदेश का अर्थ है कि अब माओवादी यह अच्छी तरह समझ लें कि लोकतंत्र में सत्ता बंदूक़ की नली से नहीं निकलने वाली और न वह सिर्फ़ ग़रीबों के नाम पर ग़रीबों का ही ख़ून बहाने से मिलने वाली है. ग़रीबों की बात करने वाले माओवादियों ने अगर सबसे ज़्यादा किसी का ख़ून बहाया है तो वह ग़रीबों का ही ख़ून है. तो क्या माओवादी जनता के इस संदेश को समझेंगे कि लोकतंत्र में लोक कल्याण सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकतंत्र में भागीदारी से ही संभव है? बिहार में पिछले पांच सालों के दौरान बनी सड़कों ने वहां की जनता में विकास के साथ–साथ विकास की आस भी जगाई है. बेरोज़गार युवाओं द्वारा ग़लत राह पर क़दम रखना एक आम बात है, लेकिन इन पांच सालों में हज़ारों बेरोज़गारों को सरकारी नौकरियां मिलीं. बिहार के लोगों को सालों बाद विकास दिखा है और वे इस माहौल को माओवादियों की धमकियों से डरकर बर्बाद नहीं करना चाहते. इसी का नतीजा है कि माओवादियों की तमाम धमकियों–अपीलों की परवाह किए बग़ैर जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की.

उत्तरी बिहार के चंपारण, मुज़फ़्फ़रपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे इलाक़ों, जो ख़ुद माओवादियों के मुताबिक़ उनके गढ़ हैं, में मतदान के दौरान लंबी–लंबी कतारों में सुबह से खड़ी महिलाएं, युवा एवं बुज़ुर्ग जिस उत्साह से वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते नज़र आए, वह क़ाबिले तारीफ़ है. मतदान के दौरान माओवादियों की धमकी का कोई असर देखने को नहीं मिला. शिवहर, जहां मतदान से दो दिन पहले माओवादियों ने 6 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, वहां भी मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई. शिवहर और सीतामढ़ी के मतदाताओं ने माओवादियों की चुनाव बहिष्कार की अपील को सिरे से ख़ारिज़ कर दिया. चंपारण की मधुबन सीट पर भी मतदान शांतिपूर्ण रहा. यह वहीं मधुबन है जहां कुछ साल पहले माओवादियों ने दिनदहाड़े एक सांसद के घर, पुलिस थाना, बैंक और पूरे बाज़ार पर एक साथ हमला बोल दिया था. 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पुलिस और माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई थी.

दरअसल, बिहार के इन ज़िलों में माओवादियों के पनपने के पीछे एक कारण यह भी है कि इन ज़िलों का ज़्यादातर हिस्सा नेपाल की सीमा से सटा है. चंपारण और सीतामढ़ी की सीमाएं नेपाल के वीरगंज एवं जनकपुर से जुड़ी हैं. सालों से यह रिपोर्ट आती रही है कि नेपाल के माओवादियों से बिहार के माओवादियों को सहायता मिल रही है. धन से लेकर हथियारों तक की सहायता. रणनीति बनाने में भी बिहार के माओवादी नेपाली माओवादियों से सलाह लेते हैं. इसके अलावा नेपाल के जंगलों में भी बिहार के माओवादियों को पनाह मिलती रहती है. इन्हीं सब कारणों से पिछले एक दशक के दौरान बिहार के इन क्षेत्रों में माओवादियों की गतिविधियां बढ़ गईं. शुरुआत में न तो लालू यादव और न ही नीतीश कुमार की सरकार ने इस ओर ध्यान दिया. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रुख़ इस समस्या पर लगभग एक जैसा ही रहा और अब भी कमोबेश वही रवैया है.

लेकिन धन्यवाद देना चाहिए बिहार की जनता को. जिस तरह से मतदान के ज़रिए उसने माओवादियों की खोखली ताक़त को बेनक़ाब किया है, वह बिहार और भारत में माओवाद के भविष्य की तरफ़ भी इशारा करती है. बिहार की जनता ने साफ़ कर दिया है कि पशुपति से तिरुपति तक लाल गलियारा बना पाना माओवादियों के लिए महज़ एक सपना बनकर रह जाएगा. कम से कम इस गलियारे का रास्ता बिहार से होकर तो बिल्कुल नहीं गुज़रेगा.

shashishekhar@chauthiduniya.com

दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत

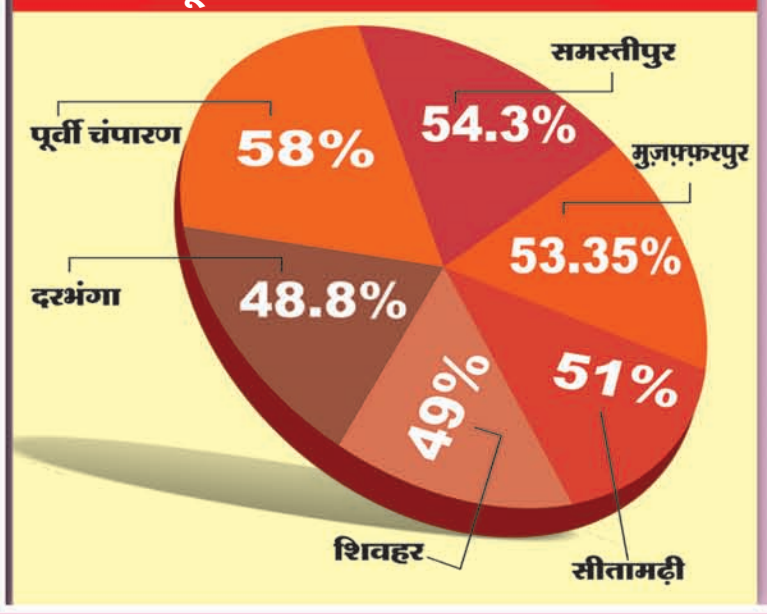

माओवादियों के प्रभाव वाले क्षेत्र

शिवहर, रीगा, बथनाहा, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, दरभंगा, हायाघाट, सकरा, कुढ़नी, मुजफ़्फ़रपुर, कांटी, वरूराज, कल्याणपुर, नरकटिया, पिपरा, मधुबन, चिरैया, ढाका, मीनापुर, पारू, साहेबगंज, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, मोतिहारी, महनार, वाल्मीकि नगर एवं रामनगर.

(दूसरे–तीसरे चरण के दौरान इन्हीं क्षेत्रों में हुए मतदान)

नवादा विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने पिछले चुनाव में निर्दलीय रूप से लड़कर विधायक बनी पूर्णिमा यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है.

राजकुमार प्रसाद उर्फ़ राजू वर्णवाल और कांग्रेस से गया नगर निगम के डिप्टी मेयर ओंकार नाथ के आने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है.

चौथी दुनिया

चुनावी तड़का

सुशासन की बोलती बंद

बिहार की चुनावी जंग का एक नज़ारा ऐसा भी है, जो घर का भेदी लंका ढाए को चरितार्थ कर रहा है. राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार अपने-अपने पक्ष में माहौल बनाने और विरोधियों की पोल खोलने में जुटे हैं. विरोधियों की पोल खोल राजनीति में सबसे अहम भूमिका अदा कर रही है एक पुस्तिका, जिसका नाम है सुशासन के नाम-लूट की छूट है जनता गई टूट है. इस पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर नीतीश सरकार के निवर्तमान मंत्री जमशेद अशरफ की तस्वीर है. इसके वह लेखक हैं. इस पुस्तिका में उस एफिडेविट का कच्चा चिट्ठा खोला गया है, जिसके कारण उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था. जमशेद अशरफ ने लूट का सीधा आरोप मुख्यमंत्री और उनके सचिवालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर लगाया है. यह पुस्तिका हिंदी और उर्दू भाषा में है. चुनाव से पहले विभिन्न क्षेत्रों में इसे खूब बांटा जा रहा है. पिछले दो माह में इसके कई संस्करण छप चुके हैं. आम मतदाता इसे सुशासन का असली रूप समझ कर मजे लेते हुए पढ़ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के सुशासन की बोलती बंद है.

बुरे फंसे प्रेम भाई

गया शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ऐन चुनाव के वक़्त बुरे फंस गए हैं. 1991 में शहर के कोतवाली थाने पर एक व्यक्ति की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन और पथराव करने के मामले में कांड संख्या-303/91 कोतवाली में दर्ज हुआ था. उस समय पुलिस द्वारा विधायक रहने के कारण उन्हें ज़मानत दे दी गई थी, लेकिन इस मामले को हल्के में लेना उन्हें महंगा पड़ गया. नामांकन के बाद स्क्रूटनी के समय प्रेम कुमार जब अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष बैठे थे तो एक निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के वकील ने अचानक प्रेम कुमार के इस मामले में फरार होने का काग़ज़ पेश कर सनसनी फैला दी. इशारा मिलते ही प्रेम कुमार मामले को भांपते हुए तुरंत लघुशंका करने के बहाने चुपके से अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से खिसक लिए और भूमिगत हो गए. इस मामले को लेकर शहर में तरह-तरह की चर्चा है.

तू डाल-डाल, मैं पात-पात

तू डाल-डाल तो मैं पात-पात वाली कहावत का असली रूप देखना हो तो भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र चले आइए. राजनीति ने यहां एक बार फिर दंगाइयों और दंगा पीड़ितों की गोलबंदी का इंतज़ाम कर दिया है. राजद-लोजपा गठबंधन ने यहां से अबू कैसर को अपना उम्मीदवार बनाया है. अबू कैसर भागलपुर के दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं. दंगा पीड़ितों को अबू कैसर के संघर्ष का फायदा भी हुआ. नाथनगर मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है. इससे पहले सुधा श्रीवास्तव यहां की विधायक थीं. कुछ माह पूर्व उनका देहांत हो गया. वह एक नेक महिला थीं. क्षेत्र के लोग उन्हें बहुत चाहते थे. वह एनडीए के साथ रहकर भी समाजवादी विचारधारा से अलग नहीं हो पाई थीं. इस क्षेत्र के लिए जब सुधा जी जैसा कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो नीतीश कुमार ने राजद के अबू कैसर के जवाब में अजय मंडल नामक एक ऐसे व्यक्ति को जदयू का उम्मीदवार बना दिया, जिसके सगे-संबंधी भागलपुर दंगे में आगे-आगे थे. 1989 के दंगे के दौरान इस क्षेत्र के चंपा गांव में कई मुसलमानों की हत्या के आरोप में अजय मंडल के पिता निरपत मंडल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. निरपत मंडल जेल में बंद हैं. नीतीश कुमार नाथनगर सीट किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते, लेकिन क्षेत्र के शांतिप्रिय मतदाता इस सियासी खेल को अच्छी तरह समझते हैं.

बूथ कैप्चरिंग का पंगा

अभी सिर्फ़ तीसरे चरण का चुनाव ख़त्म हुआ है और शुरू हो गया एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने का सिलसिला. राष्ट्रीय जनता दल ने तीसरे चरण के चुनाव में सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पर बूथ कब्ज़े का आरोप लगाया है. राजद महासचिव रामचंद्र राय ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की. विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी यहां से चुनाव लड़ रही हैं. आयोग को भेजे फैक्स में राय ने कहा कि भाजपा समर्थकों ने मतदान अधिकारियों से मिलकर मतदान केंद्र संख्या 16, 22, 23, 24, 25, 53, 55, 56, 56 ए, 57, 57 ए, 136 तथा 137 पर क़ब्ज़ा कर लिया. ग़रीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को मतदान करने से रोका गया. सोनपुर के निर्वाचन अधिकारी से भी इसकी शिकायत की गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. उन्होंने आयोग से उपरोक्त मतदान केंद्रों पर पुन: मतदान की मांग की है.

बड़े बेआबरू होकर...

लोजपा के ज़िलाध्यक्ष अताउल्ला खां के साथ पार्टी ने जो व्यवहार किया गया, उस पर वह यही कह रहे हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले... हुआ यूं कि गया शहर विधानसभा क्षेत्र से पहले लोजपा का टिकट अताउल्ला खां को मिला. उन्होंने नामांकन भी करा डाला, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन लोजपा ने राजू वर्णवाल को अपना प्रत्याशी घोषित कर अताउल्ला खां का टिकट रद्द कर दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बाग़ी बनाम दलीय उम्मीदवार

जहानाबाद

सुनील सौरभ

उग्रवाद के लिए कभी पूरे देश में चर्चित रहा जहानाबाद ज़िला इस बार के विधानसभा चुनाव में बाग़ी प्रत्याशियों के लिए जाना जा रहा है. ज़िले के जहानाबाद, मखदूमपुर और घोसी विधानसभा क्षेत्र में दलीय प्रत्याशियों को अपने ही दल के बाग़ी उम्मीदवारों से संकट बढ़ गया है. जातीय और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर उक्त तीनों विधानसभा क्षेत्रों से जदयू-भाजपा, राजद-लोजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, लेकिन टिकट न पाने वाले नेताओं ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है. यहां हर दल को अपने बाग़ी प्रत्याशियों का सामना करना पड़ रहा है. जहानाबाद से जदयू-भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक अभिराम शर्मा को अपने ही दल के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट मिलने तक यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे. जो लोग जदयू में रहकर जहानाबाद से टिकट के लिए प्रयासरत थे, उन्हें जदयू आलाकमान के फ़ैसले से निराशा हुई और वे अभिराम शर्मा के विरोध में खड़े हो गए हैं.

यह अलग बात है कि विरोध का स्वर मुखर तो नहीं है, लेकिन भितरघात की आशंका बरकरार है. वहीं राजद-लोजपा की ओर से वर्तमान विधायक डॉ. सच्चिदानंद यादव के पुन: प्रत्याशी बनने से इस दल के कई बड़े नेता मायूस हो गए हैं. इनकी परेशानी राजद के बाग़ी प्रत्याशी विजय मंडल ने बढ़ा दी है. विजय पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वह ख़ुद को रोक नहीं सके और बाग़ी प्रत्याशी के रूप नामांकन दाख़िल करके उन्होंने राजद की परेशानी बढ़ा दी. इस तरह की परेशानी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रो. रामजतन सिन्हा कुछ बचे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े नेता दबी ज़ुबान से इनकी आलोचना करते ज़रूर नज़र आ रहे हैं. मखदूमपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद जदयू ने यहां से जीतन राम मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया है. इससे पूर्व मांझी गया ज़िले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. सुरक्षित क्षेत्र होने के बाद जदयू के स्थानीय नेताओं-कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि पार्टी की ओर से उन्हें तरज़ीह मिलेगी, लेकिन अंतिम समय में जीतन राम मांझी को प्रत्याशी बनाए जाने से वे निराश हो गए. हालांकि आलाकमान के फरमान ने उन्हें चुप रहने के लिए बाध्य कर दिया, पर बदले की आग भीतर ही भीतर सुलग रही है.

पिछले उपचुनाव में यहां से जगदीश शर्मा ने नीतीश कुमार के तमाम विरोध के बाद अपनी पत्नी शांति शर्मा को बतौर निर्दलीय खड़ा कर सफलता दिलाई थी. इस बार नीतीश ने जगदीश शर्मा से हाथ मिलाकर राहुल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है. नतीजतन पिछले चुनाव में जदयू से लड़े अजय सिंह टुन्नू इस बार बाग़ी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं.

कांग्रेस ने पूर्व सांसद स्वर्गीय राम स्वरूप राम के बेटे शंकर स्वरूप को अपना प्रत्याशी बनाया है. उन्हें राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड का बताया जाता है. उन्हें अनुसूचित जाति के युवा मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिलने की संभावना है. राजद ने यहां से धर्मराज पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है. यहां से पहले धनंजय पासवान अपनी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वह बाग़ी हो गए. उनकी मदद बसपा के राम गुलाम चौधरी कर रहे हैं. बसपा के जातीय मतों पर उनकी पकड़ मज़बूत बताई जाती है. बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र घोसी में इस बार सांसद जगदीश शर्मा की अग्निपरीक्षा है. यहां से जदयू ने उनके बेटे राहुल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है. पिछले उपचुनाव में यहां से जगदीश शर्मा ने नीतीश कुमार के तमाम विरोध के बाद अपनी पत्नी शांति शर्मा को बतौर निर्दलीय खड़ा कर सफलता दिलाई थी. इस बार नीतीश ने जगदीश शर्मा से हाथ मिलाकर राहुल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है. नतीजतन पिछले चुनाव में जदयू से लड़े अजय सिंह टुन्नू इस बार बाग़ी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं.

लोजपा-राजद ने यहां से कौशल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है. उन्हें राजद-लोजपा के जातीय मत ही मिलने की संभावना है. कांग्रेस ने योगेंद्र प्रसाद सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है. उन्हें बिहार में पार्टी के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान का विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहां जगदीश शर्मा समर्थन बनाम विरोध ही चुनाव का आधार है. इस प्रकार जहानाबाद ज़िले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में जदयू और राजद गठबंधन के प्रत्याशियों को बाग़ी उम्मीदवारों से ख़तरा नज़र आ रहा है. लेकिन मतदान के दिन तक विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपनी ओर कितना मोड़ पाते हैं, चुनाव परिणाम उसी पर निर्भर करेगा. इतना तय है कि यदि चुनाव परिणाम विपरीत गए तो उसे बाग़ी प्रत्याशियों की सफलता माना जाएगा. उधर इलाक़े की जनता चुप्पी साधे सभी प्रत्याशियों की बात सुन रही है.

feedback@chauthiduniya.com

राजू ने बढ़ाई भाजपा-कांग्रेस की परेशानी

गया नगर

भाजपा का गढ़ माना जाने वाला गया नगर विधानसभा क्षेत्र पिछले 20 सालों से भाजपा के डॉ. प्रेम कुमार के क़ब्ज़े में है, लेकिन परिसीमन में भाजपा मतदाताओं का एक प्रमुख हिस्सा पटवा टोली और लखीबाग नवसृजित वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में चले जाने से उनकी परेशानी बढ़ गई है. राजकुमार प्रसाद उर्फ़ राजू वर्णवाल और कांग्रेस से गया नगर निगम के डिप्टी मेयर ओंकार नाथ के आने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है. ग़ौरतलब है कि दोनों के जातीय मतों को भाजपा का वोटबैंक कहा जाता है. दो दशक से गया शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ. प्रेम कुमार के प्रति लोगों में पानी और बिजली की समस्या को लेकर नाराज़गी है. उनके लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री रहते हुए भी गया शहर के लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ी. इस बार उनकी राह में बाधा पहुंचाने के लिए वैश्य समुदाय से आने वाले राजद-लोजपा प्रत्याशी राजू वर्णवाल एवं कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव मज़बूती के साथ लगे हैं.

भाकपा के प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद ज़लालुद्दीन अंसारी, बसपा के मनोरंजन पाठक, सपा के शैलेंद्र यादव एवं बजरंग दल के प्रदेश संयोजक सुरेंद्र सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं. ज़लालुद्दीन अंसारी राज्यसभा सदस्य रहते हुए अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं. गया नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की धुरी कुल मिलाकर भाजपा, भाकपा, लोजपा और कांग्रेस के बीच घूम रही है. मतदाता किसे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देते हैं, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, फ़िलहाल सभी दल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं. लोजपा प्रत्याशी राजू वर्णवाल का कहना है कि लोजपा-राजद गठबंधन के जातीय मतों के अलावा वैश्य समाज एवं मुस्लिमों समेत क्षेत्र के अधिकांश मत उन्हें ही मिलेंगे. शहर के लोग इस बार बदलाव की चाहत रखते हैं. भाजपा नेता जय नारायण केसरी बाग़ी होकर लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. उनका दावा है कि बदलाव की लहर का लाभ राजू वर्णवाल को मिलेगा. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को पार्टी के परंपरागत वोटों के अलावा जातीय मतों और लोगों में कांग्रेस के प्रति झुकाव का लाभ भी मिलेगा. जलालुद्दीन अंसारी अपनी साफ़ छवि और विकास कार्यों के सहारे मतदाताओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं. गया शहर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हिंदू मतों को पाने में उनकी पार्टी आड़े आ रही है. यहां यदि वोटों का बंटवारा हो गया तो प्रेम कुमार की परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन यदि भाजपा अपनी बात रखने में सफल हो गई तो मतदाताओं का रुख़ बदल सकता है. इस बार सभी प्रत्याशी भाजपा के इसी हथकंडे को नाकाम करने के लिए कमर कसे हुए हैं.

शहर के लोग इस बार बदलाव की चाहत रखते हैं. भाजपा नेता जय नारायण केसरी बाग़ी होकर लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. उनका दावा है कि बदलाव की लहर का लाभ राजू वर्णवाल को मिलेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महिला उम्मीदवारों की ललकार

नवादा

भाजपा-जदयू के जातीय समीकरण में लोजपा प्रत्याशी की सेंधमारी की आशंका ने भाजपा प्रत्याशी को संकट में डाल दिया है.

नवादा ज़िले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न दलों से आईं आधा दर्जन से अधिक महिला प्रत्याशियों ने चुनावी जंग को रोचक बना दिया है. ज़िले के नवादा, रजौली, हिसुआ, वारिसअलीगंज और गोविंदपुर आदि क्षेत्र कभी कांग्रेस के गढ़ के रूप में जाने जाते थे, लेकिन पिछले दो दशकों से बिहार में उसकी स्थिति ख़राब हो गई. इस बार कांग्रेस ने पुन: अपने बलबूते ज़िले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारे हैं. इससे अन्य दलों की परेशानी बढ़ गई है. महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने तीन विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है. नवादा विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने पिछले चुनाव में निर्दलीय रूप से लड़कर विधायक बनी पूर्णिमा यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है. राजद-लोजपा गठबंधन की ओर से पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस ने निवेदिता सिंह को मैदान में उतारा है. विगत दो दशकों के दौरान कई उतार-चढ़ाव देख चुके नवादा विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं, बल्कि व्यक्ति ही चुनाव में महत्वपूर्ण रहा है. इस बार भी सुशासन के पांच वर्षों में समुचित विकास से वंचित रहे नवादा के मतदाता चुप्पी साधे हैं. हालांकि इन तीनों दलों की हार-जीत में माले और बसपा प्रत्याशियों द्वारा काटे गए वोटों की अहम भूमिका रहेगी.

सबसे मज़ेदार चुनाव हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में है. यहां पूर्व मंत्री आदित्य सिंह की दो बहुएं आमने-सामने हैं. छोटी बहू नीतू सिंह कांग्रेस की ओर से मैदान में हैं तो दूसरी ओर बड़ी बहू आभा सिंह बाग़ी होकर विरोध में खड़ी हैं. भाजपा ने यहां से अपने विधायक अनिल सिंह को दोबारा टिकट दिया है, लेकिन उनकी परेशानी लोजपा से आए अनिल मेहता ने बढ़ा दी है. भाजपा-जदयू के जातीय समीकरण में लोजपा प्रत्याशी की सेंधमारी की आशंका ने भाजपा प्रत्याशी को संकट में डाल दिया है. रजौली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक बनवारी राम को पार्टी ने इस बार बेटिकट कर कन्हैया रजवार को प्रत्याशी बनाया है. बनवारी राम ने राज्यसभा के चुनाव में पार्टी के ख़िलाफ़ क्रास वोटिंग की थी. कांग्रेस ने यहां से ज़िला पार्षद बसंती देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है. बसंती देवी नवादा के एक पूर्व ज़िलाधिकारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाकर चर्चित रह चुकी हैं. उधर राजद-लोजपा गठबंधन ने प्रकाशवीर को अपना प्रत्याशी बनाकर लालटेन की रोशनी बढ़ाने की कोशिश की है. सबकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए माले की सुदामा देवी ने कमर कस ली है. गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक कौशल यादव इस बार जदयू के प्रत्याशी हैं. जदयू ने नवादा और गोविंदपुर से कभी राजद का टिकट न मिलने पर निर्दलीय रूप से लड़े पति-पत्नी कौशल यादव और पूर्णिमा यादव को टिकट तो दे दिया है, लेकिन इनके कारनामे इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं. गोविंदपुर के पूर्व विधायक एवं मंत्री प्रो. के बी प्रसाद के राजद-लोजपा गठबंधन से उम्मीदवार बन जाने से कौशल की परेशानी बढ़ गई है.

कांग्रेस ने यहां से असद उल्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है. हालांकि नया चेहरा होने के कारण उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है. वारिसअलीगंज विधानसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक अरुणा देवी को उतारा है. अपने बाहुबली पति अखिलेश सिंह की बदौलत निर्दलीय विधायक रह चुकी अरुणा देवी को इस बार लाभ मिलने की संभावना है. जदयू ने भी यहां से निर्दलीय विधायक प्रदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया है. इन दोनों के बीच लोजपा प्रत्याशी अंजनी कुमार सिंह राजद-लोजपा गठबंधन के जातीय समीकरण के मतों को अपने पक्ष में मज़बूती के साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं. विकास के इस दौर में भी पिछड़ेपन का पर्याय बने नवादा जिले का यह दुर्भाग्य रहा है कि अब तक के जनप्रतिनिधि सिर्फ़ उसके पिछड़ेपन और जातीय भावनाओं को भुनाकर वोट हासिल करते रहे, लेकिन इस बार मतदाताओं का मिजाज़ कुछ अलग तरह के संकेत दे रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

दलीय प्रत्याशियों की नींद हराम

मतदाताओं के रुझान और गठबंधन के दलीय- जातीय मतों के भरोसे सफलता की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनकी राह में रोड़े अटकाने के लिए लगभग आधा दर्जन बाग़ी प्रत्याशी मैदान में हैं.

वजीरगंज

गया ज़िले के नवसृजित विधानसभा क्षेत्र वजीरगंज में बाग़ी प्रत्याशियों ने दलीय प्रत्याशियों की नींद हराम कर दी है. यदि बाग़ी अपनी उम्मीद के अनुरूप मत पा गए तो इस क्षेत्र में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है. बाग़ी प्रत्याशियों से सबसे अधिक परेशानी राजग के भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को हो रही है. वह मतदाताओं के रुझान और गठबंधन के दलीय-जातीय मतों के भरोसे सफलता की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनकी राह में रोड़े अटकाने के लिए लगभग आधा दर्जन बाग़ी प्रत्याशी मैदान में हैं. जदयू के बाग़ी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के क़रीबी माने जाने वाले गांधीवादी रवींद्र प्रताप इस चुनाव में बतौर निर्दलीय राजग प्रत्याशी को शिकस्त देने की फ़िराक़ में हैं. वहीं पूर्व विधायक और शरद यादव के नज़दीकी रहे डॉ. विनोद कुमार यादवेंदु एवं जदयू किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश कुमार वर्मा भी प्रदेश नेतृत्व की उपेक्षा से बाग़ी होकर निर्दलीय रूप से मैदान में हैं. वजीरगंज मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सी पी ठाकुर की पहल पर कुछ महीने पूर्व भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले पारस नाथ सिंह भी बग़ावत कर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में कूद पड़े हैं.

उधर प्रो. रामनंदन सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं. जदयू के युवा नेता सैयद शारिम अली भी बतौर निर्दलीय राजग गठबंधन के प्रत्याशी को झटका देने के प्रयास में हैं. चुनाव परिणाम चाहे जो हो, लेकिन बाग़ी प्रत्याशियों ने जदयू और भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को एक चुनौती ज़रूर दे दी है. राजद ने राजेश कुमार, कांग्रेस ने विधायक अवधेश सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

KISHANGANJ COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Bahadurganj Road, Veriadangi (Near Kishanganj Block) Kishangaj-855107
(A unit of Millia Educational Trust, Purnea)
Approved by AICTE, New Delhi Vide letter no. NRO 2010-11/1-16433411 Dated 08th September 2010 Affiliated to B.N. Mandal University, Madhepura

DIRECT ADMISSION NOTICE - 2010-11
प्रथम वर्ष बी.टेक. 2010 (4 Years Engineering Degree Course) में सीधे नामांकन हेतु महाविद्यालय से सम्पर्क करें।

Branches
- Mechanical Engineering
- Electronics & Communication Engineering
- Computer Science & Engineering
- Electrical Engineering
- Civil Engineering

Eligibility: Candidate must have passed 10+2 with mathmetics (PCM/PCMB)

Special Features: Well experience & qualified faculties, Well equipped lab, Workshop & Computer Centre with high speed Broad Band internet Connectivity

50% seats from management quota & 50% BCECE (Patna) Quota

FEE STRUCTURE

Branch	Per Annum	At the time of Admission	At the time of Form Filling
CSE & ECE	45,000/-	25,000/-	20,000/-
ME,EE&CE	55,000/-	30,000/-	25,000/-

Admission & application Form can be obtained from the office of KCET. Kishanganj on payment of Rs. 500/- in cash or Rs, 550/- DD in favour of KCET, Kishanganj payable at Kishangaj. Last date of admission : 30.11.2010 The classes will be started from 01.12.2010

MILLIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Rambagh, Purnea-854301
(A unit of Millia Educational Trust, Purnea)
(Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to B.N. Mandal University, Madhepura)

Application are invited for admission in Ist year B.Tech. 2010 for few vacant seats against BCECE (Patna) quota in ME-08, EE-10, ECE-09, CS-38,

ELIGIBILITY
Candidates must have passed 10+2 with maths. Application form is available. Date of Entrance Test : 31.11.2010, Direct Admission in 2nd year B.Tech. through lateral entry 2010 (Attach with session 2009-10)

ELIGIBILITY
Candidates must have passed in diploma Engg. in above respective branch or B.Sc. (Math Hons) with 60% marks

Helpline. : 9431087906, 9431088043, 9334527151, 06456-222171, 222172 (KCET), 06454-240433-34 (MIT)

Dr. A. Imam, Director, MET

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 08 नवंबर–14 नवंबर 2010

बिहार के सियासी समाज में राजनेताओं के बेटे-बेटियों के बीच ऐसी टक्कर कोई नई बात नहीं.

बाप नेता बच्चे अभिनेता

बिहार के सियासी समाज के बीच एक नई प्रथा चली है. कई दिग्गज नेता अपने बेटे-बेटियों को बॉलीवुड में भेज रहे हैं या यूं कहें कि बच्चे ही अपने पिता की राजनीतिक दुनिया से दूर रहना और रुपहले पर्दे के हीरो-हीरोइन बनना चाहते हैं. बिहार के कई दिग्गज नेताओं के बच्चे बॉलीवुड की ओर रुख़ कर चुके हैं.

कुमार सुशांत

हाल में सलमान ख़ान और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म दबंग ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि आमिर ख़ान की फिल्म थ्री इडियट्स भी पीछे छूट गई. फिल्म में सोनाक्षी के अभिनय को इस क़दर सराहा गया कि अरबाज़ ख़ान ने सोनाक्षी को लेकर इसका सीक्वल बनाने की ठान ली. सोनाक्षी बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं. शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की इस सफलता से काफ़ी गदगद हुए. उधर पूर्व रेल मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी फिल्मों की ओर अपने क़दम बढ़ा दिए हैं. अपने बेटे की इस उपलब्धि से रामविलास पासवान ख़ासे उत्साहित हैं और होना भी चाहिए. दरअसल, बिहार में इन दिनों ऐसी हवा चली है कि दिग्गज राजनीतिज्ञों के बेटे-बेटियां पिता की सियासी दुनिया को छोड़कर फिल्मी दुनिया में अपना करियर बना रहे हैं. केवल सोनाक्षी सिन्हा और चिराग पासवान ही नहीं, बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जो पिता की राजनीतिक राह से दूर बॉलीवुड में क़दम रख चुके हैं. शेखर सुमन को दुनिया फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में काम करने वाले एक कलाकार के रूप में जानती थी, लेकिन शेखर सुमन का राजनीतिक चेहरा तब उभर कर सामने आया, जब 2009 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के मुक़ाबले कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे डाला. शेखर सुमन ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीत गए. दोनों नेताओं के बीच जीत-हार का सिलसिला यही ख़त्म नहीं हुआ. इस चुनाव के बाद दोनों के बच्चों के बीच जंग छिड़ गई. जहां शेखर के बेटे अध्ययन सुमन ने तीन फिल्मों जश्न, राज़ और हाल-ए-दिल में अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग में दमदार अभिनय करके विरोधियों को जवाब देते हुए अपने पिता की प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी की.

हाल में बिहार में नेहा शर्मा भी काफ़ी चर्चा में रहीं. नेहा ने फिल्म क्रूक्स में इमरान हाशमी की हीरोइन बनकर यह साबित कर दिया कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है. सबसे रोचक बात यह है कि नेहा के पिता अजीत शर्मा इस बार भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. अजीत शर्मा यूं तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, पैसों के मामले में धनी भी हैं. वह कई बार कांग्रेस की टिकट पर बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए. 2009 में जब कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया तो उन्होंने मायावती यानी बसपा का दामन थाम लिया. एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर यक़ीन किया है. बिहार के सियासी समाज में राजनेताओं के बेटे-बेटियों के बीच इस तरह की टक्कर कोई नई बात नहीं है. पूर्व रेलमंत्री रामविलास पासवान यूपीए गठबंधन से नाता तोड़ने के बाद केंद्रीय स्तर पर भले ही फ्लॉप चल रहे हों, लेकिन बिहार में उनकी लोकप्रियता कम नहीं है. इसी का नतीजा है कि कांग्रेस को केंद्रीय स्तर पर लोजपा से नाता तोड़ने पर अफसोस भले ही न होता हो, पर उसे बिहार के चुनाव में राजद या लोजपा जैसी पार्टी का सहारा लेना ही पड़ता है. मजे की बात तो यह है कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान फिल्म वन एंड ऑनली के हीरो बन गए हैं. तनवीर ख़ान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में चिराग के साथ कंगना रानावत नज़र आएंगी. दूसरी ओर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव क्रिकेट में अपनी क़िस्मत आज़मा रहे हैं.

इतना ही नहीं, प्रकाश झा को बिहार के लोग राजनीतिक शख्सियत के रूप में भी जानते हैं. उन्होंने अपनी पहुंच के दम पर 2004 में चंपारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. फिर 2009 के संसदीय चुनाव में वह पश्चिमी चंपारण से मैदान में उतरे, मगर इस बार भी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया. प्रकाश झा अभी भी राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर उनकी 18 वर्षीय बेटी दिशा झा गायिका बनने की तैयारी कर रही हैं. बॉलीवुड और राजनीति में प्रकाश झा के कद को देखते हुए यही लगता है कि दिशा के लिए गायिका बनने की राह ज़्यादा मुश्किल नहीं है. बिहार में राजनेता अपने विरोधियों को मात देने की जुगत में रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे कांटे भरी राजनीतिक राह से अलग हटकर प्रसिद्धि हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. यह बात अलग है कि उनकी राह को आसान बनाने में उनके पिता की पहुंच और पैसे की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. जो भी हो, बिहार के लिए तो यह एक अच्छा संकेत है.

kumarsushant@chauthiduniya.com

करगहर : कौन बनेगा पहला विधायक?

नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए करगहर में चर्चा है कि यहां का पहला विधायक कौन बनेगा? यहां से खम ठोक रहे जदयू के रामधनी सिंह, लोजपा के शंकर कुशवाहा, कांग्रेस के आलोक सिंह, कांग्रेस (जे) के रमेश तिवारी उर्फ़ टाइगर एवं अपना दल के मनोज कुमार मतदाताओं के बीच अपनी बात रख रहे हैं. ज़िले में एक तरफ़ विक्रमगंज विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हुआ तो वहीं नए परिसीमन के चलते करगहर विधानसभा क्षेत्र का उदय हुआ. पूर्व में चेनारी, दिनारा एवं कैमूर के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में बंटे इस प्रखंड को विधानसभा मुख्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ तो पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों के बीच जातीय जोड़-तोड़ शुरू हो गई. कुर्मी बहुल इस विधानसभा क्षेत्र में यादव, ब्राह्मण, राजपूत एवं कुशवाहा मतों का महत्व बढ़ा है. जबकि रविदास पासवान, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़े मतों की बदौलत अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं. जदयू ने दिनारा के पूर्व विधायक एवं वर्तमान विधान पार्षद रामधनी सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जो काफ़ी उम्रदराज एवं अनुभवी हैं. बसपा ने ज़िला पार्षद जग नारायण पटेल को उम्मीदवार बनाया है.

शंकर कुशवाहा

रमेश तिवारी

रामधनी सिंह

जगजीवन राम की पोती मेधावी कीर्ति की पार्टी कांग्रेस (जे) से बाहुबली रमेश तिवारी उर्फ़ टाइगर उम्मीदवार हैं. लोजपा ने शंकर कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस ने यहां आलोक सिंह को मैदान में उतारा है. इस विधानसभा क्षेत्र में पुरा करगहर, पुरा कोचस एवं शिवसागर आदि तीन प्रखंड शामिल हैं. लगभग ढाई लाख मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में कोचस प्रखंड में 94899, करगहर प्रखंड में 1,24,278 एवं शिवसागर प्रखंड में 31,610 मतदाता हैं. इस क्षेत्र में करगहर प्रखंड की 21 पंचायतें, कोचस प्रखंड की 16 एवं शिवसागर प्रखंड की 5 पंचायतें शामिल हैं. कोचस में 104, करगहर में 149 एवं शिवसागर में 40 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. हर दल चाहता है कि करगहर में पहला विधायक उसी का हो. जातीय गणित के आधार पर सभी ख़ुद को भारी बता रहे हैं. कोई कुर्मी मतदाताओं को अपनी जागीर समझ रहा है तो कोई यादव, पासवान, कुशवाहा एवं अल्पसंख्यकों को अपना बता रहा है. कुछ प्रत्याशी स्वजातीय मतों के भरोसे अपनी जीत पक्की बता रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com